आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। बिना किसी किंतु-परंतु के इसे पोषित करने वाली ताकतों पर काबू पाना होगा। -नरेंद्र मोदी

विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1990 से 2019 के बीच स्ट्रोक की घटनाओं में 70 फीसदी और इससे होने वाली मौतों में 43 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो वाकई चिंताजनक है। इससे बचने के लिए बेहद जरूरी है कि लोग स्वस्थ जीवनशैली को अपनाएं और नियमित स्वास्थ्य जांचें भी कराएं।

बचें और बचाएं

आज हम आधुनिक जीवनशैली और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्रोक के बढ़ते मामलों ने भारत समेत पूरी दुनिया में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1990 से 2019 के बीच स्ट्रोक की घटनाओं में 70 फीसदी और इससे होने वाली मौतों में 43 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो वाकई चिंताजनक है। वैसे तो रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में स्ट्रोक के अधिक मामले बेहद निर्धन देशों में आते हैं, लेकिन भारत में भी यह समस्या कोई कम गंभीर नहीं है, जहां हर चार में से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में स्ट्रोक का खतरा होता है। उल्लेखनीय है कि स्ट्रोक मुख्य रूप से तब होता है जब मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे मस्तिष्क का कार्य संचालन प्रभावित होने लगता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, धूम्रपान और शराब के अत्यधिक सेवन और असंतुलित जीवनशैली इसकी प्रमुख वजहें हैं। दुर्भाग्यवश, शहरीकरण और तकनीकी प्रगति ने लोगों की दिनचर्या को इतना बदल दिया है कि शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं, तिस पर अस्वास्थकर खानपान ने स्ट्रोक के जोखिम को और बढ़ा दिया है। मानवीय गतिविधियों के चलते जिस तरह धरती का तापमान बढ़ रहा है, उससे स्ट्रोक से होने वाली मौतों में गर्मी की भूमिका 1990 के बाद से करीब 72 फीसदी बढ़ गई है और चिंता की बात है कि भविष्य में यह खतरा और तेजी से बढ़ने की आशंका है। बड़ी चिंता की बात यह भी है कि स्ट्रोक अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, युवा आबादी में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्ट्रोक के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख चुनौती स्ट्रोक के मरीज को 'गोल्डन आवर' के भीतर इलाज मुहैया कराने की होती है, लेकिन निम्न आय वाले देशों के दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाता। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 17 वर्षों में स्ट्रोक का खतरा 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है। ऐसे में, स्ट्रोक के बचाव व प्रबंधन के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना तो जरूरी है ही, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लेकर लोग जागरूक बनें। स्ट्रोक के बढ़ते मामलों को रोकना सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि हम स्ट्रोक के खतरों को समझें, इससे बचने के उपाय अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें।

आतंकवाद की परछाई

'खालिस्तान' ब्रितानी षड्यंत्र का सह-उत्पाद है। स्वतंत्रता के बाद मृत 'खालिस्तान' विचार को कांग्रेस ने 1977-78 में अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता हथियाने की लालसा में पुनर्जीवित किया, जिसका खुलासा पूर्व आईपीएस गुरबख्श सिंह सिद्धू ने अपनी पुस्तक 'द खालिस्तान कांस्पीरेसी' में किया है।

बलबीर पुंज
भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

गत दिनों अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें वह पुलिस सतर्कता से बाल-बाल बच गए। उन पर गोली तब चलाई गई, जब वह 2007-17 के बीच अपनी सरकार के दौरान हुई 'गलतियों' के लिए 'तनखैया' घोषित किए जाने के बाद अकाल तख्त की 'सजा' पर स्वर्ण मंदिर में सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। 68 वर्षीय हमलावर नारायण सिंह चौड़ा घोषित खालिस्तान समर्थक है और उस पर 20 से अधिक आपराधिक मामले हैं।

अकाली दल दावा करता है कि वह पंथिक संगठन है और सिखों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं हमलावर चौड़ा, जोकि पाकिस्तान भी जा चुका है-सुखबीर को पंथ का 'गद्दार' मानता है। इस जघन्य कांड के मूल में एक विशेष मानसिकता है। कौन सिख है, कौन नहीं और कौन सच्चा सिख है, कौन 'गद्दार'-आखिर इसका निर्णय कौन और कैसे करेगा?

बादल पर हमले के केंद्र में 150 वर्ष पुराना 'खालिस्तानी नैरेटिव' है। ब्रितानी 1857 विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 'बांटो-राज करो' की विभाजनकारी नीति अपनाई। इसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय समाज की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर उस पर बौद्धिक-शैक्षणिक काम किया। इसमें हिंदू-मुस्लिम विवाद सबसे सरल रहा, क्योंकि तब दोनों समुदायों में 600 वर्षों का शत्रुभाव था। यही कारण है कि मुस्लिमों में अलगाव पैदा हेतु अंग्रेजों को सैयद अहमद खां आसानी से मिल भी गए, जिनके 'दो राष्ट्र सिद्धांत' ने इसलाम के नाम पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को जन्म दे दिया।

अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन हिंदू-सिख संबंधों में कड़वाहट घोलना था-क्योंकि 15वीं शताब्दी में सिख पंथ के जन्म से ही देश का प्रत्येक हिंदू, सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखता था और प्रत्येक सिख अपनी गुरु परंपरा के अनुरूप स्वयं को धर्मरक्षक मानता था। तब अंग्रेजों ने आयरलैंड में जन्मे अपने एक अधिकारी मैक्स आर्थर मैकॉलीफ को चुना, जिसने स्वयं के सिख पंथ अपनाने का दावा किया। मैकॉलीफ का एजेंडा, सिखों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह को भी रोकना था। इसलिए उसने भाई काहन सिंह नाभा की सहायता से 'श्री गुरुग्रंथ साहिब' का अंग्रेजी में विकृत अनुवाद किया और छह खंडों में 'द सिख रिलीजन-इट्स गुरु, स्केयर्ड स्क्रीप्टस और ऑथर' पुस्तक की रचना की। फिर नाभा ने मैकॉलीफ से प्रेरणा लेकर 1897-98 में 'हम हिंदू नहीं' नाम से प्रकाशन निकाला। 'खालिस्तान' ब्रितानी षडयंत्र का सह-उत्पाद है, जिसे सिख पंथ का एक वर्ग आत्मसात करके अपनी मूल जड़ों से कट गया है। स्वतंत्रता के बाद मृत 'खालिस्तान' विचार को कांग्रेस ने 1977-78 में अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता हथियाने की लालसा में पुनर्जीवित किया। इसका उल्लेख गैर-राजनीतिक, पूर्व आईपीएस अधिकारी और भारतीय खुफिया एजेंसी 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (रॉ) में वर्षों जुड़े रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए गुरबख्श सिंह सिद्धू ने अपनी पुस्तक 'द खालिस्तान कांस्पीरेसी' में किया है। उनका खुलासा इसलिए भी महत्व रखता है, क्योंकि वह कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत सरदार स्वर्ण सिंह के दामाद भी हैं।

अपनी पुस्तक में गुरबख्श लिखते हैं, 'वर्ष 1977 के पंजाब (विधानसभा) चुनाव में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल-जनता पार्टी गठबंधन से कांग्रेस हार गई थी। इसके तुरंत बाद, मुझे पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी द्वारा जरनैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन से अकाली दल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों की जानकारी मिली...।' बकौल सिद्धू, 'ज्ञानी जैल सिंह ने संजय गांधी को सलाह दी कि पंजाब में अकाली दल-जनता पार्टी गठबंधन सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, यदि उनकी उदारवादी नीतियों पर...एक उपयुक्त सिख संत द्वारा लगातार हमला किया जाए।' इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को चुना और उसे 'संत' कहकर संबोधित किया। इसी विभाजनकारी राजनीति का परिणाम रहा कि भिंडरांवाले ने श्री हरिमंदिर साहिब को अपना अड्डा बना लिया। चूंकि खालिस्तान की प्रकल्पना विदेशी है और इसे अधिकांश भारतीय सिखों का समर्थन नहीं मिलता, इसलिए तब भिंडरावाले के निर्देश पर मासूम हिंदुओं के साथ देशभक्त सिखों को भी चिह्नित करके मौत के घाट उतारा जाने लगा। सैन्य अभियान 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख सुरक्षाकर्मियों ने नृशंस हत्या कर दी। इसके तत्काल बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में कांग्रेस समर्थित असामाजिक तत्वों ने हजारों निरपराध सिखों का नरसंहार किया, जिसे न्यायोचित ठहराते हुए राजीव गांधी ने कहा था, 'जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती थोड़ी हिलती है।'

वास्तव में, सुखबीर बादल को 'पंथ का गद्दार' मानना उसी विदेशी असहिष्णु चिंतन से प्रेरित है, जिसमें केवल 'मैं सच्चा, शेष झूठे' मानने की अवधारणा है। इसी विचारगर्भ से पाकिस्तान जन्मा, जिसकी बुनियाद ही बहुलतावादी, समरस और सह-अस्तित्व आधारित भारतीय जीवनशैली का विरोध है। यही चिंतन उसे भीतर से झुलसा भी रहा है। सदियों से जारी शिया-सुन्नी संघर्ष की लपटें बीते दिनों पाकिस्तान के खैबरपख्तूनख्वा प्रांत स्थित कुर्रम तक जा पहुंचीं, जहां 22 नवंबर से शुरू हुई हिंसा में अपने सहबंधुओं के हाथों 130 से अधिक मुस्लिमों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2001 से 2018 के बीच मजहबी घटनाओं में 4,847 शियाओं की सुन्नी कट्टरपंथी हत्या कर चुके हैं। पाकिस्तान घोषित इसलामी राष्ट्र है। फिर भी उसका 'तहरीक-ए-तालिबान' नामक आतंकी संगठन सैकड़ों हमले करके हजारों पाकिस्तानी नागरिकों-सैनिकों को इसलिए मौत के घाट उतार रहा है, क्योंकि वे उनके मुताबिक खालिस सरीयत प्रेरित व्यवस्था को नहीं अपना रहे हैं। यही स्थिति अफगानिस्तान में तालिबान और आईएस-खुरासन के बीच भी है, जो इसलाम के प्रति वफादार होते हुए भी एक-दूसरे का विरोध करते हैं।

पाकिस्तान और कनाडा कथित 'खालिस्तान' आंदोलन के सबसे बड़े पोषक बने हुए हैं। भारत और विशेषकर पंजाब की भलाई इसी में है कि वे सिख गुरुओं के तप, त्याग, परिश्रम और आपसी-भाईचारे के मार्ग पर चलें। अकाल तख्त द्वारा एक पूर्व उपमुख्यमंत्री को 'सजा' देने पर सवाल उठता है कि जनमत से चुनी हुई सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए-मतदाता और विधायिका के या फिर किसी मजहबी संस्था के?

edit@amarujala.com

जीवन धारा

रामवृक्ष बेनीपुरी

जीव-जंतु के जीवन में भी हास्य होगा, पेड़-पौधों के रेशों में भी गुदगुदी दौड़ती होगी, मानता हूं। लेकिन ठहाके लगाकर छतें हिला देना या खिलखिलाहट से सारे कमरे को फूलों की सुवास से भर देना, यह मनुष्य ही कर सकता है।

हंसी से दिल जीतने का वरदान मनुष्य के ही पास

मानव-वंश की विशेषताओं में हंसी की भी गिनती होती है। सभी प्राणियों में मनुष्य ही हंसता है, ऐसा लोगों का विश्वास रहा है। यद्यपि इस धारणा का खंडन जगदीशचंद्र बसु के प्रयोगों ने कर दिया है और अब माना जाने लगा है कि जीव-जंतु की क्या बात, पेड़-पौधे भी हंसते हैं। किंतु तो भी मनुष्य की हंसी, उसकी अन्य कई विशेष खूबियों की तरह, कुछ और ही है। उच्च अट्टहास से लेकर मधुर-मुस्कान तक, हास्य की एक ऐसी सरणी उसके जीवन से जुड़ी है कि जब-जब उसकी कल्पना कीजिए, विस्मय विमुग्ध हो जाना पड़ता है। जीव-जंतु के जीवन में भी हास्य की धारा प्रवाहित होती होगी, पेड़-पौधों के रेशों में भी गुदगुदी दौड़ती होगी, मानता हूं। किंतु भी जोरों का ठहाका लगाकर छतों को हिला देना, कभी खिलखिलाहट से सारे कमरे को फूलों की सुवास से भर देना और कभी हल्की मुस्कराहट से किसी के दिल को जीत लेना, यह वरदान तो मनुष्य को ही मिला है। और, यह वरदान है तो हम मानवों में, जिनमें से कुछ लोगों पर इसकी अजस्र वर्षा की गई, उनमें स्वर्गीय पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का नाम पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। जैसी उन्मुक्त हंसी मैंने चतुर्वेदीजी में पाई थी, वैसी हंसी अन्यत्र नहीं मिली। चतुर्वेदीजी को उनके जीवन में 'हास्यरसावतार' की उपाधि हिंदी-संसार ने सर्वसम्मति से दे रखी थी। वह जहां भी रहते, हंसी की फुलझड़ियां छूटती रहतीं। जिस साहित्य-गोष्ठी में वह पहुंच जाते, वहां का सारा वातावरण ही हास्य-रस से ओतप्रोत हो जाता। जहां चतुर्वेदीजी हों, वहां मनुहसित रह नहीं सकती थी। प्रकृति ने उन्हें ऐसा रूप दिया था, जिस पर हंसी वैसी ही खिलती थी, जैसी कुमुद-वन में शरद की शुभ्र चांदनी खिलती है। गोरा-चिट्टा चेहरा, सजे-संवरे बाल, सिर पर कलगीदार मुरेठा, पतली भवों के नीचे हंसती हुई आंखें, उन पर सुनहले प्रेम का चश्मा, काली मूंछें, चमकीले दांत, छोटी तुड़ाई, मैंने 1918 में, जबकि वह बिहार-प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व कर रहे थे, उन्हें इस रूप में देखा था। सभापति को गंभीर होना चाहिए, यह धारणा तो आज तक बनी हुई है, किंतु जब चतुर्वेदीजी अगणित मालाओं से लदे अपना सभापति का भाषण सुनाने के लिए उठे, और, एक मंद मुस्कराहट से, सोनपुर मेले में उठाउस भरे विशाल हॉल में दर्शकों की ओर देखा, तो ऐसा लगा कि सबके हृदय को वह तार छू गया, जो आनंद की लहर दौड़ा देता है और जब उन्होंने भाषण शुरू किया, तो भाव-विमुग्ध ही न रहे, बल्कि बीच-बीच में सभा-भवन अट्टहास से गुंजित होता रहा। एक दिन उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों बेटों को बड़े प्रेम से खिला रही थीं और वह तालियां बजाकर गा रहे थे- 'कल्लू मल्लू दोनों भाई, बैठे प्रेम से खाते हैं। बैठी माता खिला रही है, खड़े पिताजी गाते हैं।' चतुर्वेदीजी और लोगों को प्रफुल्लित करने के उनके अनेक किस्से हैं। कहने का मतलब यह है, हमारे पूर्वजों की वह उन्मुक्त हंसी और जिंदाखिली हमारे जीवन में उतरे और हमारे अनुवर्ती उनका अनुसरण करें, यही हमारी कामना है।

चेहरे पर लाएं मुस्कान

सूत्र

मौजूदा दौर में इन्सान के जीवन में इतनी भागदौड़ है कि वह अपनी अलग ही धुन में भागा चला जा रहा है। काम का बोझ है, गृहस्थी के कलेश हैं, किसी को शरीर का कष्ट है, तो कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में हम यदि किसी के चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कान ला दें, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं।

दूसरा पहलू

दुनिया के देशों का 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, जबकि कोपेनहेगन शहर अपने साल इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा।

दुनिया की पहली कार्बन मुक्त राजधानी

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया की पहली 'कार्बन न्यूट्रल' राजधानी बनने जा रही है। अन्य राजधानियों ने जहां 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, वहीं कोपेनहेगन 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले डेढ़ दशक से जुटा है। वर्ष 2009 में यहां नई जलवायु योजना लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 2025 तक दुनिया का पहला कार्बन मुक्त राजधानी-महानगर बनाना है।

कोपेनहेगन एक कार्बन तटस्थ शहर के रूप में वैश्विक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा आपूर्ति को टिकाऊ स्रोतों में बदलने, इमारतों में हरित प्रौद्योगिकी के समावेशन, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और परिवहन एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे इस शहर की जलवायु परिवर्तन से मुकाबले और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में इसकी पूर्ण भागीदारी हो। गौरतलब है कि कोपेनहेगन का जिला हॉर्टेग नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिला हीटिंग प्रणाली है, जो इस शहर की 98 प्रतिशत इमारतों को गर्म करने का काम करता है। इस प्रणाली को चलाने के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त कर बायोमास (जैव ईंधन) का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ वहां की इमारतों को ठंडा करने के लिए बंदरगाह से पानी लिया जाता है, जिसके लिए व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 100 पवन टर्बाइन, हजारों वर्ग मीटर के सौर पैनल और जैविक अपशिष्टों का बायोगैसीकरण, जैसे कदम इस लक्ष्य को साकार कर रहे हैं। वहीं, कोपेनहेगन ने 2025 तक 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा है। कोपेनहेगन में पवन और भूतापीय ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी विशेष जोर है। यही नहीं, वहां 75 प्रतिशत यात्राएं पैदल या सार्वजनिक परिवहन द्वारा की जाती हैं। वहां 2025 तक शहर की अधिकांश कारें बिजली, हाइड्रोजन या जैव ईंधन पर चलेंगी। इस शहर को साइकिल से घूमने के अनुकूल भी बनाया गया है, जिससे अधिकांश लोग साइकिल को यात्रा को प्राथमिकता देते हैं।

2025 तक कोपेनहेगन की अधिकांश कारें बिजली, हाइड्रोजन या जैव ईंधन पर चलेंगी। इस शहर को साइकिल से घूमने के अनुकूल भी बनाया गया है, जिससे अधिकांश लोग साइकिल को यात्रा को प्राथमिकता देते हैं।

शहर की जलवायु योजना में हरित शिक्षा और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्मचारियों और श्रमिकों को भी पर्यावरण-अनुकूल कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों जैसे किंडरगार्टन और अस्पतालों में कम मांस परोसने जैसी नीतियां लागू की गई हैं, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन समग्र प्रयासों के माध्यम से कोपेनहेगन न केवल एक हरित और स्मार्ट शहर बनने की दिशा में बढ़ रहा है, बल्कि यह टिकाऊ विकास के लिए वैश्विक प्रेरणा भी बन रहा है। कोपेनहेगन का मॉडल यह स्पष्ट करता है कि शहरीकरण और सतत विकास परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि सही दृष्टिकोण और योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से इन्हें एक-दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है।

-सुधीर कुमार

आंकड़े

उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ देश के सभी राज्यों को मिल रहा है। पर यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार लाभ लेने में सबसे आगे हैं।

उत्तर प्रदेश	1.85 करोड़
पश्चिम बंगाल	1.23 करोड़
बिहार	1.16 करोड़
मध्य प्रदेश	88.5 लाख
राजस्थान	73.8 लाख

आंकड़े उज्ज्वला योजना कनेक्शन के, 1 नवंबर, 2024 तक के | स्रोत : MoPNG

भगवान ने विष्णुचित्त को आदेश दिया कि जाकर राजा बलदेव का संदेह दूर कीजिए। विष्णुचित्त ने राजा से कहा-माया से छूटने का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति है।

नारायण ही सर्वोपरि

अंतर्यात्रा
संकलित

बलदेव नाम के राजा एक दिन भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे। उन्हें पेड़ के नीचे एक सज्जन विश्राम करते हुए मिले। राजा ने उनसे पूछा, 'आप कहां से आए हैं?' उन्होंने कहा, 'मैं एक ब्राह्मण हूं और गंगा स्नान कर आया हूं, अब सेतु नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा।' राजा ने कहा, 'आप विद्वान लगते हैं, कुछ ज्ञान दीजिए।'

ब्राह्मण ने कहा, 'इन्सान को आठ महीने तक खूब श्रम करना चाहिए, तकि वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक खा सके। दिन भर खूब मेहनत करें, ताकि रात्रि में सुख की नींद ले सके, जवानी में बुढ़ापे के लिए संग्रह करे और सबसे महत्वपूर्ण इस जन्म में परलोक के लिए कमाई यानी भगवान भक्ति करें।' ब्राह्मण उपदेश देकर निकल गए, लेकिन राजा के मन में भक्ति जागृत हो गई और सच्चे संत की खोज में लग गए। उन्होंने कई विद्वानों को बुलाया और शास्त्रार्थ करवाया, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक दिन भक्त विष्णुचित्त को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि आप जाकर राजा बलदेव के संदेह को दूर करो। विष्णुचित्त राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं। खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दो। ये ही हमारे रक्षक हैं। माया से छूटने का एकमात्र उपाय भगवान की आराधना करो। ॐ नमो नारायणाय।' विष्णुचित्त की वाणी सुनकर राजा का हृदय शीतल हो गया और उनसे गुरुमंत्र लेकर भगवान की आराधना शुरू कर दी।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 02 अक्तूबर, 1962

अहिंदी भाषी क्षेत्रों में रोमन लिपि से हिंदी पढ़ाने का सुझाव

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में रोमन लिपि के माध्यम से हिन्दी पढ़ाने का सुझाव राष्ट्रीय एकता का विषय बताते हुए

भारत सरकार की भावात्मक एकता समिति, जिसके अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल डॉ. संपूर्णानंद थे, ने यह सिफारिश की है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को रोमन लिपि में पढ़ाया जाए।

कई संकटों का संकेत है कम बर्फबारी

हिमालय में कम बर्फबारी से पीने और सिंचाई के लिए कम पानी मिलेगा, बीमारियां बढ़ेंगी व पर्यटन उद्योग समेत पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

जयसिंह रावत | **पर्यावरण**

मध्य हिमालय के ओम पर्वत, बदरीनाथ और केदारनाथ समेत ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर सामान्यतः नवंबर से बर्फ पड़नी शुरू हो जाती थी। इस बार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बर्फबारी शुरू हुई है। लेकिन यह बर्फ ऊंची पहाड़ियों पर लंबे समय तक टिकी रहेगी, इसके आसार कम हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वोत्तर को छोड़ कर शेष हिमालयी क्षेत्र में इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है और अगर वर्षा में कमी आई, तो बर्फ भी कम पड़ेगी, जिसका व्यापक असर हिमालय से जुड़े पांच देशों पर पड़ेगा, क्योंकि हिमालय एशिया का जलस्रोत होने के साथ ही इस महाद्वीप का मौसम नियंत्रक भी है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर 2024 में उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों, पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सामान्य से अधिक 121 प्रतिशत तक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिणी प्रशांत महासागर में तटस्थ अल-नीनो स्थितियां देखी जा रही हैं, जबकि ला नीना की स्थितियां अधिक विकसित हो सकती हैं, जो भारतीय जलवायु पर असर डाल सकती हैं। कम वर्षा का हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बर्फबारी वर्षा के ही रूप में होती है। लेकिन यह तापमान और ऊंचाई पर निर्भर करती है।

कम वर्षा से हिमालय की ऊंची चोटियों व घाटियों बर्फ के बजाय हल्की बारिश या शुष्क मौसम का सामना कर सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, हिमालय में कम वर्षा व कम बर्फबारी के मुख्य कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अल-नीनो प्रभाव, वायुमंडलीय दबाव में बदलाव और मानवीय गतिविधियां हैं। वायुमंडलीय दबाव के पैटर्न में बदलाव के कारण उत्तर-पश्चिमी हवाएं हिमालय के ऊपरी हिस्सों तक नहीं पहुंच पातीं, जिससे वर्षा और बर्फबारी में कमी हो सकती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो ही रही है, जिससे बर्फबारी की प्रक्रिया प्रभावित होती है। गर्मी बढ़ने से बर्फ की जगह बारिश अधिक होने लगती है। इसके अलावा पृथ्वी के जलवायु चक्र में प्राकृतिक रूप से बदलाव आते रहते हैं, जैसे 'इंटर-मानसून' और 'मानसून ब्रेक्स', जो हिमालय क्षेत्र में कम वर्षा और बर्फबारी का कारण बन सकते हैं।

कम बर्फबारी का मतलब है बर्फ का पिघलना, जिसका सीधा असर नदियों के जलस्तर पर पड़ता है। इससे जलसंकट पैदा हो सकता है, जो कृषि, पेयजल और उद्योगों पर असर डालता है। गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी ग्लेशियर आधारित नदियां भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये नदियां न केवल जल आपूर्ति का एक मुख्य स्रोत हैं, बल्कि इनका कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन और पीने के पानी के लिए भी बड़ा महत्व है। इन नदियों पर बड़ी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और कई अन्य निर्माणाधीन हैं, जो कम बर्फबारी से प्रभावित होंगी।

बर्फबारी में कमी से ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप, हिमालय क्षेत्र में जलस्तर में वृद्धि हो सकती है, जो बाद में बर्फीले तूफान, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का कारण बन सकता है। कम बर्फबारी से तापमान बढ़ने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। बर्फबारी का एक प्राकृतिक कार्य सूर्य की किरणों को परावर्तित करना (अल्बेडो प्रभाव) है। जब बर्फ कम होती है, तो अधिक गर्मी अवशोषित होती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। हिमालय पर कम बर्फबारी के कारण, भारतीय मानसून और वर्षा पैटर्न भी प्रभावित हो सकते हैं। गर्मी के बढ़ने से मानसून की दिशा और पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिससे असामान्य वर्षा और सूखा जैसी स्थितियां बन सकती हैं।

हिमालय में बर्फबारी कम होने से पानी की आपूर्ति में कमी हो सकती है, जो रबी और खरीफ फसलों के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हिमालय क्षेत्र में स्कीइंग, ट्रैकिंग और अन्य बर्फ आधारित पर्यटन गतिविधियां बहुत प्रसिद्ध हैं। बर्फबारी में कमी से इन गतिविधियों का आकर्षण कम हो सकता है, जिससे पर्यटन उद्योग पर बुरा असर पड़ सकता है। यह स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति में हिमालयी क्षेत्र के वायुदाब और वायुगतिकी में बदलाव आ सकता है। यह वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे श्वसन संबंधित बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वायु प्रदूषण पहले से उच्च स्तर पर होता है। हिमालय पर कम बर्फबारी से गर्मी की लहरें और अधिक प्रकोपित हो सकती हैं। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में सरकारों और जन-सामान्य को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहने की जरूरत है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 10 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जो मनुष्य अपने साथी से घृणा करता है, वह उसी मनुष्य के समान हत्यारा है, जिसने सचमुच हत्या की हो

-स्वामी रामतीर्थ

गलत तरीका

हरियाणा में सुरक्षाकर्मियों ने शंभू बॉर्डर पर बहुस्तरीय अवरोधों के करीब पहुंचे किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की गारंटी समेत अन्य तमाम मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों के विभिन्न संगठन यह प्रदर्शन कर रहे थे। झड़प के बाद कुछ संगठनों ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया मगर कुछ विरोध की रणनीति को लेकर पशोपेश में हैं। पहले ही दिल्ली को निकले किसानों के जत्थों को रोक दिया गया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकार से शंभू बॉर्डर समेत अन्य हाई-वे खोलने के निर्देश देने की मांग की गई है। भीड़ के अनियंत्रित होने पर उन्होंने धुएं के गोले प्रयोग किए। हरियाणा के खाप नेताओं ने भी विरोध मार्च में शामिल होने का निर्णय लिया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा विभाजित है। उसके विभिन्न समूहों में गुटबाजी के चलते उनके निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री हरियाणा जा रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों से विशेष सतर्कता बरतने की उम्मीद लाजमी है। किसानों को चोट पहुंचाना कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। मगर पुलिस का आरोप है कि उन्होंने लोहे की छड़ों व रस्सियों के मार्फत लोहे की सुरक्षा जालियों को हटाना चालू कर दिया था। पूर्व में हमने देखा है, किसानों ने इन व्यवधानों से निपटने की भरपूर और बड़े स्तर पर तैयारियां की थीं। उन्होंने क्रेन व ट्रैक्टरों के आगे लोहे की मोटी-मोटी मजबूत छड़ें लगवाई थीं, जो विरोध-प्रदर्शन का उचित तरीका नहीं कहा जा सकता। हालांकि तीन सौ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के प्रति सरकार का रवैया भी सामान्य नहीं है। किसानों के प्रति सहिष्णुताभाव प्रदर्शित करते हुए सरकार को विशेषज्ञों के दल के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत करानी चाहिए। घायल किसानों के इलाज में किसी तरह असावधानी अक्षम्य मानी जाएगी। हकीकत में समर्थन मूल्य को लेकर देश भर के किसान उतने उग्र नहीं हैं। जितने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ईर्द-गिर्द के किसान संगठनों ने नाराजगी दिखाई है। समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के साथ ही ऋण माफी, पेंशन व सस्ती बिजली की मांग के प्रति सरकार को सलीके से जवाब देने चाहिए। क्योंकि बात केवल बड़े किसानों की नहीं है, इसमें छोटे-मझोले किसान भी शामिल हैं। जिनकी जिन्दगी पूरी तरह कृषि पर ही आधारित है। बड़े व समृद्ध किसानों पर होने वाली सख्ती की मार से कमजोर किसानों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है।

'अमंगलकारी' रविवार

भारतीय क्रिकेट के लिए बीता रविवार का दिन अच्छा नहीं बीता, क्योंकि एक नहीं तीन हारों का सामना करना पड़ा। पहले रोहित शर्मा की अगुआई में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से पिंक बॉल टेस्ट में 10 विकेट से हार गई। इसके बाद महिला क्रिकेट टीम, यह भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 122 रनों से हारकर तीन वनडे मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़कर सीरीज गंवा बैठी। वहीं अंडर-19 टीम एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश से हारकर खिताब पर कब्जा जमाने से वंचित हो गई। भारतीय पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली पांच टेस्ट सीरीजों में से चार जीती हैं और उसने सीरीज का पहला पर्थ टेस्ट जीता तो क्रिकेटप्रेमियों को लगा कि वह एक और सीरीज जीतने की तरफ बढ़ गया है, लेकिन एडिलेड टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने जिस दबदबे के साथ जीता है, उसने टीम की चिंताओं को बढ़ा दिया है। असल में पिंक बॉल रात में ज्यादा स्विंग करती है और उसे हैंडिल करने में हमारे बल्लेबाज सक्षम नजर नहीं आए। भारत को अब ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में वापसी करनी होगी और वह ऐसा कर सका तो टीम फिर से पटरी पर लौट आएगी। साथ ही उसकी इस हार से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की कमजोर पड़ी संभावनाओं को मजबूती मिल जाएगी। एडिलेड की हार से भारत डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में 57.29 प्रतिशत अंकों से तीसरे स्थान पर पिछड़ गया है। जहां तक महिला टीम की हार की बात है, तो इसमें गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन की अहम भूमिका रही। जब गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट पर 371 रन बनाने की छूट दे दी, तब ही हार तय हो गई। गेंदबाजों के कमजोर प्रदर्शन के बाद बल्लेबाज भी कभी टीम को मुकाबले में लाते नहीं दिखे। पुरुष टीम और महिला टीमों की हार इतनी धक्का पहुंचाने वाली नहीं है, जितनी अंडर-19 एशिया कप में बांग्लादेश के हाथों हार। वनडे फार्मेट से खेले गए इसमें बांग्लादेश को 198 रनों पर सीमित करने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने 139 रन तक ही पहुंचकर बेहद निराश किया। बांग्लादेश लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। इससे यह संकेत तो मिलता है कि हमारी सप्लाई लाइन पहली की तरह मजबूत नहीं है। बेहतर हो कि इस तरफ अभी से ध्यान देकर सुधार लाया जाए, क्योंकि भविष्य की बागडोर इनके ही हाथों में रहनी है।

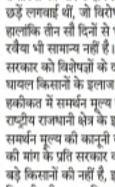

विमर्श/अवनीश कुमार गुप्ता

समय की मांग है प्राकृतिक खेती

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भारत की कृषि में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन और किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। रासायनिक खेती के दीर्घकालिक प्रभावों ने न केवल मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किया है, बल्कि जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस संदर्भ में, प्राकृतिक खेती एक सशक्त समाधान के रूप में उभर रही है, जो न केवल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है, बल्कि कृषि उत्पादन प्रणाली को भी स्वस्थ और प्राकृतिक बनाती है।

प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके खेती की जाती है, जिससे लागत कम होती है और किसानों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। गोबर, गोमूत्र, और जीवक खाद जैसे प्राकृतिक उत्पादों के उपयोग से मिट्टी में जैविक तत्वों की वृद्धि होती है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ने इस दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें 2025-26 तक 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के लिए 2,481 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बाजार समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस मिशन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदों के प्रति जागरूक करना। वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता ने किसानों के मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। प्राकृतिक खेती का दूसरा अहम पहलू यह है कि यह पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। रासायनिक खेती के कारण जल स्रोतों में प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। प्राकृतिक खेती न केवल इन समस्याओं को कम करती है, बल्कि मिट्टी में जैविक तत्वों की पुनर्बहाली और जल प्रबंधन में भी सुधार करती है। इस पहल से पर्यावरणीय संकट को कम करने में मदद मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।

सहयोग से होगी संरक्षा

मानवाधिकार दिवस

राजेश मणि

वर्ष 2024 के मानवाधिकार दिवस की थीम 'असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना' हमारे समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। यह थीम यह संदेश देती है कि असमानताएं केवल आर्थिक और सामाजिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव के रूप में भी मौजूद हैं, जो समाज में नफरत, हिंसा और विभाजन को जन्म देती हैं। इन असमानताओं का निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन भेदभावपूर्ण संरचनाओं को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम सभी के लिए समान अवसर, समान न्याय और समान विकास सुनिश्चित नहीं कर सकते।

असमानताओं का प्रभाव न केवल उन व्यक्तियों पर पड़ता है जिन्हें यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, बल्कि यह समग्र समाज के लिए नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। जब महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक या अन्य कमजोर वर्ग अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं, तो उनका योगदान समाज में घट जाता है, और इससे समाज का समग्र विकास रुक जाता है। अतः असमानताओं को कम करना केवल एक कानूनी या मानवाधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी कदम है जो समाज की समृद्धि और शांति के लिए आवश्यक है।

'असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना' की थीम हमें यह समझने का अवसर देती है कि असमानताएं केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक स्तर पर भी मौजूद होती हैं। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार में भेदभाव के कारण कई समुदायों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। इस प्रकार, कुछ समुदायों के पास संसाधन और अवसर होते हैं, जबकि अन्य अपने बुनियादी अधिकारों तक भी नहीं पहुंच पाते। इसका समाधान तभी संभव है, जब हम सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से समान अवसरों की गारंटी प्रदान करें, ताकि सभी वर्गों और समुदायों को उनके अधिकारों का पूरी तरह से अनुभव हो सके। जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तो वे इन असमानताओं के खिलाफ खड़े हो सकेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। मानवाधिकार के सिद्धांतों का आधार 'मानवता' है, जिसका अर्थ है कि हर इंसान को अपने अस्तित्व के लिए समान अधिकार प्राप्त है, चाहे उसका रंग, धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जो किसी भी अन्य अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी को भी

स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानूनी प्रक्रिया के। इसके अलावा, संविधान उन व्यक्तियों को सजा देने का प्रावधान करता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस संदर्भ में, भारतीय संविधान और कानूनी प्रावधानों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह संविधान न केवल नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाए। हालांकि, इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के मामले में, कई क्षेत्रों में अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा केवल कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि यह समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन आज भी कई महिलाएं हिंसा, भेदभाव और असमानता का सामना करती हैं। इसी तरह, बच्चों का सबसे बुनियादी अधिकार शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य है, लेकिन लाखों बच्चे बालश्रम, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त सामाजिक प्रयास की आवश्यकता है। इसी तरह, बच्चों के अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। बच्चों का सबसे बुनियादी अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा है, लेकिन लाखों बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं और उनके साथ बालश्रम, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है।

भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 28 सितम्बर 1993 को एक महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया, और इसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' की स्थापना की गई। यह आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले मामलों में जांच करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। मानवाधिकार दिवस पर हमें महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और समाज में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मानवाधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि यह हमारे सामाजिक और नैतिक दायित्व भी हैं। हमें संविधान के अनुच्छेदों का पालन करते हुए इन अधिकारों की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। समाज में हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि मानवाधिकार केवल अधिकार नहीं हैं, बल्कि ये कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम सही मायनों में एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना होगी।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसा समाज बनाएं, जहां हर महिला और बच्चा अपनी स्वतंत्रता से जी सके, जहां उन्हें किसी प्रकार का उत्पीड़न, भेदभाव, या असमानता का सामना न करना पड़े। यह समाज तभी संभव होगा जब हम मानवाधिकारों के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। ऐसे वातावरण का सृजन हो जिसमें मानवाधिकारों की ग्राह्यता रहे समाज का प्रत्येक वर्ग इसके लिए जागरूक रहे एक बेहतर भविष्य के लिए जागरूक होना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना हमारे समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। यह थीम यह संदेश देती है कि असमानताएं केवल आर्थिक और सामाजिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव के रूप में भी मौजूद हैं, जो समाज में नफरत, हिंसा और विभाजन को जन्म देती हैं। इन असमानताओं का निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन भेदभावपूर्ण संरचनाओं को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम सभी के लिए समान अवसर, समान न्याय और समान विकास सुनिश्चित नहीं कर सकते।

असमानताओं का प्रभाव न केवल उन व्यक्तियों पर पड़ता है जिन्हें यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, बल्कि यह समग्र समाज के लिए नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। जब महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक या अन्य कमजोर वर्ग अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं, तो उनका योगदान समाज में घट जाता है, और इससे समाज का समग्र विकास रुक जाता है। अतः असमानताओं को कम करना केवल एक कानूनी या मानवाधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी कदम है जो समाज की समृद्धि और शांति के लिए आवश्यक है।

'असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना' की थीम हमें यह समझने का अवसर देती है कि असमानताएं केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक स्तर पर भी मौजूद होती हैं। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार में भेदभाव के कारण कई समुदायों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। इस प्रकार, कुछ समुदायों के पास संसाधन और अवसर होते हैं, जबकि अन्य अपने बुनियादी अधिकारों तक भी नहीं पहुंच पाते। इसका समाधान तभी संभव है, जब हम सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से समान अवसरों की गारंटी प्रदान करें, ताकि सभी वर्गों और समुदायों को उनके अधिकारों का पूरी तरह से अनुभव हो सके। जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तो वे इन असमानताओं के खिलाफ खड़े हो सकेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। मानवाधिकार के सिद्धांतों का आधार 'मानवता' है, जिसका अर्थ है कि हर इंसान को अपने अस्तित्व के लिए समान अधिकार प्राप्त है, चाहे उसका रंग, धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जो किसी भी अन्य अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी को भी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानूनी प्रक्रिया के। इसके अलावा, संविधान उन व्यक्तियों को सजा देने का प्रावधान करता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस संदर्भ में, भारतीय संविधान और कानूनी प्रावधानों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह संविधान न केवल नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाए। हालांकि, इन कानूनी प्रावधानों के बावजूद, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के मामले में, कई क्षेत्रों में अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा केवल कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि यह समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन आज भी कई महिलाएं हिंसा, भेदभाव और असमानता का सामना करती हैं। इसी तरह, बच्चों का सबसे बुनियादी अधिकार शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य है, लेकिन लाखों बच्चे बालश्रम, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त सामाजिक प्रयास की आवश्यकता है। इसी तरह, बच्चों के अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। बच्चों का सबसे बुनियादी अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा है, लेकिन लाखों बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं और उनके साथ बालश्रम, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है।

भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 28 सितम्बर 1993 को एक महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया, और इसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' की स्थापना की गई। यह आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले मामलों में जांच करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। मानवाधिकार दिवस पर हमें महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और समाज में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मानवाधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि यह हमारे सामाजिक और नैतिक दायित्व भी हैं। हमें संविधान के अनुच्छेदों का पालन करते हुए इन अधिकारों की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। समाज में हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि मानवाधिकार केवल अधिकार नहीं हैं, बल्कि ये कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम सही मायनों में एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना होगी।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसा समाज बनाएं, जहां हर महिला और बच्चा अपनी स्वतंत्रता से जी सके, जहां उन्हें किसी प्रकार का उत्पीड़न, भेदभाव, या असमानता का सामना न करना पड़े। यह समाज तभी संभव होगा जब हम मानवाधिकारों के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। ऐसे वातावरण का सृजन हो जिसमें मानवाधिकारों की ग्राह्यता रहे समाज का प्रत्येक वर्ग इसके लिए जागरूक रहे यह केवल अधिकार नहीं सभी के दायित्व का बोध भी हो। और यह परिवार से प्रारम्भ होकर, समाज, समुदाय में दिखे हमारे देश की यही भव्यता, दिव्यता है जहां विभिन्न जाति-धर्म-समुदाय को एक समान देखा जाता है।

(लेख में विचार निजी हैं)

तेजी से बढ़ रहा गैर-एल्कोहल बेवरेज क्षेत्र

- भारत पेय प्रसंस्करण उद्योग में खुद को विश्व लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए अपार अवसरों के साथ अहम मोड़ पर है और गैर-अल्कोहल बेवरेज सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है
- इंडियन बेवरेज एसोसिएशन (आईबीए) के मुताबिक, अर्थव्यवस्था में यह क्षेत्र रोजगार, जमीनी स्तर पर विकास और इनोवेशन को बढ़ा रहा है। इससे हम विजन-2047 के मुताबिक आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, किसानों की आय दोगुना करने और निर्यातोन्मुख अर्थुति श्रृंखला को संभव बना सकेंगे

(स्रोत - मीडिया इनपुट्स)

हिन्दुत्व समर्थक कार्यकर्ताओं की परेशानी यह है कि वे संकटग्रस्त देशों के कट्टरपंथियों के व्यवहार की नकल करते हैं- उन्ही समूहों की, जिनकी वे आलोचना करते हैं। इससे लोकतांत्रिक दुनिया में भारत की स्थिति को नुकसान पहुंचा है।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kasushikcbasu

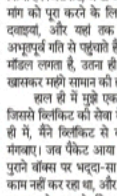

ऑनलाइन कंपनियां | नरविजय यादव

ग्राहकों का भरोसा जरूरी या गति

सुविधाजनक, तेज और 10 मिनट में घरेलू वस्तुओं की डिलीवरी के वादे ने शहरी उपभोक्ताओं को आकर्षित किया है। ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म इस मांग को पूरा करने के लिए सामने आए हैं, जो किराना, दवाइयां, और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी अभूतपूर्व गति से पहुंचाते हैं, लेकिन जितना आकर्षक यह मॉडल लगता है, उतना ही चुनौतियों से भरा हुआ भी है, खासकर महंगे सामान की होम डिलीवरी के मामले में।

हाल ही में मुझे एक परेशानी वाला अनुभव हुआ, जिससे ब्लिंकिट की सेवा में खामियों का पता चला। हाल ही में, मैंने ब्लिंकिट से वोट निर्वाणा ऑवन ईयरबड्स मंगवाए। जब पैकेट आया तभी लगा कि कुछ गड़बड़ है। पुराने बॉक्स पर भद्दा-सा टेप चिपका था, बायां ईयरबड काम नहीं कर रहा था, और दो ईयरफाक गायब थे। मैंने तुरंत कस्टमर केअर को ईमेल करके बताया और रिप्लेसमेंट की मांग की। दो दिन की जद्दोजहद के बाद तीसरे दिन जो रिप्लेसमेंट आया, उसने मुझे हैरान कर दिया। यह बॉक्स भी खुला हुआ था, चार्जिंग केस खाली था, और दोनों ईयरबड्स गायब थे! फटाफट वीडियो और फोटो के साथ ईमेल से शिकायत की और कंपनी को टैग करते हुए ट्वीट किया।

ब्लिंकिट ने अपनी कमी नहीं मानी और रिफंड या रिप्लेसमेंट से साफ इनकार कर दिया। हैरानी इस बात की थी कि दोनों डिलीवरी कर्मचारियों ने उत्साह से बताया था कि डिब्बे में क्या है, जबकि सामान्यतया ये ऐसा नहीं करते हैं। दूसरे वाले ने तो पैकेट को चेक भी नहीं करने दिया और फटाफट खिसक गया। यह पहला मामला नहीं है जिसमें महंगी चीजें डिलीवर करने में ब्लिंकिट विफल रहा। खाली बॉक्स भेजना, पैकेट से छेड़छाड़, और गलत सामान की डिलीवरी की शिकायतें आम हैं। दिवाली पर एक ग्राहक को सोने का आधी कीमत वाला सिक्का दिया गया, एक महिला को खराब पंखे दे दिए, जबकि एक अन्य ग्राहक को पुरुषों के अंडरवियर की जगह महिलाओं के अंतःवस्त्र भेज दिए। इन सभी मामलों में रिटर्न और रिफंड करने से मना कर दिया गया। ऐसी घटनाएं ब्लिंक कॉमर्स मॉडल की कमजोरी दर्शाती हैं, जहां भरोसे और ईमानदारी की जगह स्पीड पर ध्यान दिया जाता है। तेजी से सामान को होम डिलीवरी का मॉडल सुविधाजनक तो है, लेकिन खामियों से भरा है।

डिलीवरी कर्मी समय सीमा का पालन करने के दबाव में रहते हैं, जिससे जांच या गुणवत्ता नियंत्रण की गुंजाइश कम बचती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी महंगी चीजें, ऐसे माहौल में असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उचित निगरानी न होने से चीजों की चोरी और डिब्बे से छेड़छाड़ की आशंका बढ़ जाती है। बाहरी डिलीवरी पार्टनर्स पर निर्भर रहने से समस्या और जटिल हो जाती है। डिलीवरी कर्मियों का संदिग्ध व्यवहार और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही की कमी ने मुझे निराश और असहाय कर दिया। वोट की पैकेजिंग दोषपूर्ण है। वे डिब्बों को सिर्फ दो छोटे स्टिकर से बंद करते हैं। मेरे मंगाए दोनों डिब्बों के स्टिकर हटे हुए थे, यानी उन्हें खोलकर उनमें से महंगी चीजें चुरा ली गई थीं। ऐसे अपर्याप्त सुरक्षा उपाय न केवल नियमितों बल्कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी सवाल उठाते हैं। और भी परेशान करने वाली बात ब्लिंकिट की ग्राहक सेवा का ढीला रवैया है। मेरी शिकायतों को खारिज किया गया। कंपनी ने मेरा पैसा लौटाने और दूसरा सही प्रोडक्ट देने से साफ इनकार कर दिया। वैध शिकायतों के प्रति यह उपेक्षित दृष्टिकोण ब्लिंकिट के खिलाफ कई शिकायतों में एक सामान्य बात है। इनके कस्टमर केअर से सिर्फ ईमेल से संपर्क हो सकता है, जिस पर बोट्रियो भी अपलोड नहीं हो पाते हैं। किसी भी उपभोक्ता-केंद्रित व्यवसाय की रीढ़ प्रभावी ग्राहक सेवा है। समस्याओं को पारदर्शी और कुशल ढंग से सुलझाने में विफल रहकर ब्लिंकिट अपने ग्राहकों को नाराज करने का जोखिम उठा रहा है। इन बार-बार होने वाली खामियों से सिस्टम में बदलाव की मांग उठती है।

ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म को स्पीड से ज्यादा ग्राहकों के भरोसे को तरजीह देनी चाहिए। इसमें डिलीवरी कर्मियों की सख्त जांच, टैंपर-प्रूफ सीलबंद पैकेजिंग, और जवाबदेही के लिए रीयल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हो सकता है। इसके अलावा, ग्राहकों की शिकायतें तत्काल दूर करने का सिस्टम होना जरूरी है। एक बिल्क कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक सेवा टीमें समस्याओं को निष्पक्षता व शीघ्रता से हल करने में सक्षम हों, न कि रिटर्न या रिफंड को हतोत्साहित करें। बिल्क डिलीवरी का आकर्षण निर्विवाद है, ऐसे में इसकी दीर्घकालिक सफलता विश्वसनीयता और जवाबदेही पर निर्भर करती है। उपभोक्ता मामलों के विभाग को उचित होम डिलीवरी के लिए दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जिसमें पैकेजिंग मानकों और समस्या निवारण का सिस्टम भी शामिल रहे। भले ही ब्लिंक कॉमर्स एप्स ने रिटेल के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि भरोसा और पारदर्शिता उपभोक्ता से जुड़े रहने के लिए आवश्यक तत्व हैं। रिटेल में कड़ी प्रतियोगिता है, लेकिन इसे स्पीड से नहीं, ग्राहकों के भरोसे व संतुष्टि से ही जीता जा सकता है।

निर्णय | ओशो

एक बादशाह ने अपने दरबारी मसखरे को खुश होकर पुरस्कार में एक घोड़ा दिया। घोड़ा बड़ा मरियल और कमजोर था। चल भी सकेगा, यह भी संदिग्ध था। मसखरा तो मसखरा ठहरा, उसने सम्राट से ते कुछ न कहा, छलांग मारकर घोड़े पर सवार हो गया और एक ओर चलने की कोशिश करने लगा या घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा। बादशाह ने आवाज देकर पूछा, बड़े मियां, कहां चल दिए? उसने कहा, हुजूर, जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। पर सम्राट ने कहा, आज तो सोमवार है। उसने कहा, यह घोड़ा जुम्मे तक भी पहुंच जाए मस्जिद तो बहुत है! अभी से चले तो ही पहुंच पाएंगे। और मस्जिद दो कदम पर है। घोड़ों घोड़ों की बात है। कौन पहुंचा, नहीं पहुंचा, इसकी फिकिर छोड़ो। घोड़ों घोड़ों की बात है। मस्जिद दो कदम पर थी, मैं तुमसे कहता हूं, दो कदम पर भी नहीं है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर है। और कल पहुंचोगे ऐसा भी नहीं है, घड़ी भर बाद पहुंचोगे ऐसा भी नहीं है, तत्क्षण, इसी क्षण, जैसे बिजली कौंध जाए ऐसे क्रांति होती है। आंख बंद करके तुम अगर भीतर देखो तो अभी पहुंच गए, इसी क्षण पहुंच गए। कल पर टालने का प्रश्न ही नहीं है। जनक को हुआ, तुम्हें हो सकता है, क्योंकि जनक से रत्ती भर भी तुममें कमी नहीं है। मुझे हुआ, तुम्हें हो सकता है, क्योंकि मुझसे रत्ती भर भी तुममें कमी नहीं है। और अगर नहीं हो रहा है, तो याद रखना, तुमने कहीं गहरे में निर्णय कर रखा है कि अभी होने नहीं देना है। शायद न होने में तुम्हारा कुछ न्यस्त स्वार्थ है। शायद न होने में तुम अभी सोचते हो, थोड़ा और रस ले लें, थोड़ा और उटोल लें, शायद संसार में कुछ हो, यह तो फिर कभी भी कर सकी लेंगे। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं, अभी तो जिंदगी पड़ी है। ध्यान करना जरूर है, लेकिन आखिर में कर लेंगे। अभी के थोड़े ही हो गए, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। और का आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े से

दैनिक जागरण
परिवर्तन के साथ सामंजस्य ही प्रगति का मंत्र है

जार्ज सोरोस का साया

एक और दिन संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस हंगामे का कारण वही अमेरिकी निवेशक जार्ज सोरोस रहे, जिन्हें लेकर पहले भी संसद के भीतर और बाहर पक्ष-विपक्ष के बीच तकरार हो चुकी है। पहले भाजपा के नेता यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी जार्ज सोरोस के भारत विरोधी एजेंडे को न केवल आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके करीबियों से मेल-मुलाकात भी करते रहे हैं। अब भाजपा का आरोप यह है कि सोनिया गांधी का संबंध उस फोरम आफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन से है, जिसे जार्ज सोरोस से वित्तीय मदद मिलती है। भाजपा की मानें तो सोनिया गांधी उक्त फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं और यह मंच इस मत का है कि कश्मीर को भारत से अलग क्षेत्र माना जाना चाहिए। यह तो ब्ये खतरनाक विचार है, जो पाकिस्तान का है। आखिर भारत की एकता-अखंडता के खिलाफ ऐसे विचार रखने वाले किसी संगठन से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को कोई लेना-देना क्यों होना चाहिए? भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस का क्रोधित होना समझ आता है, लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है। आखिर उसे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने में क्या समस्या है? कांग्रेस के साथ सत्तापक्ष से भी यह अपेक्षित है कि वह जार्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने तक ही सीमित न रहे, बल्कि यह भी उजागर करे कि यह अमेरिकी निवेशक भारतीय हितों के खिलाफ किस तरह सक्रिय है। ऐसा केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि जार्ज सोरोस का ओपेन सोसायटी फाउंडेशन ओसीसीआरपी नामक उस अमेरिकी मीडिया समूह को पैसा देता है, जिसने अदाणी समूह के खिलाफ अभियान छेड़ा था, बल्कि इसलिए भी है कि बांग्लादेश में उथलपुथल के पीछे भी उनका हाथ नजर आ रहा है।

जो जार्ज सोरोस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस को अपना मित्र बताते हैं, उनके एक करीबी ने इसी रविवार को उनसे ढाका में मुलाकात की थी। यह मुलाकात भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश जाने के पहले हुई। क्या यह महज एक दुर्योग है? सच जो भी हो, बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे अमेरिकी एजेंसियों की भूमिका किसी से छिपी नहीं। तथ्य यह भी है कि भारत की तमाम चिंताओं के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों का दमन थम नहीं रहा है। इससे भी चिंताजनक यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन उस पर अमल करने में आनाकानी कर रही है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की कारोबारी गौतम अदाणी से करीबी और सोनिया-राहुल गांधी की जार्ज सोरोस से निकटता एक जैसी बात नहीं है। जार्ज सोरोस कोई भारतीय कारोबारी नहीं हैं। वह केवल मोदी सरकार से ही बैर नहीं रखते। उन्हें अन्य कई देशों की सरकारें भी खलनायक मानती हैं। उनके भारत विरोधी रवैये के कारण विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी उन्हें खरी-खरी सुना चुके हैं।

असुरक्षित बेटियां

कहा जाता है कि जिनके घर बेटियां होती हैं, वे भाग्यशाली होते हैं। कामिन परिवेश में बेटियों के जन्म पर लोग जितनी खुशी मनाते हैं, उससे अधिक चिंता उन्हें बेटियों की अस्मिता और सुरक्षा को लेकर रहती है। बढ़ते आपराधिक मामले उन्हें असहज व असुरक्षित महसूस करवाते हैं। बेटियों के बिना सृष्टि की कल्पना असंभव है, लेकिन समाज में कुछ लोगों की घृणित सोच उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। बेटियों के विरुद्ध अपराध में देवभूमि कहे जाना हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश की सरकारों ने गंभीरता दिखाई है और हेल्पलाइन भी शुरू की है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाला पक्ष यह है कि अब भी छेड़छाड़, दुष्कर्म व पिटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ससुराल में प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। बिलासपुर जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 14 वर्षीय बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके वास्तविक कारण तो जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी छोटी सी आयु में उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? चिंता का विषय यह है कि अधिकतर घटनाओं में जान-पहचान वाले लोग ही संलिप्त पाए जा रहे हैं। शिमला जिले के जुब्बल में पड़ोसी युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। दो दिन पहले शिमला शहर में शर्मनाक घटना हुई थी, जिसमें सात वर्षीय बच्ची से मामा ने ही दुष्कर्म किया। पिछले सप्ताह भी ठियोग में दुष्कर्म पीड़िता युवती ने बच्ची को जन्म दिया था। बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है तो उनकी सुरक्षा का दायित्व भी समाज का है ही। कहीं भी बेटियों के विरुद्ध अपराध होता देखें तो यह न सोचें कि वह किसकी बेटी है। बेटियां सबकी साझा अमानत होती है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सबको निभानी होगी।

असद के पतन का अंतरराष्ट्रीय असर

दिव्य कुमार सोती

तुर्किये और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों को देखते हुए भारत को भी सीरिया के घटनाक्रम से सतर्क रहना होगा

अफोरेस्ट हाफ्ताह

सीरिया में नाटकीय घटनाक्रम के तहत बशर अल-असद सरकार का पतन हो गया। वहां वर्षों से असद की शिया प्रभुत्व वाली सरकार और विभिन्न सुन्नी चरमपंथी गुटों के बीच संघर्ष जारी था, परंतु 2019 में इस्लामिक स्टेट के पतन और उसके स्वयंघोषित खलीफा अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद वह सुर्खियों से बाहर था। 2015-16 में असद सरकार के समर्थन में रूसी वायुसेना के अभियान द्वारा सुन्नी चरमपंथियों के खदेड़े जाने के बाद यह तय माना जाने लगा था कि असद सरकार का पतन संभव नहीं है, परंतु गत दिवस ऐसा ही हुआ। पिछले 11-12 दिनों में सुन्नी चरमपंथी गुट हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) के अभियान ने एकाएक तेजी पकड़ी और सीरिया की फौज बिना लड़े ही पीछे हटती चली गई और अंततः बशर अल असद को देश छोड़कर रूस जाना पड़ा। इस बार रूस और ईरान, दोनों ने असद सरकार के समर्थन में हस्तक्षेप से परहेज किया। असद सरकार यूक्रेन से लेकर फलस्तीन तक बिछी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर बलि का बकरा बन गई। ईरान ने असद की बचाने के लिए कोई बड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया, क्योंकि उसे खुद पर इजरायली और अमेरिकी हमले का अंदेशा है। वह अपने सीमित सैन्य और आर्थिक संसाधनों को सहेज कर रखना चाहता है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के चलते रूस अपने सैन्य संसाधनों को यूक्रेन मोर्चे पर केंद्रित रखना चाहता है, ताकि वहां अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा कर सके और संघर्ष विराम की स्थिति में उसके कब्जे वाला भूभाग उसके पास ही रहे। ईरान और रूस के इस रवैये से सबसे बड़ा लाभ इजरायल और तुर्किये को हुआ।

हमास और हिजबुल्ला के कमजोर पड़ने के बाद असद सरकार का पतन ईरान के नेतृत्व वाले शिया गठजोड़ के लिए एक बड़ा झटका है और हाल-फिलहाल इजरायल के लिए बड़ी तात्कालिक सफलता। असद सरकार के पतन के तुरंत बाद इजरायली सेनाओं ने गोलान की पहाड़ियों से आगे बढ़कर सीरिया के अंदर आपरेशन प्रारंभ कर दिया है। इसका उद्देश्य इजरायल की सीमाओं का विस्तार, एक बफर जोन का निर्माण और सीरिया की सैन्य क्षमता को कुंद करना है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सीरियाई सेना के लड़ने से मना कर देने के पीछे कहीं इजरायल और उसके समर्थक पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का हाथ तो नहीं? इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने असद सरकार के पतन को ऐतिहासिक अवसर बताया, परंतु साथ ही चेताया भी कि इस घटनाक्रम के भयावह परिणाम हो सकते हैं। नेतन्याहू ऐसा कहने के लिए इसलिए मजबूर हैं, क्योंकि जिस एचटीएस को पश्चिमी मीडिया सीरिया का विद्रोही संगठन बता रहा है, उसमें अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के पूर्व आतंकी भरे पड़े हैं। सीरिया पर काबिज तत्व फिलहाल भले ही इजरायल के काम आए हों, पर वे अपना असली रंग दिखा सकते हैं। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार के बाद अमेरिका के पाले-पोसे ओसामा बिन लादेन ने ऐसा ही किया था। एचटीएस का असली आका कोई और नहीं, बल्कि तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं, ठीक वैसे ही जैसे जैश और लश्कर का पाकिस्तान है।

प्रथम विश्व युद्ध में तुर्किये की हार से पहले तक सीरिया के विभिन्न इलाके आटोमन तुर्क साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। सऊदी अरब भी उस साम्राज्य का हिस्सा था। आज के सीरिया और इराक जैसे देशों की सीमाएं प्रथम विश्व युद्ध के विजेता देशों फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने मनमुताबिक खींची थीं। एर्दोगन उसी आटोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना का सपना देख रहे हैं। वह सीरिया पर काबिज हुए तत्वों का उपयोग कुर्दों को ठिकाने लगाने में कर सकते हैं, जो सीरिया के एक हिस्से पर काबिज हैं और तुर्किये में भी सक्रिय हैं। सीरिया का तुर्किये समर्थित लड़ाकों के हाथ में जाना कतर-तुर्किये गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव को नया जीवन दे सकता है, जिसके जरिये कतर और सऊदी अरब की गैस सीरिया और तुर्किये से होकर यूरोप पहुंच सकती है और यूरोप की रूस पर ऊर्जा निर्भरता घट सकती है। ऐसे में बहुत संभव है कि रूस और ईरान सीरिया में अपने खुफिया अभियानों का दायरा बढ़ाएं और जैसे अमेरिका, तुर्किये और इजरायल ने अपने-अपने हितों के लिए चरमपंथी गुटों का उपयोग किया, वैसे ही रूस भी अपने मतलब के चरमपंथियों को बढ़ावा दे।

भले ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ट्रंप का कहना हो कि अमेरिका का सीरिया से कोई लेन-देन नहीं है, पर एचटीएस का नेता गोलानी इस्लामिक स्टेट के सरगना अबु बकर अल बगदादी का दायें हाथ रह चुका है और सीरिया में अलकायदा का प्रमुख भी रहा है। विडंबना यह है कि अमेरिका का लिबरल मीडिया दस मिलियन डालर के इनामी और इराक में अमेरिकी सैनिकों की हत्याओं में शामिल रहे गोलानी को क्रांतिकारी बता रहा है। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भी अमेरिकी डीप स्टेट ने अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया है या वह ट्रंप के काबू से बाहर है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप की जीत के बाद भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा बांग्लादेश में सत्तासीन की गई मोहम्मद युनुस सरकार की भारत को लेकर आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। मुस्लिम जगत में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा की कई अलग-अलग शख्सा मुस्लिम ब्रदरहुड, वहाबी इस्लाम और खामेनेई के चरमपंथी शिया संगठनों के संघर्ष का प्रभाव भारत की सुरक्षा पर पड़ता रहा है। इनमें से किसी भी विचारधारा का विस्तार भारत के हित में नहीं है। इसलिए जहां हमास और हिजबुल्ला का विनाश और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्षरण भारत के हित में है, वहीं मुस्लिम जगत में सुन्नी-शिया खेमों में शक्ति संतुलन बना रहना भी आवश्यक है। तुर्किये और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों के चलते भी भारत को सीरिया के घटनाक्रम से सतर्क रहना होगा। यह ठीक नहीं कि एक के बाद एक देश सुन्नी चरमपंथी गुटों के हाथ में पड़ते जा रहे हैं और तुर्किये एवं कतर जैसे देशों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरह ही आतंकवाद को विदेश नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ता सिनेमा

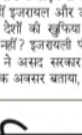

सुभाष घई

कोई फिल्म महोत्सव सही अर्थों में तभी सार्थक बनता है, जब वह अपने इतिहास को याद करता है

55वें फिल्म महोत्सव की एक झलक। प्रेट्र

हाल में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआइ) संपन्न हुआ। फिल्मों से संबंधित सभी पहलुओं के इस भव्य समारोह का मुख्य आकर्षण भारतीय सिनेमा की चार महान हस्तियों-बहुमुखी अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव, महान शोमैन राज कपूर, सदाबहार स्वरों के सशक्त मोहम्मद रफी और प्रतिभाशाली कहानीकार तपन सिन्हा के कार्यों से जुड़ा एक ऐतिहासिक उत्सव रहा। इन दिग्गजों ने अपनी प्रतिभा एवं दृष्टिकोण से फिल्म उद्योग को गौरवान्वित किया और एक ऐसा अमिट जादू बिखेरा, जिसने फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों और दर्शकों की कई पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित किया है। उनकी विरासत युगों-युगों तक गूंजती रहेगी।

राज कपूर अभिनेता, निर्देशक, स्टूडियो मालिक और निर्माता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्में अक्सर सामाजिक मुद्दों को हास्य एवं संवेदना के साथ चित्रित करती थीं, जिससे वे आम आदमी की आवाज बन गए। अपनी मार्मिक कथाओं और गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाने वाले तपन सिन्हा बंगाल के एक निपुण फिल्मकार थे, जिनका काम अक्सर आम लोगों के संघर्ष को उजागर करता था। कलात्मकता को सामाजिक टिप्पणी के साथ मिश्रित करने की उनकी क्षमता ने उनकी फिल्मों को कालजयी बना दिया है। अक्किनेनी नागेश्वर राव, जिन्हें एएनआर के नाम से जाना जाता है, तेलुगु सिनेमा की महान हस्ती थे। उन्हें उनके लचीले व्यवहार एवं सहजता अभिनय के लिए जाना जाता है। छह दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने तमाम यादगार भूमिकाएं निभाईं। सबसे लोकप्रिय पार्श्वगायकों में से एक रफी अपनी असाधारण आवाज और अभिव्यंजक गायन शैली के लिए प्रसिद्ध रहे। उनके सदाबहार गीतों ने कई पीढ़ियों एवं भाषाओं के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है।

एक फिल्म महोत्सव सही अर्थों में तभी सार्थक बनता है, जब वह अपने इतिहास को याद करता है। आइएफएफआइ के 55वें संस्करण ने न केवल इन हस्तियों की सिनेमाई उपलब्धियों का उत्सव मनाया, बल्कि फिल्म प्रेमियों की नई पीढ़ी को उनकी विरासत से परिचित कराने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। पहले एक आडियो-विजुअल प्रस्तुति में एएनआर, राज कपूर, मोहम्मद रफी और तपन सिन्हा की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समारोह का एक अनूठा आकर्षण इन हस्तियों की समर्पित एक विशेष डाक टिकट संग्रह का विमोचन था। इन चार दिग्गजों की प्रतिष्ठित छवियों को प्रदर्शित करने वाले इस स्मारक डाक टिकट संग्रह ने सिनेमा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदानों को अमर बना दिया। एक बेहद सराहनीय बात यह रही कि इस फिल्म महोत्सव में इन महान हस्तियों के परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और फिल्म उद्योग के दिग्गजों के साथ पैनल चर्चा एवं बातचीत के सत्र की एक श्रृंखला पेश की गई। इस बातचीत ने इन दिग्गजों के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन से जुड़ी अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रसिद्ध अभिनेत्री खुशबू सुंदर और अक्किनेनी नागेश्वर राव के बेटे एवं अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी ने तेलुगु सिनेमा को आकार देने में इस कलाकार की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला। महान शोमैन के पोते एवं अभिनेता रणबीर कपूर और फिल्म निर्देशक राहुल रवैल ने राज कपूर की विरासत की पड़ताल की तथा भारतीय सिनेमा में उनके प्रेरक कार्यों और कला को सामाजिक प्रभाव के साथ जोड़ने की उनकी क्षमता का विश्लेषण किया। मुझे भारतीय संगीत में रफी के कालातीत योगदान पर विचार करने के लिए प्रसिद्ध पार्श्वगायकों अनुराधा पौडवाल एवं सोनू निगम और गायक शाहिद रफी के साथ एक गहन परिचर्चा में भाग लेने का सौभाग्य मिला। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, अभिनेता अर्जुन चक्रवर्ती और फिल्मों के विद्वान एम. मनु चक्रवर्ती ने तपन सिन्हा की कहानी कहने की उत्कृष्ट शैली और बांग्ला एवं भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव के बारे में अपने विचार पेश किए।

आइएफएफआइ ने दिग्गज कलाकारों की कलात्मक उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिए डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित फिल्मों की एक विशेष लाइनअप भी खूबसूरती से तैयार की थी। चयनित फिल्मों में देवदासु (अक्किनेनी नागेश्वर राव), आवारा (राज कपूर), हम दोनों (मोहम्मद रफी का संगीत), और हारमोनियम (तपन सिन्हा) शामिल थीं। इन फिल्मों के प्रदर्शन ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया और पीढ़ियों से चली आ रही उनकी शाश्वत अपील का उत्सव मनाया। 'कारवां आफ सांग्स' नाम की एक संगीतमय यात्रा में राज कपूर और मोहम्मद रफी के 150 गीतों के साथ-साथ एएनआर और तपन सिन्हा के 75 गाने प्रदर्शित किए गए। इस संगीतमय श्रद्धांजलि ने भारतीय सिनेमा के समृद्ध साउंडस्केप में उनके बेजोड़ योगदानों पर प्रकाश डाला। अंत में इस फिल्म महोत्सव में 'सफरनामा' नाम की एक प्रभावशाली प्रदर्शनी में इन चारों दिग्गजों के जीवन एवं करियर से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, यादगार वस्तुएं और कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और केंद्रीय संचार ब्यूरो ने अतीत एवं वर्तमान के बीच के अंतर को पाटते हुए इन हस्तियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपलब्धियों को जनता के सामने लाने का अच्छा काम किया। कुल मिलाकर इस समारोह ने न केवल उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाया, बल्कि भारतीय सिनेमा की उस स्थायी भावना को भी मजबूत किया, जिसे इन दिग्गजों ने आकार देने में मदद की। आइएफएफआइ ने यह सुनिश्चित किया कि इन सिनेमाई हस्तियों की विरासत भावी कहानीकारों और दूरदर्शी लोगों का मार्ग प्रशस्त कराती रहे।

(लेखक जाने-माने फिल्मकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुंदर भविष्य

प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के, संतति के तथा परिजनों के सुंदर भविष्य की चिंता रहती है। इस दिशा में वह अपनी बुद्धि के अनुसार संघर्ष भी करता रहता है। जहां कुछ लोग भविष्य को लेकर आश्वस्त रहते हैं, वहीं अधिसंख्य जन सदा आशंकित, चिंतित मिलेंगे। यह अंतर व्यक्ति के सोच से उत्पन्न होता है। सोच में अस्पष्टता हो तब सुख-संतुष्टि तो दूर चिंताकुल और अधीर रहना व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। इसके विपरीत प्रभु और उसकी योजना में आस्था रखने वाले को निरंतर उच्च शक्तियों से संबल मिलता रहता है।

आज की भली या बुरी स्थिति की आधारशिला बीते कल में रखी गई थी। वर्तमान तो कल संजोई गई अभिकल्पना तथा उसके अनुकूल संपादित किए गए कार्यों की स्वाभाविक परिणति है। भलाई, बुराई वापस लौट कर हमारे पास आती है। आज जो सद्कार्य में निरत हैं वे सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सोच भी कर्म है, जिन विचारों को मन-मंदिर में प्रतिष्ठित करेंगे उसी अनुरूप हमारा आचरण तथा कार्य होंगे और फल मिलेगा। कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए शास्त्र और सुधीजन धर्म और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। सद्बुद्धि होगी तो उन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं, मूल्यों और संगत को अपनाएंगे, जो हमें सम्मान से विचलित नहीं होने देते। प्रत्येक प्राणी का चेतन स्वरूप सार्वभौम चेतन की सूक्ष्म इकाई है। प्रभु का अंश होने के कारण प्रत्येक मनुष्य अथाह सामर्थ्यपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद के बीजमंत्र 'अहम् ब्रह्मास्मि' की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य ने यह संदेश दिया कि स्वयं के भीतर निहित ईश्वरीय अंश को अनुभूत कर लेंगे तो आध्यात्मिक और नैतिक रूप से जागृत हो जाएंगे। उस स्थिति में हमारे विचार, आचरण और कार्य स्वतः ही ईश्वरीय विधान की अनुयायिता में होंगे और जैसा चाहेंगे वैसा हमारा भविष्य बन जाएगा।

हरीश बड़थ्वाल

मानवाधिकारों का न हो हनन

योगेश कुमार गोयल

मानवाधिकार संगठनों ने पीड़ित मानवता के हित में सार्थक फल की है, किंतु दुनिया भर में आज भी करोड़ों लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी सिफारिशों को इसके सभी सदस्यों ने 10 दिसंबर, 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। तभी से विश्वभर में 10 दिसंबर का दिन विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मनुष्य के जीवनयापन और विकसित होने के लिए मूलभूत (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक) अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'मानवाधिकार' के रूप में स्वीकार किया गया है।

वस्तुतः 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि भविष्य में द्वितीय विश्वयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद मानवाधिकारों का संरक्षण किए जाने की ओर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन विडंबना है कि मानवाधिकारों की घोषणा के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी विश्वभर में करोड़ों लोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों से वंचित हैं। करोड़ों लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। एक अरब से भी ज्यादा लोग कम अथवा ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं। भारत में आठ करोड़ से भी ज्यादा बच्चे अपने मासूम बचपन को बाल मजदूरी की तपती भट्ठी में झोंकने की विवश हैं, जो स्कूली शिक्षा से भी वंचित हैं। देश में मजदूर महिलाओं एवं छोटे-छोटे मासूम बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किसी से छिपा नहीं है। दुनियाभर में करोड़ों लोग आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। एक अरब से अधिक लोगों को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। क्या यह सरासर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है?

क्या यह मानवाधिकार आयोग का दायित्व नहीं है कि वह इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सार्थक एवं प्रभावी कदम उठाए? भारत में करोड़ों लोग आज भी भूखे-नंगे अपनी जिंदगी के दिन जैसे-तैसे उद्देश्यहीन पूरे कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए मानवाधिकारों का कोई महत्व हो सकता है? मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के अलावा लगभग प्रत्येक देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सक्रिय हैं, लेकिन जिस गति से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उससे मानवाधिकार आयोगों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगता है।

भारत में सितंबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण करना और उनको प्रोत्साहन देना था। आयोग अपने गठन के बाद के इन 30 वर्षों में भी अपने दायित्वों को निभाने में कितना सफल रहा है, इसकी पड़ताल करने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

समाज में संवाद की अहमियत

'विमर्श की स्वायत्तता का महत्व' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में आदित्य सिन्हा ने समाज में विचार-विमर्श की स्वतंत्रता के महत्व को समझाते हुए स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने का आह्वान किया है। उनकी समीक्षा से स्पष्ट है कि संवाद का माध्यम हर वर्ग के लिए समान रूप से खुला होना चाहिए। आज के समय में विमर्श की स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक समाज के विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब तक समाज में विचारों का आदान-प्रदान स्वच्छंदता से नहीं होगा, तब तक प्रगति की दिशा में ठोस कदम उठाना असंभव है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता पर अनकहा दबाव देखा जा रहा है। गांवों और कस्बों में लोग अब भी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज कहीं न कहीं दबा दी जाएगी। सामाजिक संरचना और तकनीकी माध्यमों का दुरुपयोग इस समस्या को और जटिल बना रहा है। चर्चा का उद्देश्य अगर केवल विवाद उत्पन्न करना बन जाए, तो इससे समाधान की जगह और समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे कि छोटे स्तर पर पंचायतों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ठोस चर्चा का अभाव। जब तक जनता इन मुद्दों पर अपनी राय खुलकर नहीं रखेगी, तब तक नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं होंगी। इसके समाधान के लिए सबसे पहला कदम है स्थानीय स्तर पर संवाद का माहौल बनाना। इसके लिए स्कूल, कालेज और समाज के अन्य हिस्सों में विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, संवाद का माध्यम ऐसा हो, जहां हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। आखिरकार विमर्श की स्वतंत्रता का मतलब केवल आवाज उठाना नहीं, बल्कि सुनना और समझना भी है। यह तभी संभव है, जब समाज अपने सोच की पूर्वाग्रहों से मुक्त कर एकजुट होकर समाधान की दिशा में बढ़े।

अमरजीत कुमार, चिरैला, औरंगाबाद (बिहार)

सीरिया में हिंसा

सीरिया में जो कुछ हुआ, उससे दुनियाभर के जिहादी संगठन बेलगाम हो सकते हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बसर अल-असद को हटाने की मुहिम में विद्रोहियों को प्रधानमंत्री मुहम्मद गाजी अल-जलीली और सेना का भरपूर साथ मिला। विद्रोहियों ने जिस तेजी के साथ राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाया, उससे यही समझा जा रहा है कि हयात तहरीर अल-शाम के लड़ाकों को सेना का खुला समर्थन मिला था, कहीं कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। सीरिया की सेना ने स्वीकार किया कि अब बशर अल-असद की सत्ता का अंत हो चुका है। राष्ट्रपति बशर दमिश्क में लड़ाकों के घुसने से पहले ही सपरिवार रूस में शरण ले चुके थे और प्रधानमंत्री मुहम्मद गाजी विद्रोहियों से जा मिले। पिछले 53 सालों से असद परिवार ही सीरिया की सत्ता पर काबिज था।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

बांग्लादेश में अमेरिका की भूमिका

यह एक कटु सच्चाई है कि विश्व में अमेरिकी अपनी चौधराहट बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक तरफ तो अमेरिका भारत का दोस्त होने का दिखावा करता है दूसरी तरफ भारत की कमजोर करने के लिए नित नई चालें चलता रहता है। अमेरिका खुद को विश्व का सिरमौर बनाए रखने के लिए दूसरे देशों को कमजोर करने हेतु षड्यंत्र रचता रहता है। किस देश को कब और कैसे अस्थिर करना है और तोड़ना है, ये योजना बनाता रहता है। सीरिया का संकट उसी षड्यंत्र की एक कड़ी है। आज पाकिस्तान की हालत खराब है, वह भारत में पूरी ताकत के साथ आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। कहा जा रहा है कि इसलिए उसने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर देश को कट्टरपंथी और भारत विरोधियों के हाथ सौंपने में मदद की। जिससे भारत के लिए एक नया सिरदर्दी पैदा हो जाए। बांग्लादेश भारत का दुश्मन बन बैठा है और वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अमेरिका दूसरे देशों में विद्रोही तैयार करता है और उनके माध्यम से अस्थिरता पैदा करके सरकार गिराता है, जैसे सीरिया में हुआ।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

4.33 करोड़ छात्र भारत में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित थे, जिनमें से 79 प्रतिशत छात्र स्नातक डिग्री के लिए अध्ययन कर रहे थे, आल इंडिया सर्वे आफ हायर एजुकेशन 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार।

कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

यूजीसी की पहल

वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने की ओर बढ़ते कदम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में प्रस्तावित नए दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों को एक साथ दो डिग्री प्राप्त करने और मल्टीपल एंट्री-एग्जिट जैसे विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन आने के साथ ही छात्रों के करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित यह बदलाव युवाओं के सपनों को साकार करने के साथ ही भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने की दिशा में सहायक होगा। लिहाजा, ऐसी दूरदृष्टि वाले निर्णयों का स्वागत किया जाना चाहिए

उच्च शिक्षा नीति में परिवर्तन अक्सर समाज के विकास और जरूरतों के साथ जुड़ा होता है। यूजीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया दो डिग्री नियम छात्रों को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में नामांकन की अनुमति देता है। यह नीति शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समावेशी और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। हालांकि यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की मानसिक स्थिति और सामाजिक संरचना पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकती है।

जब छात्रों को एक साथ दो डिग्री प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पाठ्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो। क्या छात्र दोनों डिग्री में समान रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे? शिक्षण संस्थानों को सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों पर शैक्षणिक बोझ न पड़े। साथ ही, उनकी गहनता से सीखने की क्षमता प्रभावित न हो। दो डिग्री प्रणाली से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। पढ़ाई के साथ-साथ समय प्रबंधन एक चुनौती बन सकता है। साथ ही, दो डिग्री करने का खर्च छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ डाल सकता है। इस समस्या का समाधान शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। दो डिग्री प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि छात्र रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। यदि पाठ्यक्रम उद्योग की मांग के अनुसार तैयार नहीं किए गए, तो छात्रों की रोजगारपरकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यूजीसी का स्नातक पाठ्यक्रमों में लचीलापन प्रदान करने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा में एक अच्छा कदम है। यह नीति छात्रों को तीन या चार साल के पाठ्यक्रम को तेज गति से पूरा करने या आवश्यकता अनुसार पांच साल तक बढ़ाने की स्वतंत्रता देती है। इससे न केवल छात्रों का समय बचेगा, बल्कि कमजोर छात्रों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी और व्यावसायिक बनाना है, जिससे छात्र व्यक्तिगत, आर्थिक और अकादमिक जरूरतों के अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

यूजीसी का मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रस्ताव उन छात्रों के लिए एक वरदान साबित होगा, जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अब वे अपनी पढ़ाई को समय और परिस्थितियों के अनुसार जारी रख सकते हैं एवं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम शिक्षा को मजबूरी नहीं, बल्कि एक अवसर बनाने की ओर है। विषय चयन की स्वतंत्रता छात्रों की रुचि और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए, विज्ञान के छात्र कला या वाणिज्य के क्षेत्रों में अपनी रुचि का अनुसरण कर सकते हैं। यह बदलाव छात्रों को अधिक आत्मनिर्भर और सृजनात्मक बना सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि छात्रों को सही मार्गदर्शन और काउंसलिंग दी जाए, ताकि वे अपने विषय का चयन समझदारी से करें। विषयों में विविधता छात्रों को नई तकनीकों के प्रति अधिक जागरूक बना सकती है। उदाहरण के लिए, एक वाणिज्य का छात्र कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेकर फिनटेक क्षेत्र में काम कर सकता है। इस प्रकार, यह नीति छात्रों के करियर विकल्पों को व्यापक बना सकती है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प ड्रापआउट दर को कम कर सकता है। छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के बावजूद बाद में इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। यह शिक्षा को लचीला और सुलभ बनाता है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये नवाचार निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और समावेशी बनाएंगे। हालांकि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए संस्थानों, शिक्षकों और सरकार को इन चुनौतियों का समाधान खोजने की आवश्यकता है। वस्तुतः शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और समानता का सबसे सशक्त उपकरण है। यूजीसी द्वारा नेशनल एजुकेशन पालिसी (एनईपी) के तहत पेश किए गए नए नियम, इस उद्देश्य को और अधिक स्पष्टता व दृढ़ता प्रदान करते हैं। स्नातक पहल न केवल शिक्षा को अधिक लचीला और समावेशी बनाती है, बल्कि कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए छात्रों को उनके रुचि और कौशल के अनुसार विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब हर छात्र को अपनी इच्छानुसार शैक्षिक दिशा चुनने का अधिकार होगा। चाहे वह कला का छात्र हो जो विज्ञान में अपनी रुचि तलाशना चाहता हो या वाणिज्य का छात्र जो मानविकी में नई संभावनाएं देख रहा हो, यूजीसी के इस कदम ने छात्रों के लिए हर दरवाजा खोल दिया है।

आगे की राह : यूजीसी द्वारा प्रस्तावित यह नई शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो शिक्षा को लचीला, समावेशी और प्रासंगिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नियम न केवल छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा का चयन करने की स्वतंत्रता देगा, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षा को समय और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह के बदलावों से न केवल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि यह देश की समग्र विकास दर को भी प्रभावित करेगा। युवाओं को अधिक लचीलापन और बेहतर अवसर मिलने से वे राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। यह व्यवस्था युवाओं को अधिक सृजनात्मक और नवाचार के लिए प्रेरित करेगी, जो अंततः भारत को वैश्विक मंच पर एक शिक्षा और कौशल विकास केंद्र बना देगा।

यह बदलाव शिक्षा को एक आयाम से निकालकर बहुआयामी दृष्टिकोण में बदलने की कोशिश है, जो युवाओं को सशक्त करेगा और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। हालांकि इसे प्रभावी बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता होगी, लेकिन इसकी व्यापकता और दूरगामी प्रभाव से भारत का शिक्षा क्षेत्र नए मुकाम पर पहुंचेगा। इस पहल का स्वागत करते हुए हमें इसे सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में समर्पित प्रयास करने चाहिए।

वर्ष में दो बार नामांकन का अवसर सराहनीय

यूजीसी द्वारा साल में दो बार उच्च शिक्षा में दाखिला देने का प्रस्ताव भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बन सकता है। यह कदम न केवल छात्रों को अधिक अवसर और लचीलापन प्रदान करेगा, बल्कि भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, यह कदम स्वागत योग्य प्रतीत होता है, इसके दूरगामी प्रभाव और संभावित चुनौतियों पर गहराई से विचार करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को हर वर्ग और हर समुदाय तक पहुंचाना है। उच्च शिक्षा में दो बार दाखिला देने की व्यवस्था, विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, एक प्रकार से शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि कोई छात्र एक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे अगले छह महीने बाद दूसरा अवसर मिलेगा, जो उसे उसकी शिक्षा की यात्रा में निराश की बजाय एक और मौका प्रदान करेगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगी जो विभिन्न कारणों से पहली बार प्रवेश नहीं पा सके, जैसे आर्थिक समस्याएं, सामाजिक दबाव या परीक्षा के दौरान उत्पन्न हुई अनचाही परिस्थितियां। इससे एक नया विश्वास मिलेगा कि शिक्षा कोई एक बार का अवसर नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर कदम पर नया अवसर मिलेगा।

साल में दो बार दाखिला लेने की नीति छात्रों को बहुविषयक शिक्षा और करियर के विभिन्न रास्तों पर सोचने का अवसर देगी। अब छात्र एक साथ दो डिग्री प्रोग्राम कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी रुचियों और करियर के लक्ष्यों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह बहुविषयक शिक्षा प्रणाली एक ऐसे युग की ओर संकेत करती है, जहां छात्रों को सीमित विषयों से बाहर अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह प्रस्ताव छात्रों के लिए लाभकारी हो सकता है, परंतु इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रशासनिक ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि दो बार दाखिले की प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाना एक कठिन कार्य होगा। शिक्षकों की संख्या, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक कर्मचारियों की अपर्याप्त तैयारी से भी गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है।

वैसे, लचीलापन और बहुविषयकता का दुरुपयोग भी हो सकता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। यदि पाठ्यक्रम की संरचना और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता, तो यह व्यवस्था एक रूपरेखा बनकर रह जाएगी, जो छात्रों को गुणवत्ता से वंचित कर सकती है। इसलिए इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक संस्थानों में ढांचागत सुधार और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता होगी। यूजीसी का यह कदम भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के करीब लाने के लिए आवश्यक है। आज के प्रतिस्पर्धी विश्व में वैश्विक मानकों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, उच्च शिक्षा में साल में दो बार दाखिले का प्रस्ताव साहसिक कदम है जो छात्रों को लचीलापन, समावेशिता और विभिन्न अवसरों का प्रदान करेगा। लेकिन इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रशासनिक, शैक्षिक और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी। इस नीति को यदि ठीक से लागू किया जाता है, तो यह भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है और देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दे सकती है।

(कैलाश विश्नोई)

खरी-खरी

डिग्री ट्रांसप्लांटेशन

डा. प्रदीप मिश्र

मैंने चाचाजी से कहा, 'समाचार है कि इन दिनों देश में ट्रांसप्लांटेशन की फील्ड में एक बड़ी खोज हुई है।'

चाचा चौंके, 'कौन सी खोज?'

'अब इंसानों पर डिग्री ट्रांसप्लांट की जा रही है।'

'क्या कहते हो?'

'एकदम सही बात है।'

'किडनी और लीवर तो ट्रांसप्लांट होते रहे हैं। लोग अपने निखट्टू और निकम्मे जिगर के टुकड़ों को राजनीति एवं सत्ता में ट्रांसप्लांट करते रहे हैं, पर ये कौन सा नया ट्रांसप्लांटेशन आ गया?'

'चचा, उपाधि-प्रत्यारोपण की विधि अत्यंत प्राचीन है। इसमें डिग्री का प्रत्यारोपण उन शरीरों पर किया जाता है, जिनके ज्ञान-चक्षुओं को लकवा मार गया होता है। ऐसे लोगों के उपचार के लिए उनमें डिग्री ट्रांसप्लांट की जाती है। इस ट्रांसप्लांट के बाद मरीज पढ़ा-लिखा नजर आने लगता है और राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, अफसरी... किसी भी फील्ड में जाकर काम करते हुए बुलेटियों को प्राप्त कर सकता है।'

'मैंने सुना है कई बार जांच हुई है और डिग्री ट्रांसप्लांट के कई केस पकड़े गए हैं।'

मैंने कहा, 'ऐसा है चाचाजी, इसके जरिए लोग कहां-कहां और किन-किन पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसकी जांच संभव ही नहीं है, क्योंकि जो जांच करने जाएगा, उसके संच की जांच कौन करेगा?'

'ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन की गलती से भी मामला बिगड़ता है?'

'देखिए, डिग्री प्रत्यारोपण करने वाले सर्जन अनाड़ी नहीं होते। वर्षों का तजुर्बा, करतूतें और मेहनत जुड़ी होती हैं। नेता, पुलिस और गुंडे उनके संग होते हैं, ऐसे में फेल होने की गुंजाइश न के बराबर होती है।'

'कहते हैं प्रशासन सख्त हो तो डिग्री ट्रांसप्लांटेशन का धंधा बंद हो सकता है?'

'ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? लाखों लोगों के पेट जुड़े हैं इससे। अरबों का टर्न ओवर है। करोड़ों को फायदा हो रहा है। डिग्री ट्रांसप्लांट में हम दुनिया में नंबर वन हैं।'

'मतलब अब डिग्रियां ट्रांसप्लांट के जरिए ही मिलेंगी। बहुत कुछ देखा है, चलो अब इसे भी देख लेते हैं।' यह कहकर चाचा प्राणायाम करने लगे। कहते हैं, इसे करने से मन की घबराहट कम होती है।

X पोस्ट

सीरिया में असद के पतन पर नौसिखिए ही जश्न मना रहे हैं। असद की जगह सत्ता संभालने वाले आतंकी धड़े ही हैं। यही, रूस एवं इज़रायल अपनी सुविधा से सीरिया को बांट रहे हैं।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

हरियाणा में नई सरकार बने दो महीने से ज्यादा हो गए हैं, मगर कांग्रेस अब तक नेता-प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पाई। इससे पार्टी के नेताओं की गंभीरता समझी जा सकती है और फिर ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। रामपाल@raamphall

आइएनडीआइए नेताओं के बयान यही दर्शाते हैं कि भाजपा से लड़ने के लिए उनके पास न तो जज्बा है और न ही मुद्दे। कुछ है तो सिर्फ अपना राजनीतिक हित। लोकसभा चुनाव में मिला उन्हें थोड़ा फायदा हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल से आते बयानों से धुंधलाता दिख रहा है। मीनाक्षी कंडवाल@MinakshiKandwal

जार्ज सोरोस का मुद्दा कांग्रेस के लिए क्वाथौली जैसा हो गया, जिसका दायरा भ्रष्टाचार से भी परे है। जहां तक राहुल गांधी के अदाणी शब्द का सवाल है तो वह उलटा ही पड़ रहा है। आइएनडीआइए के सहयोगी भी कांग्रेस से पीछा छुड़ाते दिख रहे हैं और इस मोर्चे का थमना होना बस समय की बात है। अद्वैता काला@AdvaitaKala

जागरण जनमत कल का परिणाम

टेस्ट टीम में रोहित शर्मा कप्तान व खिलाड़ी के रूप में अपनी उपयोगिता गंवाते जा रहे हैं?

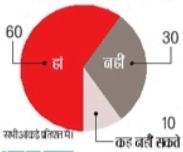

आज का सवाल

क्या सीरिया का घटनाक्रम जिहादी संगठनों का मनोबल बढ़ाने वाला है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के सर्वेक्षण का महाहै।

जनपथ

आखिर किसका है सगा कुटिल जार्ज सोरोस,
जिसकी नीयत है बुरी लुटा रहा जो कोष।
लुटा रहा जो कोष न जिसकी भाता भारत,
जो अशांति के हेतु पालता अपनी गारद!
चुभता जिसकी आंख हमारा भारत स्थिर,
कैसे खुद को दूर जार्ज से रखें अखिर!!

- ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

यूं ही नहीं 'आक्रामक' हुए ममता के तेवर

पिछले सवा 13 वर्षों के शासनकाल में मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को पहली बार आरजी कर कांड के खिलाफ हुए आंदोलन के सामने झुकना पड़ा था। उन्हें कोलकाता पुलिस आयुक्त से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंदोलन अब थम चुका है। राज्य की सड़कों पर जिस तरह जनांदोलन का ज्वार दिखा था, अब उसके निशान तक नहीं हैं। इतने झंझावात के बाद जब विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल ने सभी छह सीटों पर जीत दर्ज की तो ममता समझ गईं कि बंगाल में उन्हें टक्कर देने वाला अभी कोई नहीं है, इसलिए अब उनकी बारी है। उपचुनाव के नतीजे आने के दो दिन बाद से ही ममता ने आक्रामकता के साथ यह 'संदेश' देना शुरू कर दिया है कि पार्टी और प्रशासन पर उनका 'पूर्ण नियंत्रण' है।

पिछले 25 नवंबर से लेकर छह दिसंबर तक केवल 12 दिनों में ममता ने पार्टी के अंदर-बाहर और प्रशासनिक स्तर पर जो निर्णय लिए हैं और बातें कहीं हैं, वे बता रही हैं कि जो कुछ उनके निर्यायक से बाहर चला गया था, जिन्हें वह दुरुस्त कर रही हैं। 25 नवंबर को ममता ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक की। वहां लिए गए कई निर्णयों से यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी पर उनका 'पूर्ण नियंत्रण' है, दूसरा और कोई नहीं है। इसके तीन दिन बाद 28 नवंबर को जब रांची में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह से कोलकाता लौटीं तो एयरपोर्ट पर ही उन्होंने साफ कर दिया कि संसद में पार्टी का स्टैंड किसी व्यक्तिगत विषय का विषय नहीं है। ममता ने कहा कि संसद में तृणमूल की ओर से कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, यह तय करना किसी का व्यक्तिगत विषय नहीं है, बल्कि तृणमूल संसदीय दल फैसला करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त संसदीय दल की चेयरपर्सन

ममता बनर्जी। फाइल

वही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने संसद में मुद्दा तय करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पांच सांसदों की समिति भी बना दी और उनके नामों की घोषणा भी कर दी, जिनमें एक को छोड़कर बाकी चार उनके पुराने सहयोगी हैं। इस समिति में लोकसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता सुदीप बनर्जी, मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी, राज्यसभा में पार्टी नेता डेरेक ओ'ब्रायन, पार्टी नेता सागरिका घोष और मुख्य सचेतक नदीमुल हक शामिल हैं। समिति में उन्होंने अपने सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को नहीं रखा है। ममता ने कहा कि पहले यह समिति फैसला लेगी। उसके बाद मुझे बताएगी, फिर मैं सलाह दूंगी।

ममता की इस घोषणा के बाद तृणमूल के अंदर हलचल तेज हो गई, क्योंकि घटनाक्रम के मुताबिक पार्टी के अघोषित सेकेंड-इन-कमान व राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 27 नवंबर को दिल्ली में पार्टी सांसदों के साथ बैठक की थी। उन्होंने बैठक में संसद में उठाए जाने वाले जनता से जुड़े मुद्दे भी बताए थे। इस पर ममता ने जो तेवर दिखाए, उससे साफ हो गया है कि वह पार्टी में अपने अलावा किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके बाद दो दिसंबर को विधानसभा में पार्टी विधायकों की बैठक में भी ममता ने साफ कहा कि पार्टी में अंतिम निर्णय 'एकमात्र' वही लेंगी, दूसरा कोई नहीं। एक तरफ पार्टी संगठन तो दूसरी तरफ सांसदों से लेकर विधायकों तक को उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया कि पार्टी की सर्वेसर्वा वही हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी कई फेरबदल किए, जिसमें सीआइडी प्रमुख के पद से आर राजशेखरन को हटाना प्रमुख है। तृणमूल के ही हुमायूं कबीर जैसे नेता व विधायक तो अभिषेक को उप मुख्यमंत्री व गृहमंत्री बनाने की बातें कहने लगे थे।

अब ममता ने साफ कर दिया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और तृणमूल दोनों ही उनकी योजनाओं के मुताबिक काम करेंगे। यह बात वह खुले तौर पर एक बार नहीं, कई बार कह चुकी हैं। यहां प्रश्न यह भी उठ रहा है कि वह इतनी 'आक्रामक' क्यों हैं? इस प्रश्न के साथ ही सत्ताधारी पार्टी के संगठन में अभिषेक बनर्जी की भूमिका और भविष्य को लेकर समानांतर चर्चा शुरू हो गई है।

ममता के आक्रामक तेवर को लेकर तृणमूल के अंदर तर्क और कारण हैं। उसी तरह से प्रशासनिक हलकों में भी हैं। इस तेवर के तीन मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस बात पर दोनों पक्ष (पार्टी और प्रशासनिक वर्ग) सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, वह है आरजी कर आंदोलन के बाद हुए उपचुनावों में मिली भारी जीत। तृणमूल की पहली पंक्ति के एक नेता का कहना है कि ममता को पता चल गया है कि विधानसभा चुनाव भी हो जाए तो भी भाजपा को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इससे उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक पर पूर्ण पकड़ और तीसरा, उनकी लोकलुभावन योजनाएं हैं। यही कारण है कि ममता ने आइएनडीआइए गठबंधन के मौजूदा कामकाज पर असंतोष जताते हुए संकेत दे दिया कि वह इस गठबंधन की कमान संभालने को तैयार हैं। उनके इस तेवर के नेपथ्य में उनका यह विश्वास है कि बंगाल में मुस्लिम वोट कांग्रेस और वामपंथियों के खेमे में नहीं जाने वाला है, इसीलिए वह अब खुलकर बोलने लगी हैं। अब देखने वाली बात है कि ममता के आक्रामक तेवर आगे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में क्या गुल खिलाते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

रोग निदान की आसान राह

सस्ती-सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में बायोसिमिलर का विकास महत्वपूर्ण है। एआइ से जोड़ते हुए इसकी पूरी क्षमता का दोहन किया जा सकता है, जिससे इलाज में आसानी होगी

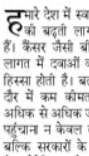

राजकुमार जैन
एआइ विशेषज्ञ

हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में उपचार की बढ़ती लागत से सभी चिंतित हैं। कैंसर जैसी बीमारियों की उपचार लागत में दवाओं की कीमत एक बड़ा हिस्सा होती है। बढ़ती दवा कीमतों के दौर में कम कीमत वाली दवाओं को अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना न केवल दवा उद्योग के लिए, बल्कि सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जेनेरिक और बायोसिमिलर्स जो कि ब्रांडेड दवाओं के संस्करण हैं, अत्याधिक कम व्यवसायक दवाओं को अधिक किफायती बनाते हैं।

बायोसिमिलर उस संदर्भ उत्पाद के समान होते हैं जिससे उनकी तुलना की जाती है, लेकिन उनमें स्वीकार्य अंतर होता है, क्योंकि ये जीवित घटकों से बने होते हैं। जबकि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की सटीक प्रतिकृति होती हैं जिनमें मूल औषधि के समान सक्रिय संघटक होते हैं। ब्रांडेड दवा के जेनेरिक अवतार की खुराक, सुरक्षा, प्रभाव, दवा प्रबंधन के तरीके, गुणवत्ता, परिणाम और चिन्हित उपयोग ब्रांडेड दवाओं के समान ही होते हैं।

एक बार जब एक दवा निर्माण एजेंसी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से विपणन प्राधिकरण प्राप्त हो जाने और विपणन शुरू कर देने के तत्पश्चात सकल वर्षों के बाद अन्य निर्माताओं को समकक्ष दवा निर्माण के संबंध में नैदानिक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चूंकि बायोसिमिलर के अणु जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें नैदानिक परीक्षणों से गुजरना जरूरी होता है। जेनेरिक दवाओं के विपरीत, बायोसिमिलर दवा के प्रत्येक पुनरावृत्ति को नैदानिक परीक्षणों से गुजरना होता है जो एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है।

मूल जैविक दवाओं के लिए पेटेंट की समाप्ति के बाद बनाए जाने वाले बायोसिमिलर उत्पाद पेटेंट के लिए पात्र नहीं होते हैं (क्योंकि अंतिम उत्पाद पहले से ही पेटेंट किए गए ज्ञात संदर्भ जीव विज्ञान के समान है) लेकिन प्रक्रिया पेटेंट के लिए तब तक पात्र हैं जब तक प्रक्रिया पेटेंट योग्यता के लिए अन्य मानदंडों को पूरा करती है।

स्वास्थ्य सेवा लागत में कमी : विकसशील देशों में बुनियादी ढांचे और विनियामक क्षमता का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापक दृष्टिकोण बायोसिमिलर को वैश्विक रूप से अपनाने में मदद करेगा, उन्नत उपचारों तक पहुंच में सुधार करेगा और स्वास्थ्य सेवा लागत को कम करेगा। विभिन्न देशों में बायोसिमिलर के लिए विनियामक ढांचों द्वारा अपनाई जा रही जटिल स्वीकृति प्रक्रियाओं और मानकीकृत दिशा-निर्देशों की कमी जैसी स्थितियों से निपटना और उच्च आय और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बीच असंगतताओं को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में स्मार्ट तकनीक, खास तौर पर एआइ और इंटरनेट आफ थिंग्स का एकीकरण बायोसिमिलर दवा विकास प्रक्रिया को बदल रहा है। वस्तुतः एआइ विशाल जैविक डाटा का विश्लेषण करके, आणविक व्यवहार का पूर्वानुमान लगाकर और परीक्षण डिजाइनों को अनुकूलित करके दक्षता और सटीकता को बढ़ाता है। यह बायोमार्कर की पहचान में लगने वाले समय को कम करता है और नैदानिक परीक्षण डिजाइन एवं डाटा विश्लेषण में सुधार करता है। इंटरनेट आफ थिंग्स बायोसिमिलर उत्पादन की निगरानी और नियंत्रण करता है एवं वास्तविक समय के डाटा के माध्यम से गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

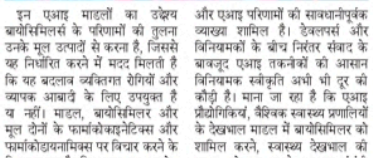

प्रतीकात्मक

इन एआइ माडलों का उद्देश्य बायोसिमिलर्स के परिणामों की तुलना उनके मूल उत्पादों से करना है, जिससे यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि यह बदलाव व्यक्तिगत रोगियों और व्यापक आबादी के लिए उपयुक्त है या नहीं। माडल, बायोसिमिलर और मूल दोनों के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स पर विचार करने के लिए व्यापक नैदानिक डाटा का उपयोग करता है, जिसमें रोगी की जनसांख्यिकी, रोग विवरण, उपचार इतिहास और परिणाम शामिल होते हैं।

कम नहीं चुनौतियां : बायोसिमिलर विकास में एआइ को लागू करने की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें उच्च-गुणवत्ता वाले बृहद डाटा सेट का संग्रहण, डाटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं और एआइ परिणामों की सावधानीपूर्वक व्याख्या शामिल है। डेवलपर्स और विनियामकों के बीच निरंतर संवाद के बावजूद एआइ तकनीकों की आसान विनियामक स्वीकृति अभी भी दूर की कौड़ी है। माना जा रहा है कि एआइ प्रौद्योगिकियं, वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों के देखभाल माडल में बायोसिमिलर को शामिल करने, स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने, उपचार संबंधी निर्णय लेने की रणनीतियों में सहायता करने और उच्च आय तथा निम्न व मध्यम आय वाले देशों के बीच की खाई को पाटने में सहायता कर सकती हैं। इसके अलावा, एआइ प्रौद्योगिकियां स्वीकृत बायोसिमिलर और जेनेरिक दवाओं की बढ़ती संख्या को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं।

चिंतन

अफ्रीकी देशों में खाद्य असुरक्षा विश्व में सर्वाधिक स्तर पर

विश्व जब विनाशक प्रवृत्ति में लिप्त है, ठीक उसी समय बढ़ी आबादी भूख का सामना कर रही है। रूस व यूक्रेन जंग जारी है, इजराइल कई मोर्चे पर लड़ रहा है, पश्चिम एशिया युद्ध, हिंसा और अराजकता से प्रभावित है, ताइवान पर चीन की तलवार लटकी है, बांग्लादेश के बाद सीरिया में तख्तापलट हुई है, दक्षिण कोरिया में स्थिति तनावपूर्ण है, क्षेत्रीय संघर्ष, सीमा विवाद के कई मामले चल रहे हैं। लग रहा है दुनिया की बड़ी ताकतें युद्ध, उन्माद व डराने के खेल में अपनी ऊर्जा झोंक रही है, जबकि अफ्रीका में भूख की दर अस्वीकार्य स्तर पर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व की एक तिहाई आबादी भूख व गरीबी से जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति-2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि अफ्रीका में खाद्य असुरक्षा विश्व के किसी भी क्षेत्र की तुलना में सर्वाधिक है। अल्पपोषण की व्यापकता 20.4 प्रतिशत (लगभग 29.84 करोड़ अफ्रीकी) है जो वैश्विक औसत की दोगुनी है। वर्ष 2015 के बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ा है। आज विश्व के अमीर व ताकतवर देशों के संस्थान अफ्रीका समेत लाचार व असहाय लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है। गरीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य साल दर साल दूर होता जा रहा है। दुनिया में आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं, गरीबी में इजाफा हो रहा है, अमीर व गरीब के बीच खाई बढ़ रही है। सूरसा की भांति बढ़ रही आर्थिक असमानता को पाटने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में संघर्ष, हिंसा व युद्ध अधिक देखने को मिलेंगे। रूस व यूक्रेन ने खरबों डॉलर जंग में जाया किया, ये पैसे अगर भूख, गरीबी व बीमारी दूर करने में लगते तो मानव कल्याण होता। ठहर कर हमें सोचने की जरूरत है कि युद्ध, हिंसा और संघर्ष से हम क्या हासिल कर रहे हैं? किस तरह के विश्व का निर्माण कर रहे हैं? जलवायु परिवर्तन और युद्ध-संघर्ष के चलते खाद्यान्न संकट और बढ़ेगा। मध्य और पश्चिम अफ्रीका में खाद्यसुरक्षा की स्थिति बदतर है, यह एक क्षेत्र-व्यापी चुनौती है। अफ्रीकी महादेश में करीब 54 देश हैं और सवा अरब से अधिक आबादी है। इस महादेश के अधिकांश देश अल्पविकसित व गरीब हैं। यूरोप, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरह अफ्रीकी महादेश काफी पिछड़ा हुआ है, व्यापक स्तर पर खाद्यान्न संकट है। अफ्रीका को कृषि व खाद्यान्न उत्पादन पर अधिक ध्यान देना होगा, इसी के साथ भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों को अफ्रीकी देशों को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करनी चाहिए। भारत समेत कई देश मदद कर भी रहे हैं, पर अफ्रीकी देशों की जरूरत अधिक है। अधिक खाद्यान्न पैदा करने से खाद्य असुरक्षा का समाधान हो सकता है। खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ इसकी पहुंच, स्थिरता, उपयोग, टिकाऊपन और आपूर्ति व प्रबंधी एजेंसी आदि मोर्चे पर भी काम करना होगा। इन उपायों से कुपोषण कम करने में भी मदद मिलेगी। अब अफ्रीका की खाद्य सुरक्षा समस्याओं को दूर करने का एक अलग तरीका आजमाने का समय आ गया है। 'एग्रोइकोलॉजी' (प्रकृति के साथ खेती) में वैज्ञानिकों के औपचारिक शोध और खेतों में प्रयोग करने वाले किसानों के अनौपचारिक ज्ञान को शामिल किया जाता है। अफ्रीका के बिगड़ते खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए 'एग्रोइकोलॉजी' एक आशाजनक तरीका है। विश्व को गरीबी उन्मूलन और मानवीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

तख्तापलट
राजेश जैन

सीरिया में विद्रोहियों की राह नहीं आसान

राष्ट्रपति असद के सत्ता से हटने के साथ ही सीरिया में बसर परिवार के शासन का अंत हो गया। विशेषज्ञों ने दमिश्क पर कब्जे की तुलना अफगान सरकार के पतन से की है, क्योंकि यहां भी सेनाओं ने बिना किसी संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी एशिया का करीब 3.35 करोड़ आबादी वाला सीरिया, भू-राजनीतिक रूप से अहम देश माना जाता है। एचटीएस के नेता अल-जुलानी ने लोगों द्वारा चुने गए काउंसिल के आधार पर संस्थाओं द्वारा शासित एक सरकार बनाने की योजना के बारे में बात की है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का वादा किया है। लेकिन यह भी कहा है कि शासन इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित होगा।

सीरिया में तख्तापलट हो गया है। इसके साथ ही वहां असद परिवार का 53 साल से चला आ रहा शासन भी खत्म हो गया। राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर रूस भाग चुके हैं। विपक्षी लड़ाकों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। लेकिन असलियत यह है कि सत्ता पर कब्जे के बाद भी विद्रोहियों के लिए देश चलाना आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए पहले विद्रोह की पूरी कहानी समझना होगी। सीरिया में बशर के पिता हाफिज अल-असद 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर ने सीरिया की सत्ता संभाली। इसके बाद से बशर सीरिया के राष्ट्रपति थे।

पश्चिमी एशिया का करीब 3.35 करोड़ आबादी वाला सीरिया, भू-राजनीतिक रूप से अहम देश माना जाता है। इसकी सीमा इराक, तुर्किये, जॉर्डन, लेबनान व इजराइल जैसे देशों से लगती है। सीरिया पर नियंत्रण अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच प्रदान करता है और पूरे क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए एक आधार प्रदान करता है। जहां तक भारत का सवाल है-भारत व सीरिया के रिश्ते अच्छे रहे हैं। 2008 में बशर भारत का दौरा कर चुके हैं। हाल में दोनों मुल्क पावर और सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। 2022 में भारत ने इसके लिए 28 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की थी। विद्रोह से इन प्रोजेक्ट पर असर होगा।

2011 में जब मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति की शुरुआत हुई। तभी सीरिया में भी असद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। इनको बेरहमी से कुचल दिया गया। इससे एक गृहयुद्ध शुरू हुआ, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों की जान गई और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। करीब आठ साल तक सीरिया के गृहयुद्ध में मोर्चे स्थिर रहे, जहां असद की सरकार रूस और ईरान के समर्थन से देश के सबसे बड़े हिस्से पर राज कर रही थी, वहीं, विभिन्न विपक्षी समूह उत्तर और पश्चिम में क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए हुए थे। सीरिया पश्चिमी एशिया में रूस का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। इसलिए रूस बशर को हर तरह की सैन्य, आर्थिक व रणनीतिक मदद देता रहा है।

इन दिनों बदले हालात में रूस और ईरान दोनों ही अपनी-अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। ईरान जहां इजरायल से लड़ाई में लगा हुआ है तो वहीं रूस भी यूक्रेन के साथ लंबे समय से युद्ध में व्यस्त है। इसके मद्देनजर सीरिया के हालात पर उनका ध्यान नहीं है और असद अकेले पड़ गए। इस बीच, सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) ने 2020 की सीजफायर के बाद 27 नवंबर को सेना से फिर जंग छेड़ दी। एचटीएस नामक यह इस्लामिक समूह, पिछले पांच साल से इदलीब प्रांत पर शासन कर रहा था। शुरू में इसने 13 गांवों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक दिसंबर को देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर अधिकार कर लिया। 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा और फिर दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा किया। दारा से ही 2011 में राष्ट्रपति बशर अल-असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी करीब 100 किमी है। इसके बाद 8 दिसंबर को दारा शहर की तरफ से विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में घुस गए

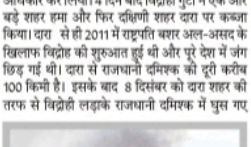

और कब्जा जमा लिया। विशेषज्ञों ने दमिश्क पर कब्जे की तुलना अफगान सरकार के पतन से की है, क्योंकि यहां भी सेनाओं ने बिना किसी संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया। सीरिया पर बारीकी से नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि जैसे ही एचटीएस के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के समूह ने राजधानी में प्रवेश किया वैसे ही राष्ट्रपति असद देश से भाग निकले। इसके बाद व्यापक भ्रष्टाचार और लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध से थकान के कारण सेना ने भी घुटने टेक दिए।

सबसे बड़ा क्षेत्र सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) के पास है, जो अमेरिका द्वारा समर्थित है और जो पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में कुर्दों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। उत्तर में, जो तुर्की के साथ सीमा लगती है, वहां अंकारा द्वारा समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना एचटीएस द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से भी बड़े क्षेत्र पर काबिज है। दमिश्क पर कब्जा करने के बाद, एचटीएस अब सीरिया में सबसे महत्वपूर्ण ताकत बन गई है और माना जा रहा है कि वह अब असद शासन द्वारा शासित क्षेत्रों पर नियंत्रण कर चुकी है। इनमें एकता आसान नहीं होगी क्योंकि सीरिया जैसे जटिल क्षेत्र में सशस्त्र समूहों के बीच नियंत्रण और प्रभाव के लिए लड़ाई चलती रहती है। दक्षिण में, स्थानीय मिलिशिया समूहों ने स्वेइदा और दारा पर नियंत्रण स्थापित किया है। सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने एचटीएस के साथ इस हमले में भाग लिया था, लेकिन उनके बीच अतीत में मतभेद रहे हैं और उनके हित अब भी अलग हैं।

राष्ट्रपति असद के सत्ता से हटने के साथ ही सीरिया में बसर परिवार के शासन का अंत हो गया। सीरिया के प्रधानमंत्री घाजी अल-जाली ने कहा कि वह शांति से सत्ता हस्तांतरण के लिए विपक्षी समूहों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीरिया के लोगों के लिए आगे क्या होगा, यह एक जटिल सवाल है। एचटीएस के नेता अल-जुलानी ने लोगों द्वारा चुने गए काउंसिल के आधार पर संस्थाओं द्वारा शासित एक सरकार बनाने की योजना के बारे में बात की है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का वादा किया है। लेकिन यह भी कहा है कि शासन इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित होगा। यह तय है कि एचटीएस दमिश्क में किसी भी राजनीतिक सत्ता में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। लेकिन क्या एसडीएफ या तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना एचटीएस-नेतृत्व वाले समूहों के साथ मिलकर एक सरकार बनाएगी, यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। इन तीन गुटों के बीच गहरी दुश्मनी है। उदाहरण के लिए, सीरियाई राष्ट्रीय सेना के सदस्यों ने एचटीएस के अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद एसडीएफ द्वारा क्षेत्रों में कई लोगों की हत्या की थी। वहीं, अमेरिका ने रविवार को सीरिया में आई एसआईएस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- सीरिया में शक्ति संतुलन बदल गया है। एसआईएस इसका फायदा उठाने की कोशिश में है लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी ओर तथ्य यह है कि विद्रोही गुट में हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) और उसके सहयोगी संगठनों को अलकायदा का समर्थन हासिल है। सुन्नी गुट एचटीएस का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल-जुलानी कर रहा है। जुलानी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद मैडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर अल-कायदा ज्वाइन कर लिया था। वह अल कायदा में अबू मुसाब अल-जरकावी का करीबी रहा। 2006 में जरकावी की हत्या के बाद जुलानी को इराक में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर 5 साल जेल रखा था। इसके बाद वह इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़ गया था। अमेरिका ने जुलानी पर साल 2017 में 84 करोड़ 67 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। अब यह देखना होगा कि विद्रोही गुट सीरिया में किस तरह की सरकार बनाती है, पर राह आसान नहीं होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

शख्सियत

विवेक शुक्ला

राज रवैल: संसद भवन लाइब्रेरी से एशियन गेम्स विलेज तक

राज रावैल जब अपनी कार से राजधानी में एशियन गेम्स विलेज, संसद भवन पुस्तकालय, दिल्ली मेट्रो निगम का मुख्यालय, ब्रिटिश उच्चायोग के फ्लैट्स, विश्व बैंक और ऐसे ही कई अन्य प्रतिष्ठित भवनों के पास से गुजरते हैं, तो वे अपने ड्राइवर को गाड़ी की गति धीमी करने का निर्देश देते हैं। इन मार्गों से बार-बार गुजरने में उन्हें अच्छा लगता है। हालांकि, वे प्रगति मैदान क्षेत्र के पास जाने से बचते हैं क्योंकि इसके दो प्रमुख स्थल - हॉल ऑफ फेम और नेहरू केंद्र - अब वहां नहीं हैं। कुछ वर्षों पहले जब पूरे क्षेत्र को नया रूप दिया जा रहा था, तब इन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने दिल्ली, भारत और दुनिया भर में कई प्रतिष्ठित इमारतों का डिजाइन किया है। राज रावैल ने पिछली 24 नवंबर को अपने दोस्तों, परिवार और छात्रों के साथ अपना 90वाँ जन्मदिन मनाया। बीते दिनों फ्रांस सरकार ने उन्हें आर्किटेक्चर के क्षेत्र में लगातार श्रेष्ठ काम करने के लिए सम्मानित भी किया। उन्हें बर्तमान में देश का सबसे प्रयोगधर्मी और बेहतरीन आर्किटेक्ट माना जाता है। राज रावैल लगातार नवाचार के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, एशियाड विलेज को लीजिये। पचास से अधिक वर्षों के बाद भी, यह अभी भी एक बिल्कुल नए, आधुनिक आवास परिसर की तरह दिखता है। इसमें 1982 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट और अन्य लोग ठहरे थे। खेलों के बाद एक आवास परिसर के रूप में इसके भविष्य के उपयोग का अनुमान लगाते हुए, रावैल ने इसे दिल्ली की गर्म जलवायु को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया, जिसमें भूनिर्माण पर बहुत ध्यान केंद्रित किया गया। उनका काम भारतीय शहरों के चरित्र को दर्शाता है, जो उन्हें उनके समकालीन और मित्र, चार्ल्स कोरिया से अलग करता है, जिनके काम ग्रामीण भारत के सार को दर्शाते हैं।

राज रावैल ने सबसे पहले वास्तुकला की दुनिया में अपनी उपस्थिति हॉल ऑफ़ नेशंस के डिजाइन से दर्ज कराई थी। तब वे 40 वर्ष के भी नहीं थे। उन्होंने तब हॉल ऑफ़ फेम और नेहरू केंद्र को डिजाइन किया था। वह साल था 1972। इस दोनों के आकर्षक डिजाइन ने तुरंत देखने वालों को आकर्षित किया था। निस्संदेह, राज रेखाल स्वतंत्र भारत की पहली पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों में से एक हैं। उन्होंने पहली बार हॉल ऑफ़ नेशंस और प्रगति मैदान में नेहरू केंद्र के अपने डिजाइनों से कला जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुख की बात है कि प्रगति मैदान के पुनर्विकास के हिस्से के रूप में दोनों को ध्वस्त कर दिया गया था। ये राजधानी की आधुनिक विरासत के शक्तिशाली प्रतीक थे, और उनके विध्वंस ने वास्तुकार समुदाय और कला प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। उनके डिजाइन न्यूयॉर्क और पेरिस के कला संग्रहालयों में प्रदर्शित किए गए थेइन्हें ध्वस्त किए जाने पर रावैल निराश हुए थे। वास्तुकारों, कलाकारों और लेखकों ने विध्वंस को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसमें ऐसी महत्वपूर्ण इमारतों को नष्ट करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि इसे ध्वस्त करने के बजाय, इसे पुनर्निर्मित और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। हॉल ऑफ़ नेशंस निस्संदेह आधुनिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति थी, विशाल और राजसी। 1971 में पूरा हुआ, यह आज के भारत से एक अलग भारत का प्रतिनिधित्व करता है - एक भारत जो संसाधन की कमी से जूझ रहा था। फिर भी, इसे भारत की स्वतंत्रता के 25वें वर्ष में बनाया गया था, और 3 नवंबर, 1972 को प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था। चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कॉर्बुसियर से प्रेरित होकर, इसे समकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता था। राजधानी के हरकोर्ट बटलर स्कूल, मंदिर मार्ग के पूर्व छात्र, राज रावैल को इस बात पर गर्व होगा कि उनके स्कूल से चार किलोमीटर से भी कम दूरी पर संसद पुस्तकालय खड़ा है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, संसद पुस्तकालय पर काम करते समय मुझे अपार खुशी और आनंद मिला। निश्चित रूप से, यह रावैल के असाधारण डिजाइन का प्रमाण है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें स्तंभों द्वारा समर्थित गुंबददार छत है। अगर एडवर्ड लुटियन्स जीवित होते, तो उन्हें भी गर्व होता। यह भव्यता और गरिमा का प्रतीक है। जाने-माने वास्तुकार बख्शीश सिंह और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में उनके छात्र कहते हैं, राज ने दिल्ली में अपनी डिजाइन की इमारतों से अपनी स्थायी छाप छोड़ी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन बना और बिगाड़ सकती है ये चीजें

संकलित
दर्शन

आम आदमी अपने दिन का पूरा समय इन दो जगहों पर बिताता है वो है घर या फिर दफ्तर में। जैसी व्यक्ति की संगति होती है वैसी ही उसकी मति हो जाती है। इसलिए जरूरी होता है कि व्यक्ति हमेशा अपने लिए सही वातावरण चुनना चाहिए, जिससे वह सही पथ पर चले। आचार्य प्रशांत के अनुसार, एक व्यक्ति किस आधार पर विवाह करता है या फिर कैसी संगति चुनता है। यह महत्व की बात है कि वह व्यक्ति किसके साथ रह रहा है। आप चाहे विवाह करके रह रहे हो या फिर बिना विवाह करके अपना जीवन व्यय कर रहा हो। ऐसे में व्यक्ति को जरूर हमेशा याद रखना चाहिए कि वह अपने जीवनसाथी का चयन किस आधार पर कर रहा है। हर एक छोटी बात जैसे कि वह व्यक्ति अब से लगातार मेरे कमरे में रहेगा? किसके शब्द लगातार पड़ने लग गए हैं तुम्हारे कानों में? इन चीजों को याद करके ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि इसी बात पर तुम्हारी जिंदगी या तो बन जाएगी या बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आचार्य प्रशांत आगे कहते हैं कि यहीं बात दफ्तर के लिए है कि दिन के आठ से दस घंटे आप किन लोगों की शक्लें देखते हैं या आर अपना बॉस बोलते हो, वो यूं ही है कोई सड़क का आदमी जो तुम्हारी जिंदगी पर अब अधिकार रखने लग गया है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यही बात दफ्तर के माहौल पर और धंधे की प्रकृति पर लागू होती है। तुम्हारी संस्था किस तरह का व्यवसाय करती है और तुम्हारे काम में किस तरह के लोग लगे हुए हैं?

धन कमाने के साथ भक्ति भी करें

संकलित
प्रेरणा

एक दिन कबीरदास अपना काम कर रहे थे। काम करते समय वे भगवान का ध्यान भी कर लेते थे। पूरे दिन कबीरदास ऐसा ही करते थे। एक व्यक्ति उन्हें कई दिनों से देख रहा था। उसने कबीरदास से पूछा कि आप भक्त हैं, लेकिन आपको अलग से भक्ति करते हुए मैंने नहीं देखा। कबीर दास जी ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। हम थोड़ा घूम आते हैं। रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई दी। वह महिला पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा मटका रखा था और वह अपनी मस्ती में गीत गाते हुए जा रही थी। उस महिला ने मटके को पकड़ा भी नहीं था। उसके सिर पर मटका स्थिर था और उसका पानी भी नहीं छलक रहा था। कबीर दास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये महिला पानी लेकर जा रही है। सिर पर मटका रखा है, लेकिन उसने मटके पकड़ा भी नहीं है और गीत गाते हुए जा रही है। इसका ध्यान अपने मटके पर है, गाने पर भी है और रास्ते पर भी है। कबीर जी ने उस व्यक्ति को आगे समझाया कि इस महिला की तरह ही मैं भी काम करते-करते भगवान का ध्यान कर लेता हूं, भक्ति कर लेता हूं। दुनियादारी के काम करते हुए भी मेरा मन भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। मैं ये काम भी कर लेता हूं और भक्ति भी कर लेता हूं। ठीक इसी तरह जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें धन भी कमाना चाहिए और भक्ति भी करते रहना चाहिए।

अंतर्मन

आज की पाती

दमघोंटू हवा के लिए जिम्मेदार कौन?

हमारा देश जो सारी दुनिया में प्रकृति प्रधान और शस्य श्यामला वसुंधरा के सौंदर्य से प्रसिद्ध है, उसकी छवि को हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषण बढ़ाकर खराब करने का काम किया है। माना कि सरकारों की गलत नीतियां प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्या हम खुद प्रदूषण से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकते? अगर हमने स्वार्थी होकर पर्यावरण को संभालने के लिए अभी भी गंभीरता नहीं दिखाई और हवा में प्रदूषण फैलाने वाले गलत कामों पर पाबंदी नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा सांस लेना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। कुदरत ने तो हमें साफ-सुथरी हवा सांस लेने के लिए दी थी, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए इसमें जहर घोलकर इसे दमघोंटू बना दिया है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

- गोविंद सोनी, दुर्ग

ट्रेंड

सोनिया गांधी को बधाई

श्रीमती सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। तमाम लोग तमाम तक दशकों की अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है। सोनिया सोमवार को 78 साल की हो गयीं। -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारत एआई क्रांति के लिए तैयार

भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि एक जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था भी है जो नवाचार एवं तकनीकीता के लिए नए मानक स्थापित कर रही है। भारत परिवर्तनकारी एआई क्रांति के लिए तैयार है जाएगा। -नितिन प्रसाद, चेयरमैन भाजपा

अर्जुन जी शुभकामनाएं

अरुण अर्जुन जी. आपके साथ से बहुत अनिमृता हूं. हम सभी आपके धैर्य और प्रतिभा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं. आप हम सभी को प्रेरित करते रहें. आपकी निरंतर सफलता के लिए मेरी प्रार्थना और शुभकामनाएं। -अभिनव बच्चन, अभिनेता

राम की भूमिका मेरा सपना

मैं उस कहानी का हिस्सा बन राम की भूमिका निभाकर बहुत खुश हूं। यह मेरा एक सपना है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें सब कुछ है। यह सिखाती है कि भारतीय संस्कृति क्या है - परिवार और परिवारों का रिश्ता। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। -रणबीर कपूर, अभिनेता

करंट अफेयर

अफ्रीका का बदतर होता खाद्यान्न संकट

अफ्रीका में भूख की दर अस्वीकार्य रूप से ऊंची है और यह बदतर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति-2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि अफ्रीका में खाद्य असुरक्षा विश्व के किसी भी क्षेत्र की तुलना में सर्वाधिक है। अल्पपोषण की व्यापकता 20.4 प्रतिशत (लगभग 29.84 करोड़ अफ्रीकी) है जो वैश्विक औसत की दोगुनी है। वर्ष 2015 के बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन और संघर्ष भी इस समस्या के कारक हैं। लेकिन मेरी राय में इस चुनौती के मूल में कुछ और मौलिक बातें निहित हैं: उत्तर-औपनिवेशिक काल के बाद यह मार्गदर्शन करने के लिए अपनाई गई विचारधारा और योजनाएं कि अफ्रीका कैसे खाद्यान्न का उत्पादन करेगा और कुपोषण कम करने का प्रयास करेगा। हालांकि, पूरे महाद्वीप में खाद्य असुरक्षा की दरें अलग-अलग हैं और मध्य और पश्चिम अफ्रीका में ये बदतर हैं, यह एक क्षेत्र-व्यापी चुनौती है। मैं अफ्रीकी खाद्य सुरक्षा और कृषि का विशेषज्ञ हूं। एक नई किताब 'डिकोलोनाइजिंग अफ्रीकन एग्रीकल्चर : फूड सिक्योरिटी, एग्रोइकोलॉजी एंड द नीड फॉर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन' में मैंने तर्क दिया है कि अफ्रीका के बेहतर भरण-पोषण के लिए निर्णय लेने वालों और दान दाताओं को ये करना चाहिए।

ऑफ बीट

भविष्य के आहार में आयरन जैसे तत्वों की कमी होगी

आयरन की कमी दुनिया भर में पोषक तत्वों की कमी के सबसे आम रूपों में से एक है। जैसे-जैसे लोग वनस्पति आधारित आहार अपनाने पर विचार करेंगे, आयरन की कमी का खतरा बढ़ने की संभावना होगी। इससे पता चलता है कि अगर खाद्य उत्पादन और आपूर्ति के 'वैश्विक पैटर्न' नहीं बदले, तो 2040 तक आहार में आयरन की कमी हो सकती है। इसका मतलब है कि हमें अपने आहार में आयरन की कमी को दूर करना होगा। ब्रेड और अनाज जैसे सामान्य खाद्य पदार्थ सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ में पहले से ही अतिरिक्त पोषक तत्व हैं। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में अक्सर उच्च मात्रा में फाइबर और फाइटेट होते हैं, जो शरीर की आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देते हैं। साबुत अनाज, नट, बीज, फलियां और पत्तेदार साग जैसे वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में आयरन भरपूर होता है और पशु-स्रोत वाले खाद्य पदार्थों में मौजूद आयरन की तुलना में कम आसानी से अवशोषित होता है। मिश्रित आहार यानी सब्जियां, अनाज और पशु-स्रोत वाले खाद्य पदार्थ जैसे कुछ मछलियों, लाल मांस या मुर्गे का सेवन आयरन अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है।

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 10 दिसंबर 2024

भारत बेफ़िक्र नहीं

सीरिया में रविवार को जिस तरह से इस्लामी विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया और राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़ने को मजबूर हुए, वह अप्रत्याशित तो है ही, पूरे पश्चिम एशिया के लिए अनिश्चितता के एक नए सिलसिले की शुरुआत साबित हो सकता है। इस प्रकरण में कई ऐसे पहलू हैं, जो भारत की चिंता से सीधे तौर पर जुड़ते हैं।

एक सेकुलर शासक | चाहे राष्ट्रपति बशर अल-असद हों या उनके पिता हाफिज अल-बशर, दोनों निरंकुश माने जाते रहे, लेकिन सीरिया में दोनों ने सेकुलर नीति अपनाई। उनके शासन काल में इस्लामी कट्टरपंथियों पर अंकुश बना रहा। अब उनकी जगह काबिज हुए इस्लामी विद्रोहियों के संभावित रुख को लेकर दुनिया भर में आशंकाएं हैं। सीरिया में उनकी वजह से ISIS जैसे आतंकवादी समूह के फिर से सिर उठाने का डर पैदा हो गया है। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आने वाले दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी तत्वों की सक्रियता बढ़ने वाली है।

सीरिया: विकल्प की तलाश

करमीर पर सपोर्ट | सीरिया के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते भले ही ज्यादा प्रगाढ़ न हुए हों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों एकजुट रहे हैं। यही नहीं, बशर अल-असद ने कश्मीर के सवाल पर हमेशा भारत का साथ दिया। यहां तक कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भी सीरिया ने कहा था कि यह भारत का आंतरिक मामला है। देखना होगा कि बदले हालात में सीरिया के रुख में किस तरह का और कितना बदलाव आता है।

तुर्किये का प्रभाव | विद्रोही गुटों को हासिल तुर्किये के कथित समर्थन को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सीरिया के नए निजाम की नीतियों पर उसका प्रभाव दिखेगा। अच्छी बात यह है कि तुर्किये के साथ भी भारत के रिश्ते में पिछले कुछ समय में सुधार देखा जा रहा है। जहां कश्मीर पर उसके रुख में नरमी आई है, वहीं भारत ने भी ब्रिक्स में तुर्किये की एंट्री को रोकने का प्रयास नहीं किया।

अखंडता और संप्रभुता | सीरिया के घटनाक्रम पर भारत ने जिस तत्परता से अपना रुख स्पष्ट किया, वह भी काफी कुछ कहता है। 24 घंटे के अंदर ही विदेश मंत्रालय ने सीरिया की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि मसले का हल निकालने की प्रक्रिया न केवल शांतिपूर्ण बल्कि सीरिया की अगुआई वाली और समाज के सभी तबकों के हितों का ध्यान रखने वाली होनी चाहिए। जाहिर है, सीरिया मामले से जुड़े अपने हितों को लेकर भारत संवेदनशील और गंभीर है।

धूप-छांव

शोर में सुकून

प्रणव प्रियदर्शी

शादियों का सीजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहेंगे इसमें कौन सी खास बात है। नाच-गाना, धूम-धड़ाका भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। बात सही है, लेकिन हंसी-खुशी के चौतरफा विस्फोट का यह माहौल इस मायने में भी सुकूनदायी साबित होता है कि अगर कोई अपने लिए एक खामोश कोना चाहता है, तो वह आसानी से मिल जाता है। कानफाड़ संगीत पर नाचते-गाते लोगों के समुद्र में किसी को आपकी खामोशी सुनने की फुरसत नहीं होती। लिहाजा आप निश्चिंत होकर अपने गम में डूब सकते हैं। कोई आपकी निजता भंग नहीं करेगा।

मशहूर एक्टर चार्ली चैपलिन ने कभी कहा था कि वह बारिश में रोना पसंद करते हैं क्योंकि तब कोई उनके आंसुओं को देख और पहचान नहीं पाता। हालांकि बारिश को अगर आंसुओं के संदर्भ में देखा जाए तो शादी-ब्याह के माहौल से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जब पूरा आसमान ही जार-जार रो रहा हो, पूरी दुनिया उसके आंसुओं से तर-ब-तर हो रही हो तो किसी एक व्यक्ति, चाहे वह चार्ली चैपलिन ही क्यों न हो, उनके आंसुओं का हिसाब कौन रखे। मगर क्या यह सही होगा कि अपने आंसू निकालने के लिए हम पूरी कायनात के रोने का इंतजार करें! अव्वल तो उस इंतजार में यह खतरा है कि अपने आंसू भीतर ही भीतर ऐसे सूख जाएं कि बारिश के लाख भिगोने पर भी अंदर का वह सोता न फूटे। यानी जब बारिश हो रही हो तो चाहकर भी आपके आंसू न निकलें। दूसरी बात यह कि अपना गम सुरक्षित ढंग से व्यक्त करने के लिए तमाम लोगों के गम में डूबने की कल्पना भी असाहज करने वाली है। अपना गम अपने कंधों पर उठाने की तमीज और काबिलियत तो हममें होनी ही चाहिए। लेकिन गम का बोझ क्या सचमुच ऐसा होता है कि हम अकेले, महज अपने कंधों की मजबूती के सहारे उसे ढोते चल सकें? ऐसा होता तो हम रोने के लिए अपने आसपास भरोसेमंद कंधों की जरूरत महसूस नहीं करते। सच्चाई यही है कि हम सबको ऐसे कंधों की जरूरत महसूस होती है जिस पर अपने कमजोर पलों में सिर रखकर रो सकें।

तो, सारी आदर्शवादी भावनाएं एक तरफ और चार्ली चैपलिन की सच्चाई में डूबी बातें एक तरफ। लेकिन, उनकी बात को सही ठहराने के लिए इतना धुआं-फिराकर कान क्यों पकड़ना। सीधा सा सवाल यह है कि बारिश को आसमान के आंसू ही क्यों मानना। वह तो पानी और ठंडक को तरसती दुनिया के लिए जिंदगी का उपहार है। तो चार्ली चैपलिन का यह मतलब भी हो सकता है कि जब आपके आसपास की पूरी दुनिया राहत और सुकून में डूबी हो, उम्मीदों में नहा रही हो, आप अपने गम के सागर में चुपचाप एक डुबकी लगा सकते हैं बिना यह चिंता किए कि कोई आपके गीले कपड़ों पर आपसे सफाई मांगेगा।

बोल वचन

चंपू नहीं है चंपू

राहुल पाण्डेय

चंपू को सब लोग जितना चंपू समझते हैं, असल में चंपू उतना चंपू नहीं होता। आजकल तो जिसे भी चिढ़ाना हो, या बड़े प्रेम से जिसको इज्जत का तिया-पांचा करना हो- कोई भी उसे झट से चंपू कह देता है। बल्कि चंपूगिरी नाम से भी शब्द चल निकला है, आमतौर पर जिसका अर्थ चंपी यानी तेल-मालिश या चमचागीरी से भी जोड़ा जाने लगा है। इन्हीं अर्थों में नेताजी, बॉस और बीवी का चंपू से लेकर विचारधारा के चंपू होने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। दरअसल, चंपू का असल अर्थ जान लेंगे तो आईना भी ऐसा करने से बचेगा। पहली बात यह कि चंपू कोई देशज नहीं, बल्कि संस्कृत से आया शब्द है। यहां इसका अर्थ गद्य और पद्य को मिलाकर बना मिश्रित काव्य है, जिसकी जड़ हमें अथर्ववेद में मिलती है। फिर त्रिविक्रम भट्ट ने 'नलचंपू' लिखा, जिसे संस्कृत में चंपूकाव्य का पहला उदाहरण माना जाता है। उनके बाद भोजराज ने 'रामायण चंपू' लिखा था। मैथिलीशरण गुप्त की 'यशोधरा' को भी चंपूकाव्य कहा जाता है। काव्यकला से निकलकर जब यह चंपू ब्रज में पहुंचता है तो पहाड़ी धान बन जाता है। वहां से बुंदेलखंड पहुंचता है तो चंपू लौटा बन जाता है। बुंदेलखंड से अवध आते ही चंपू सुंदर और विचित्र हो जाता है, तेल-मेल चुपड़कर बहुत सुंदर बनने की बेढंगी कोशिश करने लगता है। अवध में चंपू की बिगड़ी शक्ल मिथिला जाकर फिर से कवितामय हो जाती है, क्योंकि वहां भी चंपू का अर्थ गद्य पद्यमय काव्य के तौर पर लिया जाता है। क्या लगता है, इतने सारे चंपुओं के लिए इंग्लिश में कोई एक शब्द होगा? जाहिर है, ही ही नहीं सकता!

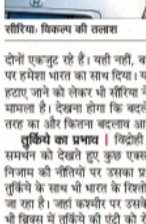

Subrata Char

लोकसभा चुनाव में मिली जीत का टॉनिक हरियाणा और महाराष्ट्र की हार से बेअसर हो गया

किस पार्टी की ग़लती से बिखर रहा I.N.D.I.A.

राज कुमार सिंह

विपक्ष अपने आचरण से संदेश दे रहा है कि उसे विरोधियों की जरूरत नहीं, वह खुद ही आत्मघात कर सकता है। लोकसभा चुनाव में BJP को अकेले दम बहुमत से वंचित करने से उत्साहित विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. में, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हार के बाद जैसा हाहाकार नजर आ रहा है, वह उसकी सख्त पर ही सवालिया निशान लगाने वाला है।

ममता ने जताई इच्छा | अपने सांसद कल्याण बनर्जी के बाद अब खुद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री रहते हुए ही विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. का नेतृत्व करने की इच्छा सार्वजनिक रूप से जता दी है। मराठा दिग्गज शरद पवार ने ममता को नेतृत्व क्षमता का प्रमाणपत्र देने में भी देर नहीं लगाई।

शिवसेना के रुख पर एतराज | महाराष्ट्र में तो SP नेता अबू आजमी ने I.N.D.I.A. के स्थानीय संकरण महायुति से इस आधार पर अलग होने का फैसला भी सुना दिया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बाबरी विध्वंस की बरसी पर खुशी जताने वाला विज्ञापन दिया। वाला साहेब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना का हिंदुत्व और अयोध्या मुद्दे पर स्टैंड जगजाहिर रहा है। जब दो साल से भी ज्यादा समय तक उद्धव महायुति सरकार के मुख्यमंत्री रहे, तब भी उनके स्टैंड में किसी बदलाव का संकेत नहीं था। ऐसे में सवाल है कि चुनाव बाद महायुति की सरकार बनी होती, तब भी क्या अबू आजमी उससे बाहर जाने का फैसला करते?

न्यूनतम साझा कार्यक्रम नदारद | नरेंद्र मोदी की सरकार और BJP की बढ़ती ताकत से त्रस्त जो विपक्ष एकता के लिए मजबूर हुआ था, उसके संभावित बिखराव के कारण भी उसके अंदर ही निहित है। पिछले साल 17-18 जुलाई को ही दो दर्जन विपक्षी दलों का गठबंधन I.N.D.I.A. अस्तित्व में आ गया था, पर वह कभी जमीन पर दिखा क्या? जिस बैठक में इसका नामकरण किया गया, उसी में संयोजक, संचालन समिति और साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय करने की भी बात हुई थी, पर सोलह महीने में उतना भी नहीं हो पाया।

सहयोगियों को सीटें नहीं | अविश्वास की नींव पर विश्वास की बुलंद इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। इसका पहला संकेत पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से ही मिल गया था, जब जीत के अति आत्मविश्वास पर सवार कांग्रेस ने I.N.D.I.A. के अन्य घटक दलों को प्रतीकात्मक रूप से भी कुछ सीटें देना उचित नहीं समझा। ऐसे में सामूहिक चुनाव प्रचार के उलट SP और AAP जैसे घटकों ने बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार भी उतारे। कारण तो कई रहे होंगे, पर परिणाम तीनों राज्यों में कांग्रेस की पराजय के रूप में ही सामने आए। दूसरा बड़ा संकेत इस साल के शुरू में मिला, जब विपक्षी एकता के सूत्रधार नजर आ रहे नीतीश कुमार और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी पाला बदल कर BJP नीत NDA में चले गए।

क्या है संकेत

- नेतृत्व को लेकर शुरू हुई तू-तू मैं-मैं
- BJP से सीधी लड़ाई में कांग्रेस पस्त
- सबको साथ लेकर चलने में नाकामी

हार से ढहता मनोबल | राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के झटके से संभली कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में सहयोगियों और छोटे दलों के साथ सीटों का बंटवारा किया। 370 या 400 पार के नारे के बीच जिस तरह BJP 240 सीटों पर ही ठहर गई, उसे I.N.D.I.A. की सफलता भी माना जा सकता है। उसका असर संसद के पहले सत्र में भी दिखा, पर अक्टूबर में हरियाणा और नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली हार से वह मनोबल ढहता नजर आ रहा है।

विपक्षी एकता की कमजोर कड़ी | बेशक दो राज्यों की हार बड़ा सदमा है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस अपने ही सहयोगियों के भी निशाने पर नजर आ रही है, उसकी अपनी कहानी है। दरअसल, चुनाव-दर-चुनाव यह धारणा पुष्ट होती जा रही है कि कांग्रेस मन से नहीं, मजबूरी में अन्य दलों को साथ लेती है। यह भी कि कांग्रेस ही विपक्षी एकता की सबसे कमजोर कड़ी है, जो अपने ऐतिहासिक पराभव काल में भी, स्वर्णिम अतीत में जीती हुई ज्यादा- से-ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है। हालांकि BJP से सीधे मुकाबले में जीतने का उसका रेकॉर्ड सबसे खराब है।

परस्पर अविश्वास | बेशक, विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा तीन राज्यों- हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना - में कांग्रेस की ही सरकार है, पर शेष राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस के बजाय अन्य छोटे और क्षेत्रीय दल, BJP को ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर दल कांग्रेस के पराभव से ही मजबूत हुए हैं। इसलिए कांग्रेस की एक हद से ज्यादा मजबूती उन्हें अपने भविष्य के लिए भी शुभ नहीं लगती। परस्पर अविश्वास और शह-मात ही विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की सबसे बड़ी विडंबना है, जिससे उबरने की कोई सूरत नजर नहीं आती।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

नोट का गड्डी को 'अपुन काईच' बोलने का

दीपक पाचपोर

तुम जानताए भिड़, अपुन का कंट्री का भीतर अस्सल प्रॉब्लेम बोले तो कऊन सा होताए? तुम बोलेगा 'सफाई का'। यईसा नईं। फिर तुम थोड़ा मुंडी खुजाके सोचेगा अऊर कहेगा कि 'महंगाई का'। ब्हादर, वो भी नईं। पैले तुम जित्ता शर्ट-प्यांट का सिलाई दिएला उत्ता प्राइस का भीतर आज तुमकूं रेडीमेड दो-दो ब्रांडेड शर्ट-प्यांट मिलने कूं सकताए। जिदर भी जायेंगा, सेल चालू दिखताए।

अबी अपुन मेन प्वाइंट पे आएंगा। अपुन का मुल्कुक का अस्सल प्रॉब्लेम होताए कि इदर कोई भी खूश रहने कूं नईं सकताए। रस्ता पे चलेगा तो कहेगा कि खड़ा भोत होताए। रिपेयरिंग करने का वास्ते उसपे काम होएंगा तो कहेंगा कि गंदी भौत उड़ताए। नाली नईं होएंगा तबी कहेंगा कि घर का गंदा पानी रस्ते पे आएला। इदर का पब्लिक कूं कोई भी बी खूश नईं करने कूं सकताए। बोले तो भगवान बी नईं खूश करने को सकताए। तुम सिद्धि विनायक जाके बच्चा का मन्नत मांगेगा। बच्चा ही जाएंगा तबी बोलेगा कि उसकूं अच्छा स्कूल मंगताए, गणपति बाप्पा! अच्छा स्कूल से पढ़ाई करके निकलेगा तबी तुमकूं उसका वास्ते अच्छा कॉलेज, फिर नोकरी, फिर अच्छा छोकरी का साथ सादी का मन्नत मांगेगा। जबी वो बी सिद्धि विनायक दे देंगा तबी तुम फिर से लाइन में लगके कहेगा, उसकूं बी जल्दी छोकरा होना मांगताए, बाप्पा!

अपुन कूं इसका मस्त जवाब बाबूराव दिएला। वो कहताए- 'ब्हादर, आईसाए कि इदर सबको पईसा मांगताए। वो बी रोकड़ा। तुमारा किस्सा भी बैंक बैलेंस होन दो। हात में नईं तो खीसा का भीतर हजार-दो हजार कैसा होएंगा वो दिखेंगा। तुमारा इंप्रेशन पड़ताए। कोई शेठ नईं तो भगी हाफिस, कचैरी, हॉटेल-विटेल से बाहेर निकलेंगा तबी कोई उसकूं पहचानेंगा बी नईं। पन जोईच हात में दस-बीस का पत्ती फड़काएंगा तबी गेटकीपर से लेके पार्किंग वाला उसकूं सलाम करेंगा। बैंक बैलेंस दिखेंगा नईं। रोकड़ा दिखताए। जईसा बैंक लॉकर का भीतर किता भी दागिना होएंगा पन कोई हवा बी नईं लगेंगा, पन तुमारा कोई उंगली में छोटा सा अंगूठी भी होएंगा वो दिखेंगा।'

AI image

खाली पीली

अपुन बाबूराव कूं कहेला, 'तुम इत्ता बोल बच्चन करताए, पन डायरेक्ट प्वाइंट पे नईं आताए।' वो बोलताए- 'इदर अक्खा पब्लिक रोकड़ा का वास्ते येड़ा हुएला। तुम जिदर बी जाएंगा अबी उदर ऑनलाइन पेमेंट का मथमथ। गारमेंट बी कैताए कि ऑनलाइन पेमेंट करने का। पन जबी वो गारमेंट चलाने वाला पार्टी इलेक्शन लड़ेगा तबी रोकड़ा बाटेंगा। पोस्टर-बैनर होन दो कि वर्कर का चा-पानी का खरचा, खुर्ची, पंडाल का पेमेंट करने का वखत आएंगा तबी नगदी देगा। तुम 'नोट फॉर वोट' सुनेलाए पन कबी 'फोनपे फॉर वोट' सुनेलाए क्या? नईं न?

तबी अपुन कूं समज नईं आताए कि सीट का नीचे से नोट का गड्डी निकलताए तबी उसकूं कोई बी आंग पे कार्पेकूं नईं लेताए? सब बोलताए कि 'अपुन का नईं, अपुन का नईं'। पब्लिक से सीखने का। जबी ट्रेन नईं तो बस में सौ-पचास का नोट मिलेंगा तबी चार लोग 'अपुन काए, अपुन काए' कैके मारामारी करेंगा। भिड़ तुमकूं खुश होना मांगताए कि तुमारा सीट का नीचे से गड्डी निकलताए। उदर सब वहा-वहा आदमी बैठताए। अऊर का सीट का नीचे से रोकड़ा किदरकूं निकला? इस करके बोलताए कि इदर का पब्लिक कूं खुश करना भौत प्रॉब्लेम होताए। अक्खा वखत रोकड़ा का वास्ते रोएंगा पन रोकड़ा तुमारा सीट का नीच्चू आएंगा तबी बी बोम मारेंगा। कॉलर ऊंचा करके बोलने का, 'बेस अपुन का होताए!' इजात बढ़ेंगा।'

शेयर करें अपने अनुभव

आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-'खाली पीली'

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

दुख का बड़ा कारण है दूसरों के जीवन में झांकना

राजिन्दर सिंह महाराज

अपनी जरूरत से ज्यादा जमा करना या हर समय ज्यादा से ज्यादा पाने के बारे में सोचते रहना एक प्रकार का लोभ है। अपनी सहायता के लिए या अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अधिक मात्रा में चाहना सकारात्मक हो सकता है, लेकिन लोभ तब पैदा होता है जब उसे पा लेने के बाद भी मन नहीं भरता। जब ज्यादा पाने की इच्छा हमारे मन पर इस कदर हावी हो जाती है कि हम कुछ और सोच नहीं पाते तो भी वह लोभ में बदल जाती है।

इच्छा करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जब इच्छित वस्तु को पाने के लिए किसी भी हद तक जाकर सभी सीमाएं और नियम तोड़ देते हैं, तो वह लोभ हो जाता है। कई बार किसी चीज को पाने के लिए दूसरों से हड़प लेते हैं, तो भी वह लोभ होता है। लोभी होने का मतलब है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला। जब लोभ अपना बदसूरत चेहरा उठाता है तो हमारा मन ऐसे विचारों से भर जाता है, जो हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है। जो संतुष्टि हम पहले महसूस करते थे, जो शांति का अहसास दिलाती थी, उसकी जगह हम लगातार ज्यादा से ज्यादा पाने की योजनाएं बनाने लगते हैं।

अधिकार जताने की भावना, लोभ का ही एक प्रकार है। हम उस चीज पर मालिकाना हक जताना चाहते हैं, जिसके हम मालिक नहीं होते। हमें लगता है कि हमारा उस चीज पर अधिकार है, जो असल में हमारी नहीं होती है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा भौतिक चीजें जमा करना चाहते हैं। कुछ लोग किसी अन्य इंसान पर हक जमाना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम उन पर नियंत्रण करने लगते हैं, जबकि हमारा खुद पर नियंत्रण खत्म होने लगता है। ऐसा हम अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहकर्मियों या कर्मचारियों- किसी के भी साथ कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति पर मालिकाना भावनाएं रखते हैं तो हर समय जांचते रहते हैं कि वह क्या कर रहा है और उसकी जिंदगी में दखल देते रहते हैं। इससे हम अपने मन की शांति को भंग कर देते हैं और दूसरों के जीवन में भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

ध्यान और अभ्यास लोभ को दूर करने में मदद करता है। सांसारिक चीजें पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे हम ईमानदारी से काम करें या किसी से वह चीज छीन लें, जिसका हमें हक नहीं है। लेकिन जब हम जो कुछ भी पा चुके हैं, उससे और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा मन खराब हो जाता है। इससे हम संतुष्ट नहीं होते। लेकिन ध्यान-अभ्यास करते समय हम मन की खुशियों से जुड़ते हैं, जो कभी खत्म नहीं होतीं। यह आनंद अनंत है और हम जितना चाहें उतना इसका अनुभव कर सकते हैं।

ध्यान-अभ्यास हमें ऐसे आंतरिक स्रोत के संपर्क में ले जाता है, जिससे हमें ये खुशियां मिलती हैं, जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं। वह हमें उससे कहीं अधिक खुशियों से भरपूर कर देता है, जो हमें बाहरी सुंदरता, ताकत या दौलत से मिल सकती है। तब हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को पाने की लालसा नहीं रखते, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारे पास आध्यात्मिक खजाने मौजूद हैं।

इस्राइल ने जो किया, बचाव में किया

Israel

हमारी गाज़ा में मौजूदगी स्थायी नहीं

इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर के ऐलान के बावजूद संघर्ष जारी है। इस बीच सीरिया में भी बड़ी उथल-पुथल मच गई है। भारत में इस्राइल के राजदूत **रूवेन अजर** ने सीरिया और इस्राइल के रिश्तों के भविष्य से लेकर हिज्बुल्लाह और हमास तक कई मुद्दों पर **पुनम पाण्डे** से बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश :

■ इस्राइली फौज अब सीरिया-इस्राइल के बीच बने बफर जोन में है। सीरिया और इस्राइल के बीच रिश्तों का क्या भविष्य है?

1974 में डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था। तब इस्राइल और सीरिया के बॉर्डर पर बफर जोन बना था। इसे खाली होना था और उसमें सिर्फ UN ऑब्जर्वर की ही मौजूदगी होनी थी। लेकिन उसका कई बार उल्लंघन हुआ। इस्राइल को इन हालात से निपटना था। ISIS और कई एफिलेटेड ग्रुप उस एरिया में मौजूद थे और वे इसका फायदा उठा रहे थे कि वहां कोई निर्दोष मौजूद नहीं थी। ये फोर्सेस भी इस्राइल पर अटैक कर रही थीं। कई बार असद आर्मी ने बागियों पर मिसाइल, मोर्टार दागे, जो इस्राइल की सीमा में आकर गिरे। उससे सबक लेते हुए हमने बचाव के रास्ते अपनाए। हम बफर जोन में गए ताकि डिफेंसिव पोजिशन ले सकें, यह अस्थायी है। हम तब तक रहेंगे, जब तक सीरिया में स्थिति साफ नहीं हो जाती और यह पता नहीं चलता कि सीरिया का कंट्रोल किसके पास जाता है और उसका इस्राइल को लेकर क्या रवैया होने वाला है।

■ कुछ दिनों पहले ही इस्राइली डिफेंस फोर्सेस ने स्टेटमेंट दिया कि असद सरकार हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रही है। तो क्या वहां बगावत होना कहीं न कहीं इस्राइल के फेवर में है?

यह इस सेंस में इस्राइल के फेवर में है या गुड न्यूज है कि अगर ईरान और लेबनान के बीच सड़क मार्ग बंद होता है तो ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल असद रिजीम और लेबनानी हिजबुल्लाह को बड़ी संख्या में सामान और आधुनिक हथियार पहुंचाने में नहीं कर पाएगा। अभी नहीं पता कि सीरिया में नई सरकार का क्या नेचर होगा।

■ इस्राइल और लेबनान के बीच सीजफायर की क्या स्थिति है?

इस्राइल सीजफायर लागू करने की कोशिश कर रहा है उन जगहों पर जहां इसका उल्लंघन हो रहा है और उन जगहों पर भी, जहां लेबनान की सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। सीजफायर एग्रीमेंट के अनुसार, लिटानी रिवर के साउथ में हिजबुल्लाह की कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने पाया कि इसका उल्लंघन हुआ है तो हमने एक्शन लिया। हम स्थिति को उस तरह खराब नहीं होने देंगे, जैसे 2006 से पहले हुआ था। इसलिए इस्राइली फोर्स कड़ाई से काम कर रही है।

■ इस्राइली डिफेंस फोर्सेस का बयान आया कि अगर सीजफायर टूटा तो वह लेबनान में अंदर तक घुसेंगे। क्या इससे तनाव नहीं बढ़ेगा?

इस्राइल ने जो एक्शन लिया, वह डीएस्केलेशन की दिशा में लिया। हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को हमने सीमित किया। हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लिया। हमने ईरान के अटैक का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इसका असर यह हुआ कि सीरिया में अपोजिशन ने स्थिति का फायदा उठाया। हिजबुल्लाह कमजोर पड़ रहा है, तो उन्होंने असद सरकार को गिराया। हम आशा करते हैं कि यह लेबनान के लोगों में कुछ सेंस लेकर आएगा।

■ गाजा में मानवीय संकट को लेकर इस्राइल की काफी आलोचना भी हुई है। एमनेस्टी इंटरनैशनल ने कहा कि गाजा में इस्राइल नरसंहार कर रहा है...

यह बकवास है। दुर्भाग्य से कुछ ह्यूमैनिटेरियन NGO, इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने अजेंडा को लेकर बायस्ड हैं। उन्होंने नरसंहार की परिभाषा भी बदलने की कोशिश की। इस्राइल ने जो किया यह अपने बचाव में किया। दुर्भाग्य से सिविलियन कैजुअल्टी हुई, क्योंकि हमास लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस्राइल की गाजा में मौजूदगी अस्थायी है। हम खतरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जब देखेंगे कि स्थिति अब सुरक्षित है तब हम उस सरकार या फोर्स को पावर ट्रांसफर करेंगे, जो रीजन में शांति लाने की इच्छुक होगी।

■ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत के स्टैंड को इस्राइल में कैसे देखा जा रहा है?

हम इस तथ्य से उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मरक्षा के अधिकार की बात कही। भारत और इस्राइल दोनों ने रैडिकल व इस्लामिक टेररिज्म झेला है। यह कॉमन चैलेंज है। तथ्य यह है कि एक देश है जो हमें समझता है जिसने आतंकवाद झेला है, यह पॉस्टिलकली कहता है कि हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, यह एनकरेजिंग है।

विशुद्ध राजनीति

इंटरव्यू

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ अमेरिका को समझें

9 दिसंबर का लेख 'सीरिया में असद की विदाई के पीछे कौन' पढ़ा। अमेरिका किसी का सगा नहीं हो सकता। वह अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक तरफ तो वह भारत का दोस्त होने का दिखावा करता है और दूसरी तरफ हमारे हितों को चोट पहुंचाने से भी बाज नहीं आता। याद कीजिए तो पिछले बरसों में भारत को लेकर कई अमेरिकी रिपोर्ट में खिलाफ बातें कही गईं। बांग्लादेश संकट के पीछे भी अमेरिका बताया जा रहा है। व्हॉशिंगटन के लिए सबसे जरूरी उसके अपने हित हैं। इसके लिए उसे किसी देश पर हमला करने, वहां अस्थिरता फैलाने, तख्तापलट करने में भी संकोच नहीं। हम अमेरिका से दोस्ती बढ़ाएं, पर उसे समझते हुए।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानें बाग

■ बातों की भिड़ंत

26 नवंबर को 'खाली-पीली' कॉलम में प्रकाशित लेख 'भयभय खल्लास, अबी काम ये लगने का' में भारतीय समाज में लोकप्रियता, क्रिकेट, मूवी और राजनीति के बीच के संबंधों को रोचक तरीके से लिखा गया है। लोग क्रिकेट और मूवी जैसी चीजों पर नजर गड़ाए रखते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है, तब राजनीति की बात आती है। चुनाव और राजनीति जुबानी जंग के खेल हैं और इसमें भी दर्शकों को असली खेल जैसा ही आनंद आता है।

खाली पीली

विजय पाटिल, ईमेल से

■ टूटता विश्वास

विद्रोहियों और सरकार के बीच हुई जंग ने सीरिया को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि विद्रोहियों ने राजधानी सहित कई शहरों पर कब्जा कर लिया। सिया और सुन्नी के बीच बिगड़ते रिश्तों और असद शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष ने यह स्थिति उत्पन्न की। सीरिया संकट ने साबित कर दिया है कि जब सरकार और जनता के बीच विश्वास टूटता है, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।

कांतिलाल मांडोत, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

हिसार के गांव में अब शादियों में
नहीं बजेगा डीजे - एक खबर
- तो क्या ढोल-नगाड़े वाली के दिन
लौट आए है।

अभिजीत गुप्ता

[illegible]

सम्पादकीय

सीरिया में बढ़ता संकट, पड़ोसी देशों के लिए भी सबक

आखिरकार विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और वहां के शासक बशर अल असद को देश छोड़ने के लिए विवश किया। विद्रोहियों के संगठन हयात तहरीर अल-शाम के लड़ाकों ने जिस बिजली की गति से सीरिया की राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया, वह हैरान करने वाला है।

इस संगठन के लड़ाकों ने 27 नवंबर से अपना अभियान शुरू किया था और पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा जमाया और इसके बाद एक के बाद एक शहरों को अपने नियंत्रण में लेते गए और अंततः दमिश्क भी जा पहुंचे। अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक उन्हें जिस तरह किसी कड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, उससे यही स्पष्ट होता है कि सीरिया की सेना कमजोर पड़ चुकी थी।

सीरिया के लोगों ने विद्रोही लड़ाकों का जिस उत्साह के साथ स्वागत किया, उससे यह भी पता चलता है कि बशर अल असद काफी अधिक अलोकप्रिय हो गए थे। इस अलोकप्रियता का कारण उनका सीरिया पर निर्मम ढंग से शासन करना रहा। सीरिया लगभग 13 सालों से अस्थिरता और अशांति से जूझ रहा है।

वह विद्रोही गुटों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ताकतों का अखाड़ा भी बना हुआ है। एक ओर जहां रूस और ईरान असद सरकार के समर्थन में खड़े थे, वहीं दूसरी ओर तुर्किये, अमेरिका और इजरायल असद सरकार का पतन चाह रहे थे। इस बार ईरान और रूस असद की सहायता इसलिए नहीं कर सके, क्योंकि जहां ईरान इजरायल के साथ उलझा हुआ है, वहीं रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा ईरान के लिए बड़ा झटका है। इसमें संदेह है कि सीरिया में अपने समर्थन वाली सरकार के पतन के बाद ईरान चैन से बैठेगा। भले ही विद्रोही बिना किसी बड़े रक्तपात के सीरिया में काबिज हो गए हों, लेकिन वहां स्थायी रूप से शांति कायम होने के आसार इसलिए कम हैं, क्योंकि तुर्किये सीरिया को अपने ढंग से चलाना चाहता है। इसके अतिरिक्त सीरिया के एक हिस्से पर काबिज कुर्द लड़ाके अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि तुर्किये उन्हें अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। सीरिया में अशांति और अस्थिरता का खतरा इसलिए भी दिख रहा है, क्योंकि हयात तहरीर अल-शाम में वस्तुतः वही लड़ाके हैं जो कभी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ थे। यदि यह संगठन सीरिया में शांति एवं स्थिरता लाने के बजाय अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करता है तो इजरायल और कुर्द विद्रोहियों के साथ उसका टकराव तय है। अब पश्चिम एशिया के देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हयात तहरीर अल-शाम का सीरिया पर कब्जा जिहादी तत्वों के मनोबल को बढ़ाने का काम न करे। चूंकि इसकी भरी-पूरी आशंका है कि सीरिया में जो कुछ हुआ, उससे दुनिया भर के जिहादी संगठन बेलगाम हो सकते हैं इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे संगठनों की सक्रियता है ही, बांग्लादेश में भी वे सिर उठाते दिख रहे हैं।

बीमा सखी योजना 2024 - ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मील का पत्थर साबित होगी

शिवम सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत की बौद्धिक क्षमता कार्यकुशलता की प्रतिष्ठा को, रेवड़ी योजनाओं के प्रहार से हमला किया जा रहा है, या यूं कहें कि रेवड़ी प्रचलन बौद्धिक क्षमता को जंग लगाने का काम कर रहा है क्योंकि स्वाभाविक है जिसको घर बैठे डीबीटी से पैसा मिल जाए 5 किलो प्रति मेंबर अनाज और परिवार को 1 किलो दाल मिल जाए तो वह अपना दिमाग क्यों खापाएगा इसका सटीक उदाहरण मैंने प्रैक्टिकल देखा कि झाड़ के पत्तों की पत्तल बनाने वाली एक महिला कारीगर से मैंने जो पत्तल 40-50 रुपए बंडल मिलती थी, वह 150 रुपए बंडल देने की बात मैंने कही तो भी,उन्होंने बनाने से इंकार किया क्योंकि उसे लाडली बहन योजना से 1500 रूपए प्रतिमाह व राशन का अनाज मिलने की बात कही तो स्वाभाविक रूप से वह पत्तल बनाकर अपनी कौशलता में दिमाग खपाकर क्योंदिखाएंगे। यह बात करीब करीब हर क्षेत्र में महसूस किया जा रही होगी जिसका सुद्धारित रूप अब 9 दिसंबर 2024 से शुरू हुई बीमा सखीयोजना से देखने को मिल सकता है, इस योजना को रेवड़ियों से काफी दूर रखा गया है, यानें ग्रामीण महिला मेहनत कर, घूम घूम कर, एलआईसी की बीमा पॉलिसी लेगी तो उसे उसका मेहनताना 7 से 218ज़ार तक होगा तथाप्रोत्साहन राशि 2100 अलग मिलेगी वो भी उसे प्रक्रिया से एलआईसी बीमा एजेंट बनना होगा।

हालांकि बीमा एजेंट अभी कोई भी बन सकता है, यह कोई नई बात नहीं है परंतु यह विशेष योजना केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए है व स्वाभाविक रूप से उन्हें अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें शासकीय कर्मचारियों की बीमा पॉलिसीयां दिलाई जाएगी,जिला स्तरपर उन्हें पॉलिसी मिलने का एक अदृश्य सपोर्ट किया जाएगा जिससे एक तीर से दो निशान होंगे, एक तो ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर पॉलिसी मिलेगी वह अपनी आय बढ़ाएगी, दूसरी ओर सरकारी प्रतिष्ठान एलआईसी को वित्त का साधन जनरेट होगा जो नेशनल लेवल पर विनियोग कर विज़न 2047 के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यानें यह अप्रत्यक्ष रूप से विज़न 2047 में भरपूर कारगर सिद्ध होगा। चूँकि 9 दिसंबर 2024 को माननीय पीएम ने हरियाणा के पानीपत में दोपहर 2 बजे बीमा सखी योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सखी बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है,यह योजना एलआईसी ने संचालित की गई है, तो आए हुए पैसों से लॉन्ग टर्म विनियोग बढ़ेगा भारत के विकास के नए-नए अध्यायों के दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इसआर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,बीमा सखी योजना रेवड़ी से कोसों दूर बल्कि कौशलता के बलपर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

साथियों बात अगर हम बीमा सखी योजना को जानने

की करें तो, आज 9 दिसंबर को महिलाओं के लिए सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है,इस योजना का नाम है बीमा सखी योजना,इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा एलआईसी की बीमा सखी योजना को शिक्षित महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत लोगों में वित्तीय समझ विकसित करने और बीमा की अहमियतसमझाने के लिए 10 वीं महिलाओं को 3 साल तक ट्रेंड किया जाएगा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए शुरू की गई इस योजना में महिलाओं को 7,000 से 21,000 रुपये तक हर महीने दिए जाएंगे. योजना की शुरुआत में महिलाओं को हर महीने 7000 रुपये दिए जाएंगे, तो वहीं दूसरे साल में यह राशि 1000 रुपये कम करके 6000 रुपये कर दी जाएगी, तो तीसरे साल में 5000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। वहीं इसके अलावा महिलाओं को 2100 रुपये का अलग से योगदान दिए जाएगा तो साथ ही जो महिलाएं अपने बीमा के टारगेट पूरा करेंगी उन्हें अलग से कमीशन भी दिया जाएगा।

साथियों बात अगर हम बीमा सखी योजना को महिला सशक्तिकरण व रोजगार की ओर कदम बढ़ाने की करें तो, जैसा इस स्कीम का नाम है बीमा सखी योजना यानि इसमें महिलाओं को बीमा से जुड़े काम के लिए सक्षम बनाया जाएगा,इस योजना के जरिए महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी नियुक्त किया जाएगा यानें उनको एलआईसी का एजेंट बनाया जाएगा।योजना में जुड़ने के बाद महिलाएं लोगों का बीमा कर सकेंगी। सरकार की इस स्कीम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को खासा लाभ होगा,ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार के मौके सामान्य तौर पर काफी कम होते हैं, ऐसे में सरकार की इस स्कीम से इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।माननीय पीएम ने सोमवार 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत से इस योजना का उद्घाटन किया।भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, अलग-अलग तबकों से आने वाले लोगों के लिए सरकार की अलग-अलग योजनाएं होती हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास करती रहती है महिलाओं के हित के लिए भी सरकार की कई योजनाएं होती हैं।

साथियों बात अगर हम बीमा सखी योजना को समझने की करें तो, केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है,इसी कड़ी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना लाई है।इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश महिलाओं के सशक्त बनाना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाना है पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि 'बीमा सखी योजना' भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की एक पहल है। बीमा सखी योजना के जरिए 10वीं पास कर चुकी 18 से 70 साल की उम्र की महिलाओं के सशक्तीकरण को बल मिलेगा। इस योजना के तहत फाइनेंशियल लिटरेसी और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को पहले 3 सालों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और वजीफा दिया जाएगा।एलआईसी एजेंट से लेकर डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का मौका ट्रेनिंग के बाद महिलाएं एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और ग्रेजुएट बीमा सखियों को एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर की भूमिका में काम करने का भी अवसर मिलेगा।पीएम ने भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किया, योजना के पहले फेज में 35 हजार महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर रोजगार दिया जाएगा। बाद में 50 हजार और महिलाओं को योजना में लाभ दिया जाएगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बीमा सखी योजना 2024 - ग्रामीण महिलाओं कोआत्मनिर्भर बनने में मील का पत्थर साबित होगी।बीमा सखी योजना से ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार के अवसर बढ़ाकरआर्थिक सपोर्ट से उनका जीवन खुशहाल होगा।बीमा सखी योजना रेवड़ी से कोसों दूर कौशलता के बल पर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने सटीक योजना है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप यहां दिनांक तथाये तो पूरा फायदा उठा सकते हैं कि आपके जीवन के किसी क्षेत्र के लिए क्या है, तथा आपके जिससे बुरा होगा और दूसरी तरफ, आपको किस बात से सावधान रहना चाहिए। तथा ये किसी तरह के उपाय हैं और मंत्रित मुद्रा को सुनकर तथा सावधानी और उनके मंतव्य को समझ लेंगे, क्योंकि पारम्परिक तरीके ही हैं, तथा यह सावधानी हमें संतुष्ट और बाधाओं से मुक्त प्रदान करेगा

मेष
घर के सदस्यों के स्वास्थ्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी।

वृष
शत्रु पस्त होंगे। सुख के साधन जुटेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। लंबे समय से रुके कार्य सहज रूप से पूर्ण होंगे। कार्य की प्रशंसा होगी। दुष्टजनों से दूरी

मिथुन
दूसरों के कार्य में दखल न दें। बड़ों की सलाह मानें। लाभ होगा। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। मानसिक बेचैनी रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। धैर्य रखें।

कर्क
धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कुबुद्धि हावी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। मित्रों से संबंध सुधरेंगे।

सिंह
व्यय होगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। अज्ञात भय रहेगा।

कन्या
शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। शुभ समय। घर में अतिथियों का आगमन होगा।

तुला
लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। बेवजह कहासुनी हो सकती है। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। व्यापार ठीक चलेगा। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा।

वृश्चिक
प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। बेवजह कहासुनी हो सकती है। कानूनी अड़चन दूर होगी। व्यापार में वृद्धि होगी।

धनु
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में उच्चाधिकारी सहयोग करेंगे। शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। दुःखद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी।

मकर
निवेश शुभ रहेगा। प्रसन्नता रहेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी अपने के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। शारीरिक कष्ट संभव है।

कुंभ
व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। पुराना रोग परेशानी का कारण रह सकता है।

मीन
कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शत्रु पस्त होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल होंगे। निवेश शुभ रहेगा।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

श्री मुक्तानन्द अग्रवाल (आई.ए.एस)

नमस्कार मित्रों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री मुक्तानन्द अग्रवाल जी।28 जनवरी सन 1985 को जोधपुर में जन्में मुक्तानन्द राजस्थान के बेस्ट कलक्टर्स की श्रेणी में गिने जाते हैं। बेहद शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं अग्रवाल सर। अलवर व दौसा कलक्टर शिप के दौरान लोगों को इनकी शानदार कॉरशैली देखने को मिली इसके साथ ही कोटा कलक्टर के रूप में जब बाढ़ आई तो पूरे गाँव को बचाने में इनकी महती भूमिका रही। एम.ए(संस्कृत) बी.ए(इतिहास) एम.फिल-कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा में आए और आज संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली जैसे बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं।निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली। पंजीयक, सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।आयुक्त, उद्योग एवं विनियोजन एवं अप्रवासी भारतीय निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू।जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक। उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान, जयपुर। विशेष कर्तव्य अधिकारी, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर। उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद बारां रहे । इसके अलाव आयुक्त, दिल्ली.मुम्बई औद्योगिक गलियारा, जयपुर। विशेष सचिव, सरकार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर राजस्थान, जयपुर। प्रबंध निदेशक, राजसिको जयपुर। अध्यक्ष, जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर आदि पदों पर अतिरिक्त कार्य भार भी संभाला। शानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

मन्नत के डोरे..

मन्दिरों में या पीर बाबाओं की मजारों पर ऐसे सीन आपकों अधिकतर मिल ही जाऐंगे। ये मन्नत के डोरे हैं ये बता रहे हैं कि भगवान तू तो नहीं चाहिए पर तुझसे बहुत कुछ चाहिए। मजिदों में नमाज अता होती है,चर्च में प्रार्थना सभाए होती हैं,गुरूद्वारों में अरदास होती है और मन्दिरों में भगवान की पूजा-अर्चना होती है। लेकिन ऐसा लगता है उस ऊपर वाले को याद नहीं किया जाता बल्कि जैसे बाजार जाने से पहले एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक वैसे ही ऊपर वाले से डिमांड की जाती है। शायद मन्नत का डोरा इस बात का जीता-जागता गवाह है कि उसे नहीं बल्कि उससे मांगा गया है। वैसे भी हमारी आरती में ईश्व को पाने का जिक्र कहीं नहीं है बल्कि आरती क्या ऐसा लगाता है कि जैसे डिमांड हो रही हो कोई। सुख सम्पत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का और लास्ट में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इमानदारी से पूछिये कि क्या सच में उसको उसका सा अर्पण कर रहे है या भगवान की धूपबत्ती के पंसारी बाजार से धी ला रहे हैं। उस धी का नाम भी पूजा वाला धी है जो कि भगवान के लिए ही है, देशी है, शुद्ध है बस एक ही कमी है सस्ता है इसलिए हमारे खाने लायक नहीं है ज्यादा है तो भगवान के भोग का हलवा बन सकता है। ठीक ऐसे ही मज्जिदों में नमाज के लिए कहा जाता है कि देश में अमन चैन के लिए दुआए कर रहे हैं एक बार दिल पर हाथ रखकर पूछिए जरा कितना अमन चैन कायम है। पीर बाबाओं की मजार पर बंधे मन्नत के डोरे या मन्दिरों में बंधे नारियल इस बात का सुबूत है कि उस महाशक्ति को नहीं मांगा जा रहा है बल्कि उससे मांगा जा रहा है।

रूपक शर्मा
संपादकीय प्रभारी
अलवर संस्करण

विशेष आलेख

नये आयामों को जाग्रत करेगा- 'अंतरराष्ट्रीय विश्व ध्यान दिवस'

सुनिल महला

भारत निरंतर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। योग ही या ध्यान, भारत ने युगों-युगों से विश्व को ऐसा कुछ दिया है, जो शायद ही विश्व के किसी अन्य देश ने संपूर्ण विश्व को दिया हो। शायद इसीलिए भारत को विश्व गुरू की संज्ञा दी जाती रही है। यह बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस' को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद अब 21 दिसंबर के दिन को विश्व 'विश्व ध्यान दिवस' के रूप में मनाने जा रहा है। सच तो यह है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बाद अब भारत ने विश्व को एक और भारतीय विधा-'ध्यान' से लैस किया है। उल्लेखनीय है कि ध्यान मनुष्य के विकारों का शमन करता है। वास्तव में, ध्यान का अर्थ है, अपने भीतर नए आयाम जागृत करना।जीवन का मूल उद्देश्य खिलने की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना है, जहां तक पहुंचना संभव है। ध्यान खिलने के लिए खाद्य पदार्थ है। ध्यान से सकारात्मक स्थितियों का निर्माण किया जा सकता है और आज के तनाव और अवसाद भरे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नये जोश का सहज ही समावेश किया जा सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि ध्यानस्थ रहकर नकारात्मक मनोभावों पर नियंत्रण का अभ्यास होता है और इससे क्रोध, काम, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। आज के इस युग में स्वयं को ढूंढने के लिए ध्यान ही एकमात्र विकल्प है। ध्यान, मनुष्य को यंत्रवत होना छोड़ना सिखाता है और शान्ति, संयम(धैर्य) अहिंसा को जन्म देता है। कहना गलत नहीं होगा कि ध्यान अनावश्यक विचारों को मन से निकालकर शुद्ध और आवश्यक विचारों को मस्तिष्क में जगह देता है। यह मनुष्य की आत्मिक शक्ति का विकास करता है और मनुष्य के तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक सम्बन्ध बनाता है और उसे बल प्रदान करता है। बहरहाल, पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र(यूएन) महासभा ने भारत द्वारा सह-प्रायोजन एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस (वर्ल्ड मेडिटेशन डे) घोषित किया है।भारत के साथ लिकटेंस्टीन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको और अंडोरा उन देशों के मुख्य समूह के सदस्य थे, जिन्होंने 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'विश्व ध्यान दिवस' शीर्षक वाले प्रस्ताव को शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित करने में अहम भूमिका निभाई। वास्तव में यह अत्यंत काबिले-तारीफ है कि भारत ने विश्व कल्याण की दिशा में यह एक बेहतरीन कदम उठाया है। युगों युगों से भारत का लक्ष्य समग्र मानवता का कल्याण रहा है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपने सभ्यतागत सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम' को लेकर चलता है और संपूर्ण विश्व को सदैव सकारात्मकता, शान्ति, संयम, आपसी सहयोग, मेलजोल, सौहार्द और सद्भावना का अनूठा संदेश देता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अपने सभ्यतागत सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम' को लेकर चलते हुए हाल ही में कोरु समूह के अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाए जाने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि 21 दिसंबर का दिन शीतकालीन अयनांत या संक्रांति का दिन होता है, जो भारतीय परंपरा के अनुसार उत्तरायण की शुरुआत होता है, जो विशेष रूप से आंतरिक चिंतन और ध्यान के लिए वर्ष के एक शुभ समय की शुरुआत होती है। बहरहाल, विश्व ध्यान दिवस के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति को विश्व स्तर पर एक और बड़ी कामयाबी है। हाल ही में शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को सभी देशों ने भारत के विश्व ध्यान दिवस के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए एक तरफ से इसके पक्ष में वोटिंग की। बहरहाल, अंत में यही कहूंगा कि ध्यान मनुष्य मस्तिष्क और मनुष्य के समग्र कल्याण और विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। कहना गलत नहीं होगा कि ध्यान अपने अस्तित्व की खूबसूरती को जानने का एक तरीका है। पाठकों को बताता चलूं कि असल में ध्यान का अर्थ है, अनुभव के स्तर पर यह एहसास होना कि आप कोई अलग इकाई नहीं हैं - आप एक ब्रह्मांड हैं। सच तो यह है कि ध्यान का अर्थ है- पूरी तरह से बोध में स्थित होना। वास्तव में पूरी तरह से मुक्त होने का यह(ध्यान) अकेला मार्ग है। कहना गलत नहीं होगा कि एक दशक में जिस तरह से योग दिवस एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, जिसके कारण दुनिया भर में आम लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस भी मानवता के समग्र कल्याण के संबंध में एक नायाब तोहफा व एक अनूठा आयाम बनकर उभरेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड़ खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

हिन्दुस्तान
1936

पड़ोस की चिंता

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद पहली बार शीर्ष स्तर के किसी भारतीय अधिकारी ने ढाका की उड़ान भरी। निस्संदेह, इसके गहरे निहितार्थ हैं। वहां के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखते हुए नई दिल्ली अब तक खामोश थी, क्योंकि भारत दूसरे देशों की संप्रभुता का हमेशा से सम्मान करता रहा है, बांग्लादेश तो फिर भी मित्र देश है। उम्मीद थी, वहां हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह वहां कट्टरपंथ का दबदबा बढ़ता दिख रहा है और हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके उपासना स्थलों में तोड़-फोड़ की जा रही है, ऐसे में बहुत जरूरी हो गया था कि ढाका को भारतीय चिंताओं से अवगत कराया जाए और वहां अल्पसंख्यकों के जान-माल व उपासना स्थलों की सुरक्षा तय करने संबंधी कोशिशों का जायजा लिया जाए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी का ढाका दौरा वहां भारत-विरोधी दुष्प्रचार को थामने के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ बांग्लादेश के भीतर की, बल्कि कुछ बाहरी ताकतें भी वहां भारत के खिलाफ विष-वमन में जुटी हैं।

यह अकारण नहीं है कि हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद अचानक पाकिस्तान का ढाका प्रेम उमड़ आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ न सिर्फ सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी दोनों देशों की ओर से कई बड़े फैसले किए गए हैं। दशकों बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 25 हजार टन चीनी निर्यात करने का करार किया है, तो वहीं ढाका की अंतरिम सरकार कराची से चिटगांव के बीच मालवाहक जहाज की आवाजाही को पहले ही हरी झंडी दिखा चुकी है। अब उसने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा शर्तों में छूट की घोषणा की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया खालिदा जिया का पाकिस्तान के प्रति झुकाव कोई ढकी-छिपी बात नहीं है। ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की उनसे मुलाकात के बाद अंतरिम सरकार की इस मेहरबानी को समझा जा सकता है। मगर जिस तरह वहां फौज के रिटायर्ड अधिकारियों को आगे करके दबाव की राजनीति की जा रही है, वह भारत के लिए जरूर चिंता व चिंतन का विषय होना चाहिए।

भारतीय उप-महाद्वीप के हित में यही है कि ढाका में जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार कायम हो, जो उसे कट्टरपंथ के बजाय लोकतंत्र के रास्ते पर आगे ले जा सके।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे अवसर अक्सर आते हैं, जब राष्ट्रों को अपने हितों के आलोक में रिश्तों को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ती है और वे करते हैं। बांग्लादेश के उदय में भारत की भूमिका न बांग्लादेशियों से छिपी है और न ही दुनिया से। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को वहां के आम अवाम ने बिल्कुल बिसरा दिया है। आज भी वहां फरहाद मजहर जैसे कई बुद्धिजीवी हैं, जो मोहम्मद यूनुस की कारगुजारियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। इसलिए वहां की मजहबी अदावत को केंद्र में रखकर कटु प्रतिक्रिया करने के बजाय बंगाली अवाम को पाकिस्तानी जुल्म व ज्यादतियों की याद दिलाने की जरूरत है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मंचों से वहां जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दबाव बनाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोकतंत्र की वापसी हो सके। ज्यादा लंबी अवधि तक कार्यवाहक सरकार बनी रही, तो इसे पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। भारतीय उप-महाद्वीप के हित में यही है कि ढाका में जल्द से जल्द एक लोकप्रिय सरकार कायम हो, जो उसे कट्टरपंथ के बजाय लोकतंत्र के रास्ते पर आगे ले जा सके।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

10 दिसंबर, 1949

हेग समझौते का स्वागत

संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली ने हेग समझौते के लिए जिम्मेदार पक्षों- डचों, हिन्देशियावासियों और हिन्देशिया के लिए संयुक्त राष्ट्रीय कमीशन को बधाई दी है और एक स्वतंत्र सार्वभौम राज्य के रूप में संयुक्त हिन्देशिया जनतंत्र की निकट भविष्य में ही राही स्थापना का स्वागत किया है। जनरल असेम्बली का यह प्रस्ताव बिल्कुल निर्दोष था और उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी। किन्तु रूस के साथी राष्ट्रों ने इसका भी विरोध किया। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा कि समझौते का स्वागत करने के बजाय जनरल असेम्बली को यह आदेश देना चाहिए कि डच फौजें हिन्देशिया से तुरन्त हटा ली जायें। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने जनरल असेम्बली के सामने एक जवाबी प्रस्ताव भी पेश किया था, किन्तु अध्यक्ष ने उसे अनियमित करार दे दिया। इस प्रस्ताव में हिन्देशिया के राजधन्दियों को रिहा करने, हिन्देशियावासियों के विरुद्ध चलाई जाने वाली कथित आतंकवादी हलचलों को बन्द करने और हिन्देशिया की समस्या को हल करने के लिए मौजूदा कमीशन की जगह सुरक्षा कौंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त ११ राष्ट्रों का एक कमीशन नियुक्त किये जाने की मांग की गई थी। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा समझौते के जरिये हिन्देशिया का सामन्ती विभाजन कर दिया गया है और विदेशी एकाधिकारी संगठनों द्वारा उसके प्राकृतिक साधनों को हस्तगत करने की छूट दे दी गई है। उसके अनुसार बिना डचों की पूर्व स्वीकृति के हिन्देशिया अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा घरेलू और वैदेशिक मामलों में कोई अंतिम कदम नहीं उठा सकेगा। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने जो चित्र प्रस्तुत किया, यदि वह ठीक होता तो हिन्देशिया के नेता इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ लोग... प्रत्येक वस्तु को संतुलित रूप में देखने के बजाय एक ही रंग में देखना ज्यादा पसन्द करते हैं।

हम यह नहीं कहते कि हेग समझौता एक आदर्श समझौता है। हिन्देशिया के लोगों के पास अगर इतनी फौजी ताकत होती कि वे डचों को पूरी तरह परास्त कर सकते, तो उन्हें हेग जाकर डचों से समझौते की बातचीत करने की जरूरत न होती। जब दो पक्षों को शांतिपूर्वक किसी झगड़े का निपटारा करना होता है, तो दोनों ही पक्षों को कुछ न कुछ रियायत देनी पड़ती है।

सीरिया के सामने सुलगते सवाल

यहां स्कैन करें

अश्विनी महापात्रा | प्रोफेसर, जेएनयू

वहां 50 साल से भी ज्यादा समय बाद तानाशाही का अंत हुआ है। लोग देश में और बाहर बहुत खुशी मना रहे हैं, मगर इस खुशी का इतिहास, वर्तमान और भविष्य क्या है?

सीरिया में तख्तापलट के बाद लोगों को उस अरब स्प्रिंग या क्रांति की याद आ रही है, जो दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू हुई और धीरे-धीरे पूरे अरब में फैल गई थी। अरब दुनिया में जितने बड़े तानाशाह थे, सबके अंत की शुरुआत हुई। पहले ट्यूनीशिया के तानाशाह गए, इसके बाद मिस्र में हुस्नी मुबारक को जाना पड़ा। लीबिया में कर्नल गद्दाफी और यमन के अली अब्दुल्लाह सालेह भी इतिहास हो गए। सीरिया में तानाशाह बशर अल असद इसलिए बच गए, क्योंकि रूस और ईरान उनके पक्ष में खड़े हो गए।

तब साल 2011 में सीरिया में तानाशाह बसर अल असद के खिलाफ जो शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था, वह वास्तव में लोकतंत्र के लिए था। सरकार ने अत्याचार किया, तो कुछ महीनों में आंदोलन हिंसक हो गया। इससे सुन्नी उग्रपंथी समूह, अल-कायदा इत्यादि सक्रिय हो गए। जब आंदोलन शांतिपूर्ण था, तभी असद को समन्वय के साथ चलना शुरू कर देना चाहिए था, पर वह तो तानाशाह थे, उन्होंने सत्ता साझा करने से इनकार कर दिया। असद ने पूरी निर्ममता से आंदोलन को दबाने की कोशिश की और आंदोलन हिंसक होता चला गया। अपने बचाव के लिए उन्होंने रासायनिक हथियार भी इस्तेमाल किए। इसका असर हुआ कि 50 लाख से ज्यादा सीरियावासी विस्थापित हुए, दूसरे देशों में जाने को मजबूर हुए। गृह युद्ध ने सीरियाई समाज को रसातल में पहुंचा दिया।

दरअसल, सीरिया अंदर से ही बंटा हुआ है। वहां की 74 प्रतिशत आबादी सुन्नी है, जबकि सत्ता अलावी या अलवाइज समूह के पास है, जो आबादी का 12 प्रतिशत है, यह संप्रदाय शिया के ज्यादा करीब है। गौर करने की बात है, ईरान असद के समर्थन में आ गया, रूस ने भी सहयोग किया। हिजबुल्लाह से भी मदद मिली और असद बचते रहे। साल 2019 तक आते-आते असद की सत्ता मजबूत हो गई। असद के समर्थन में रूस की सैन्य मौजूदगी सीरिया में बनी रही। असद के लिए खराब दौर तब शुरू हुआ, जब 7 अक्तूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया। यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि पश्चिम एशिया दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हर चीज परस्पर जुड़ी हुई है।

जब हमास के हमले के बाद इजरायल आक्रामक हुआ, तो उसने हिजबुल्लाह पर भी हमला बोल दिया। हिजबुल्लाह लेबनान में भी है और सीरिया में भी। इजरायल को लगता है कि अगर सीरिया की सरकार गिर जाए, तो हिजबुल्लाह की ताकत घट जाएगी। इसलिए पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह के नेतृत्व को खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह का जो बेस था, उसे भी हवाई हमले से इजरायल ने खत्म करना शुरू कर दिया।

असद की हुकूमत को कमजोर पड़ते देख, विद्रोहियों ने फिर पांव पसारने शुरू कर दिए। इसी बीच रूस ने एक बार असद के पक्ष में बमबारी की, पर उसे जल्द ही पता चल गया कि अब असद सत्ता नहीं संभाल पाएंगे। असद अकेले पड़ते गए। उनकी सेना में फूट पड़ गई, आला सैन्य अधिकारियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इससे असद का जमीनी आधार खिसकता गया, अंततः राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और असद को जान बचाकर भागना पड़ा।

ध्यान रहे, बशर अल असद के पिता सैन्य कमांडर और रक्षा मंत्री हाफिज अल असद ने भी सन् 1970 में तख्तापलट से ही शासन पाया था। तानाशाह हाफिज अल असद की मौत 2000 में हुई और उसके बाद से उनके दूसरे बेटे बशर अल असद गद्दी संभाल रहे थे। सीरिया में 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद तानाशाही का अंत हुआ है और सीरियाई लोग देश में और बाहर भी बहुत खुशी मना रहे हैं।

असद को शिया समुदाय के करीब माना जाता है, जबकि अभी जो विद्रोही सत्ता में आए हैं, वे सुन्नी हैं। यहां जोखिम है, जो समूह सत्ता में आया है, वह उग्रपंथी है, उसका इस्लामी एजेंडा स्पष्ट है। कहीं वहां भी अफगानिस्तान जैसा हाल न हो जाए, जहां औरतों को पढ़ने से रोका जा रहा है। उन्हें बुर्के में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मानना चाहिए कि असद का शासन बहुत हद तक सेकुलर व सोशलिस्ट था। वहां औरतों को पढ़ने और आगे बढ़ने दिया जाता था। खुद असद की पत्नी सुन्नी हैं और लंदन में पीढ़ी-लिखी हैं। उनके तख्तापलट के बाद सीरिया में सेकुलरिटी के खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है।

यह भी हो सकता है कि सुन्नी लोग शिया या अलवाइज संप्रदाय पर हमले करने लगें। सीरिया में करीब 10 प्रतिशत ईसाई भी हैं। अब ईसाइयों में भी डर फैल गया है कि अगर सीरिया में कट्टर इस्लामी एजेंडा चला, तो वहां पर भी हमले होंगे। यहां कुर्द भी करीब 10 प्रतिशत हैं, जो तुर्किये के ज्यादा करीब हैं, क्या इन्हें भी निशाना बनाया जाएगा? सीरिया इस समय कई सवालों से घिर गया है और वहां जल्दी स्थायी सरकार बनने की आशा नहीं दिखती। सीरिया अनेक समूहों में बंटा हुआ है, हर समूह अपनी पहचान से किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहता। यही सीरिया की सबसे बड़ी समस्या है। अब सीरिया में एक स्थिर सरकार के न होने से पहला असर लेबनान पर दिखाई देगा। लेबनान में हिजबुल्लाह अभी भी मजबूत है। लेबनान के अस्थिर होने का खतरा है। ईरान शिया देश है, वहां भी इस तख्तापलट का असर दिखाई देगा। अरब में शिया और सुन्नी का विभाजन बढ़ सकता है।

देखने वाली बात है कि अमेरिका ने विद्रोही समूह का समर्थन किया है, क्योंकि अमेरिका अभी ईरान के खिलाफ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान आस-पड़ोस में कमजोर पड़ जाए और इजरायल भी यही चाहता है। आने वाले दिनों में अमेरिका-इजरायल की ओर से यह भी कोशिश तेज हो सकती है कि ईरान में कट्टर मजहबी शासन के खिलाफ विद्रोह हो जाए।

पश्चिम एशिया में केवल देश ही आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न समूहों के बीच लड़ाई जारी है। जमीनी स्थिति बहुत जटिल है। फिलहाल भारत का हित इसी में है कि सीरिया में ज्यादा समय तक हिंसा, अस्थिरता न चले। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सुन्नी बहुल हैं, अगर सीरिया में कट्टर सरकार बनी, तो दक्षिण एशिया में भी उग्रता या हिंसा में इजाफा होगा। सुन्नी आतंकवाद ज्यादा बड़ी चुनौती है। एशिया या दक्षिण एशिया में अगर कहीं भी हिंसक इस्लामी एजेंडा चलता है, तो भारत के लिए ही नहीं, सऊदी अरब जैसे अपेक्षाकृत उदारवादी इस्लामी देशों के लिए भी खतरा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

किसी आपदा के समय ग्राहक सेवा से मुंह न मोड़े उद्योग

दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

नवंबर के अंत में तमिलनाडु में आए चक्रवात फेंगल ने 14 जिलों में व्यापक तबाही मचाई। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश हुई और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे तटीय और अंदरूनी क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए, हजारों एकड़ में खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं, सैकड़ों बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर, सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।

तूफान थमने के बाद नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने तत्काल राहत के लिए 2,000 करोड़ रुपये और आपदा प्रबंधन के लिए 2,500 करोड़ रुपये की मांग की है। नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय टीम ने रविवार को दौरा शुरू किया है। अब केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा। राज्य केंद्र पर अपर्याप्त धन मुहैया कराने का आरोप लगाएगा और केंद्र का आरोप रहेगा कि राज्य सरकार धन लेकर भी केंद्र सरकार को कोई बेव नहीं देती। सच्चाई कहीं न कहीं दोनों आरोपों के बीच है। वैसे, अंततः राज्य सरकार ही सबसे अधिक प्रभावित होगी, क्योंकि यह लोगों के करीब है। राज्य सरकार राहत कार्य पूरे करेगी, उससे पहले ही 10 दिसंबर के आसपास फिर तूफान की आशंका है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में तीसरे तूफान की भविष्यवाणी है।

यह खास तौर पर तब और दुखद है, जब आम लोग किसी आपदा के समय भी बुनियादी मदद या निर्धारित सेवा पाने से भी वंचित रह जाते हैं।

ध्यान देने की बात है, अब शहरी इलाकों में लोगों की समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन को लोगों की तकलीफें कम करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। शहर का बिजली विभाग, नगरपालिका अधिकारी व अन्य नागरिक एजेंसियां तुरंत आपातकालीन सहायता लाइन स्थापित करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि समाधान तुरंत निकाला जाए। ज्यादातर लोग सरकार पर निर्भर हैं और निजी कंपनियों से सुविधाएं खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते। सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि लोगों को परेशानी न हो, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है।

कई लोग जब 1 दिसंबर को चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि हवाई पट्टियों को पानी भरने के कारण बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को पहले सूचित नहीं किया। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। कोई ट्रेन से गया, तो ट्रेन स्टेशन से पहले ही रुक गई। कोई बस से गया, तो बस बीच रास्ते में खराब हो गई। कई लोगों को स्वयं सफर कर रहे सैन्य अधिकारियों ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंचाया।

माफी मांगने की बात तो दूर, एयरलाइन अपने कुछ यात्रियों को नए टिकट बुक करने के लिए कह रही थी। मुआवजे या टिकट राशि लौटाने की चर्चा भी नहीं थी। जिन यात्रियों ने चेन्नई में ही रुकने का फैसला किया, उनसे टैक्सी चालक कम से कम 10 गुना अधिक भाड़ा ले रहे थे। कई होटलों में कमरे महंगे हो गए। ऐसा लग रहा था, मानो सब आपदा के इंतजार में थे, ताकि असहाय लोगों से एक-एक रुपया निचोड़ सकें। जो लोग घर पर रहे, उन्हें भी बिजली कटौती और इंटरनेट ठप होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह शिकायतें सुनने की सेवा ही नदारद हो गई।

साल 1991 में अर्थव्यवस्था के मुक्त होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि सरकार केवल जरूरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी और अधिकांश सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ देगी। परिवहन क्षेत्र, विशेष रूप से विमानन को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाना गया, जहां सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए थी। यह उम्मीद की गई थी कि सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए मजबूत नियामक ढांचा तैयार करेगी। उम्मीद से दूर नियामक संस्थाएं शायद ही गलत व्यापार पर लगाम लगाने में कामयाब रही हैं। कुछ निजी कंपनियां न केवल अपना एकाधिकार बनाने लगी हैं, बल्कि प्रतिस्पर्द्धा को खत्म करने के लिए आक्रामक व्यवहार करने लगी हैं।

चूंकि अधिकांश निजी कंपनियों के लिए मुनाफा ही मुख्य मकसद है, इसलिए सेवाएं अक्सर प्रभावित रहती हैं। यह खास तौर पर तब और दुखद है, जब लोग किसी आपदा के समय भी बुनियादी मदद पाने से वंचित रह जाते हैं। सरकारों और नियामक संस्थाओं को अच्छी सेवा के पक्ष में सख्ती बरतने से जरा भी हिचकना नहीं चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

धारणा से मुक्त कर्म

कर्म का अर्थ है करना, गतिशील होना। लेकिन जब आप कोई धारणा लेकर चलते हैं, तो केवल एक मानसिक कल्पना चलती रहती है, कर्म से जुड़ी हुई एक विचार प्रक्रिया चलती रहती है। यदि धारणा न हो, तो क्या होगा? आप जो हैं, वही रहेंगे। आप कंजूस हैं, निष्ठुर हैं, मूर्ख या विवेकहीन हैं। अगर आप इन सबके साथ ठहर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए कि क्या होता है। जब मैं अपनी कृपणता को पहचान लेता हूं, केवल शाब्दिक या औपचारिक रूप से ही नहीं, बल्कि सच में जब मुझे यह एहसास हो जाता है कि मैं कृपण हूं, स्नेहहीन हूं, तब 'जो है' उसके प्रत्यक्ष दर्शन में क्या प्रेम नहीं समाया होता? क्या मैं तत्क्षण उदार नहीं हो जाता?

यदि मैं स्वच्छ होने की आवश्यकता महसूस करता हूं, तो यह सरल सी बात है कि मैं जाऊंगा और हाथ-मुंह धो लूंगा। लेकिन मुझे साफ-सुथरा रहना चाहिए, यह यदि एक आदर्श हो, तब क्या होता है? तब स्वच्छता या तो स्थगित कर दी जाती है, या वह एक सतही मामला हो जाता है। धारणा पर, विचार पर आधारित कर्म बड़ा सतही होता है, वह वास्तविक कर्म होता ही नहीं, यह महज एक कल्पना है, जो सतत बनी रहने वाली विचार-प्रक्रिया है। वह कर्म, जो मनुष्य के रूप में हमारा कायापलट कर दे, हममें नवजीवन का संचार करे, हमें पूरी तरह से बदल दे, हमें मुक्त कर दे, धारणा पर आधारित नहीं होता। ऐसा कर्म पुरस्कार और दंड के क्रम से अप्रभावित रहता है। यह समय से परे होता है, क्योंकि मन की, जो कि समय की प्रक्रिया है; जो आकलन, विभाजन, अलगाव की प्रक्रिया है, ऐसे कर्म में कोई भूमिका नहीं होती।

आप में से अधिकांश लोग प्रश्न करते हैं और 'हां' या 'नहीं' में किसी उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। 'आपका इससे क्या आशय है?' ऐसा कोई प्रश्न आप पूछ लें, आराम से बैठ जाएं और मैं समझाता रहूं। यह सब तो बहुत आसान है, लेकिन उस उत्तर को खुद अपने लिए खोजना, उस समस्या का गहराई से और बिना किसी तोड़-मरोड़ के अन्वेषण करना कि वह समस्या रह ही न जाए, कहीं अधिक दुष्कर है। यह तभी संभव है, जब समस्या का सामना करते वक्त मन वास्तव में शांत हो।

वह कर्म, जो मनुष्य के रूप में हमारा कायापलट कर दे, हममें नवजीवन का संचार करे, हमें मुक्त कर दे, धारणा पर आधारित नहीं होता। वह पुरस्कार और दंड के क्रम से अप्रभावित रहता है।

अगर उस समस्या से आप प्यार करते हैं, तो यह उतनी ही सुंदर है, जितना कि सूर्यास्त। यदि उस समस्या के प्रति आपका विरोध भाव है, तो उसे आप कभी समझ नहीं पाएंगे। हममें से अधिकतर व्यक्ति विरोधग्रस्त होते हैं, क्योंकि हम परिणाम से भयभीत रहते हैं। हम इस एहसास से डरे रहते हैं कि यदि हम इसमें आगे बढ़े, तो न जाने क्या होगा; अतः हम समस्या के महत्व को, उसकी व्याप्ति को खो बैठते हैं।

जे कृष्णमूर्ति

बेंजामिन नेतन्याहू | इजरायली प्रधानमंत्री

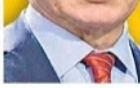

मध्य-पूर्व के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। असद शासन का पतन महान अवसरों, मगर साथ ही बड़े खतरों से भी भरा हुआ है। हम सीरिया के उन सभी लोगों के लिए अमन का हाथ बढ़ाते हैं, जो इजरायल के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं।

पश्चिम ने उनके साथ बड़ा धोखा किया

आज अफगानिस्तान की महिलाओं को यदि पाषाण युग में जीने को विवश होना पड़ रहा है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा अमेरिका, पश्चिमी देश व नाटो संगठन जिम्मेदार हैं। अगस्त 2021 में अमेरिका और नाटो फौजों के अफगानिस्तान से निकलने के बाद वहां की तत्कालीन गनी सरकार भाग खड़ी हुई थी और कायुल में फिर से तालिबान काबिज हो गए। तालिबान वहां कुछ इस तरह से विजेता बनकर उभरे, मानो उन्होंने वहां की अशरफ गनी सरकार और समूचे नाटो गुट से यह युद्ध जीता हो। किसी ने तालिबान का कोई विरोध नहीं किया। आज वहां भुखमरी, बीमारी, लाचारी, अशिक्षा का साम्राज्य है। देश की आधी आबादी, यानी औरतों का जीवन नारकीय बन गया है। न बच्चियां कॉलेज जा सकती हैं, न ही स्कूल। न वे बच्चों को पढ़ा सकती हैं और न ही किसी तरह की नौकरी कर सकती हैं। उनके बाजार जाने और अकेले घूमने-फिरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी मंगलवार को नया तालिबानी फरमान आया है कि अब महिलाएं दाई या नर्स के प्रशिक्षण भी नहीं ले सकतीं। एक यही क्षेत्र था, जिस पर तालिबान ने अब तक प्रतिबंध नहीं लगाया था। औरतों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि पुरुष चिकित्सकों को मर्द अभिभावक की गैर-मौजूदगी में महिलाओं के इलाज की अनुमति पहले ही नहीं है।

अफगानिस्तान में लगभग दस सार्वजनिक और 150 से अधिक निजी स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो 18 विषयों में दो वर्षीय डिप्लोमा प्रदान करते हैं। इनमें दाई से लेकर एनेस्थीसिया, फार्मेसी और दंत चिकित्सा तक शामिल हैं, जिनमें कुल 35,000 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अब इन सबके लिए प्रशिक्षण ले पाना नामुमकिन कर दिया गया है। इसका बुरा असर अगले कुछ वर्षों में देखने को मिलेगा, जब प्रसूति केंद्रों में महिला कामगार नहीं मिलेंगी? तब यह काम तालिबान किनसे कराएगा?

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

अफगानी महिलाएं

सबसे बड़ा दोषी अमेरिका

ओसामा बिन लादेन को खत्म करने की हड़बड़ी में जब अमेरिका अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा था और उसकी उस कार्रवाई में बेगुनाह अफगानी मारे जा रहे थे, तब उसने वहां के लोगों से वादा किया था कि वह दहशतगर्दों का सफाया करके उन्हें एक जम्हूरी मुल्क सौंपेगा, ताकि वे अपना भविष्य खुद तय कर सकें। मगर तालिबान से गुपचुप समझौता करके उसने अफगानिस्तान की आधी आबादी का भविष्य गिरवी रख दिया। अफगानी महिलाएं उसके धोखे का शिकार हुई हैं।

राकिया खानम, टिप्पणीकार

इस्लामी देशों ने कौन-सा इंसाफ किया

तालिबान की बर्बरता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पहले उसने महिलाओं की नौकरियों पर पाबंदी लगाई, उनके अकेले बाहर निकलने पर रोक लगाई, फिर उसने सभी ब्यूटी पार्लरों को बंद कराया। लड़कियों से शिक्षा के अधिकार छीन लिए और अब नर्सिंग, यानी मानव सेवा के उनके कार्यों पर भी पाबंदी लगा दी है। निस्संदेह, संयुक्त राष्ट्र और समूचा विश्व अफगानी औरतों का गुनहगार है। मगर सबसे ज्यादा गुनहगार अगर कोई है, तो वह इस्लामी दुनिया ही है। आखिर इस्लाम के नाम पर ही तालिबान यह सब जुल्म कर रहा है। फिर भी कोई इस्लामी मुल्क आगे बढ़कर तालिबान को लल्लकार नहीं रहा। क्यों? ईरान में जिस बड़े पैमाने पर औरतों का दमन हो रहा है, दुनिया उसकी भी मूक तमाशाई है। इसलिए यह बात तो अब अफगानिस्तान के लोगों, खासकर वहां की महिलाओं के आगे साफ हो जाना चाहिए कि कोई और उनकी लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा। उन्हें अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी।

इस्लाम के आलिम कहते हैं कि उनके मजहब में औरतों को पूरा-पूरा हक दिया गया है। अगर ऐसा है, तो अफगानी बेटियों से तालीम का हक क्यों छीना जा रहा है? अपने पांव पर खड़े होने की उनकी इच्छाओं का दमन क्यों किया जा रहा है? विडंबना यह है कि अरब मुल्कों में औरतों के लिए खिड़कियां खोली जा रही हैं। दशकों से उन पर आयद पाबंदियों में आहिस्ता-आहिस्ता ढील दी जा रही है। कार चलाने, स्टेडियम में बैठकर मैच का लुत्फ उठाने, वहां तक कि खेलों में भाग लेने जैसी सहूलियतें उनके लिए बहाल की जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान इस्लाम की एक अलग इबारत लिख रहे हैं?

महात्मा गांधी बराबर कहा करते थे कि किसी भी धर्म या समाज में टिकाऊ सुधार तभी होता है, जब खुद उसके भीतर के लोग इसकी पहल करते हैं। पश्चिम ने तो अपनी धमक दिखाने के लिए इराक और अफगानिस्तान को अपना शिकार बनाया था। उसकी मंशा वहां सामाजिक सुधार की कभी थी ही नहीं। इसलिए इस्लाम के खैरख्वाहों को यह समझना होगा कि जब तक तालिबान और आईएसआईएस जैसी जमातें उनमें प्रभावी रहेंगी, तब तक दुनिया का नजरिया उनके प्रति बदलने वाला नहीं है। इस्लामोफोबिया को खाद-पानी पश्चिमी मीडिया या गैर-इस्लामी देश नहीं, बल्कि खुद उनके धर्म के कट्टरपंथी मुहैया करा रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ तरक्की-पसंद मुसलमानों को आगे आना होगा और अपने मजहब में व्यापक स्वीकृति हासिल करनी होगी। तभी फर्क आएगा।

राकेश सिंह राणा, टिप्पणीकार

असद का तख्तापलट

ऐतिहासिक परिवर्तन

दमिश्क में विद्रोही शक्तियों के कब्जे के बाद बशर अल असद वहां से भाग गए। यह सीरिया में ऐतिहासिक परिवर्तन है। असद परिवार की सीरिया पर पांच दशक से पकड़ थी और अब वह विरासत समाप्त हो गई है। विद्रोहियों द्वारा दमिश्क पर कब्जे से बशर अल असद का नाटकीय तख्तापलट हुआ। इससे वह युग समाप्त हो गया जिसकी शुरुआत उनके पिता हाफिज़ अल असद से हुई थी। यह असाधारण परिवर्तन सीरिया का रास्ता बदलता है तथा पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। असद परिवार का शासन 1970 में शुरू हुआ था जब उनके पिता हाफिज़ अल असद ने एक सैनिक विद्रोह से सत्ता पर कब्जा कर अस्थिर सीरिया को कठोर नियंत्रण वाले राज्य में बदल दिया था। हाफिज़ के शासनकाल में कठोरता से केन्द्रीकरण किया गया, नस्ली मतभेदों पर लगाम लगाई गई तथा सेना पर कठोर नियंत्रण रखा गया। उनकी 'बांटो और राज करो' वाली रणनीति ने अलावाइट अल्पसंख्यकों को सत्ता में पहुंचा दिया जो ऐतिहासिक रूप से हाशियाकृत समुदाय था। इस सरकार का जीवन संस्थाओं पर कठोर नियंत्रण से संभव हुआ। हाफिज़ के वारिस उनके बेटे असद को विरोधाभासों से भरा राज्य विरासत में मिला जिनको शुरुआत में संभावित सुधारक के रूप में देखा जाता था। लेकिन बशर का राष्ट्रपति कार्यकाल जल्दी ही तानाशाही, आर्थिक दरबारीवाद और विरोधियों के निर्मम दमन में बदल गया। सत्ता पर उनके केन्द्रीकरण से सीरिया के ग्रामीण बहुसंख्यक उनसे दूर हो गए तथा नस्ली तनाव बढ़े। इससे

अशांति के बीज उगने लगे जिनको 2011 में 'अरब वसंत' के दौरान और बढ़ावा मिला।

बशर के शासनकाल में व्यापक गरीबी, भ्रष्टाचार और असमानता ने जनता के बड़े हिस्सों को उनसे दूर किया। आर्थिक कुप्रबंधन के साथ 2000 के दशकांत में पड़े भयानक सूखे ने ग्रामीण आजीविकाओं पर भारी प्रभाव डाला जिससे पहले से ही भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में और पलायन हुआ। इससे जनता में गुस्सा और बढ़ा। 2011 के विद्रोह ने लंबे गृहयुद्ध को जन्म दिया जिसने सीरिया को विभाजित कर दिया। हालांकि, इसके बाद भी बशर एक दशक तक सत्ता पर कब्जा जमाए रखने में सफल हुए पर सैनिक बलों पर सरकार की निर्भरता ने विद्रोहों के दमन के बावजूद अनेक लोगों को अलग-थलग किया। राज्य युद्ध के दौरान मूलभूत सेवाओं की सुरक्षा करने में विफल रहा जिससे उसकी वैधता प्रभावित हुई। 'हयात तहरीर अल शाम'-एचटीएस गठबंधन ने सरकार की घटती शक्ति का लाभ उठाया। अलकायदा से पहले जुड़ाव के विवादास्पद इतिहास के बावजूद एचटीएस की सैनिक सफलताओं और अबू मुहम्मद अल जोलानी द्वारा अपनी 'छवि परिवर्तन' से विपक्षी शक्तियों को एकजुट कर दमिश्क पर कब्जे की राह आसान बनाई। कई सप्ताह की भयंकर लड़ाई के बाद दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और बशर तथा उनके परिवार को भागना पड़ा। असद सरकार के पतन के सीरिया तथा पूरे पश्चिम एशिया के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। सीरिया का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि असद के मुकाबले कोई स्पष्ट राजनीतिक विकल्प नहीं है। एचटीएस के उभार से असद-पश्चात सीरिया में प्रशासन तथा समावेशन के बारे में चिन्तायें पैदा होती हैं। एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बिना सीरिया के और विखंडन का खतरा बना हुआ है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन से पड़ोसी देशों में अस्थिरता पैदा हो सकती है। विपक्षी समूहों का समर्थन करने वाला तुर्की अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है। असद के लंबे समय से सहयोगी ईरान का प्रभाव घट सकता है, जबकि इज़राइल पूरे घटनाक्रम पर गहरी नजरें रखे है। वास्तव में दशकों से जारी टकराव ने सीरिया की अर्थव्यवस्था को बरबाद कर दिया है, लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है तथा ढांचागत संरचना जर्जर हो गई है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़ कर सहायता व पुनर्वास के माध्यम से सीरियाई जनता के कष्ट दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

भारत की सामुद्रिक विरासत

भारत की समुद्री विरासत पर पुनर्विचार करने से नौसेना की ताकत, व्यापार सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग में प्रगति हो सकती है, जिससे एक मजबूत समुद्री भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है

अनूप शर्मा
(लेखक, डिफेंस स्टाफ कालेज, वेलिंग्टन में कार्यरत हैं)

भारत का समुद्री इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मौर्य और चोल जैसे प्राचीन भारतीय साम्राज्यों के लोग सक्रिय नाविक थे, जिन्होंने व्यापार, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से लंबी और कठिन यात्राएं कीं। मराठा, मराक्कर और यहाँ तक कि मुगलों जैसी विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों और शासकों ने भारतीय जल में यूरोपीय नौसैनिक वर्चस्व के उदय को चुनौती देने की कोशिश की। वर्तमान भारतीय नौसेना का जन्म 1947 में रॉयल इंडियन नेवी से हुआ था, जिसमें पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत कम संपत्ति विभाजित थी। परिणामस्वरूप, भारतीय नौसेना शुरू में तटीय रक्षा और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक तटीय बल थी। भारतीय नौसेना ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान अपनी क्षमता साबित की।

1971 के युद्ध में नौसेना द्वारा निर्णायक और साहसिक कार्रवाइयों ने राष्ट्र को व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के मूक, फिर भी गतिशील और प्रभावी तत्व की क्षमता का एहसास कराया। 2004 की सुनामी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और आपदा राहत अभियान शुरू करते हुए, भारतीय नौसेना ने अपनी परिचालन गति को काफी बढ़ा दिया है।

अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में भारतीय नौसेना की हाल की सफलताओं ने पाकिस्तानियों सहित विभिन्न राष्ट्रीयताओं के नाविकों की रक्षा की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। भारतीय नौसेना के जहाजों ने लेबनान (2006) और यमन (2015) जैसे संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय प्रवासियों और मित्र देशों के नागरिकों को निकाला है।

प्राचीन भारतीय समुद्री संस्कृति जैसा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी उचित स्थिति के लिए प्रयास कर रहा है, हमें ऐतिहासिक और स्वदेशी भारतीय समुद्री रणनीतिक विचारों को पुनर्जीवित करने और उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे धर्मग्रंथ, ग्रंथ और साहित्य समृद्ध भारतीय समुद्री रणनीतिक संस्कृति का संदर्भ देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में उभरी अन्य शक्तियों जैसे सातवाहन, पल्लव, पांड्य, चोल और कई अन्य ने शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी भारतीय सभ्यता की समृद्ध समुद्री परंपराओं को जारी रखा। शिवाजी के समुद्री प्रयासों की भावना से प्रेरित एक नए नौसैनिक ध्वज को अपनाना इस दिशा में एक कदम है जिसे राष्ट्र के सभी समुद्री और नौसैनिक प्रयासों के लोकाचार में शामिल किया जाना चाहिए।

शिवाजी के समुद्री प्रयास: 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मराठा एकमात्र भारतीय शक्ति थे जिन्होंने भारतीय जल में बढ़ते यूरोपीय प्रभाव को सफलतापूर्वक चुनौती दी।

शिवाजी, उनके बेटे संभाजी महाराज और उनके योग्य एडमिरल जैसे मयंक भंडारी, दौलत खान, सिद्धोजी गूजर और महान कान्होजी आंग्रे ने 5000 से अधिक कर्मियों वाली एक मजबूत नौसेना का गठन किया और उसे बनाए रखा, जिसमें 300 से अधिक जहाज शामिल थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने स्वीकार किया कि नौसेना और नौसैनिक ठिकानों के निर्माण से अधिक स्पष्ट रूप से शिवाजी की जन्मजात राजनेता के रूप में प्रतिभा को साबित करने वाला कुछ भी नहीं है।

> **अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में भारतीय नौसेना की हाल की सफलताओं ने पाकिस्तानियों सहित विभिन्न राष्ट्रीयताओं के नाविकों की रक्षा की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। भारतीय नौसेना के जहाजों ने लेबनान (2006) और यमन (2015) जैसे संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय प्रवासियों और मित्र देशों के नागरिकों को निकाला है।**

मराठा नौसैनिक कौशल को 1699 के बाद से मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे के अधीन और मजबूत किया गया। उन्होंने रत्नागिरी के विजयदुर्ग में अपने अड्डे से पश्चिमी तट पर ब्रिटिश समुद्री शक्ति को प्रभावी ढंग से चुनौती दी।

गहरे ड्राफ्ट वाले ब्रिटिश जहाजों पर उथले पानी के जहाजों से हमला करने, उथले प्राकृतिक बंदरगाह और किले की शरण का उपयोग करके भारी तोपों के साथ हमला करने की उनकी रणनीति आधुनिक नौसेनाओं द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट समुद्री इनकार और तटीय युद्ध संचालन के समान थी। मराठा नौसैनिक वर्चस्व ऐसा था कि 1772 में मुंबई के कोलाबा द्वीप पर एक संयुक्त एंग्लो-पुर्तगाली हमला भी मराठों को खदेड़ने में विफल रहा। चोलों की रणनीतिक समुद्री संस्कृति चोल की नौसैनिक शक्ति का सबसे पहला उल्लेख पहली शताब्दी ईस्वी के रोमन अभिलेखों में मिलता है, जो कावेरीपट्टनम में एक समृद्ध बंदरगाह की उपस्थिति और राजा के बेड़े द्वारा व्यापारी जहाजों को बंदरगाह तक ले जाने पर प्रकाश डालता है।

एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस में कावेरीपट्टनम से प्रशांत महासागर में द्वीपों तक प्रारंभिक चोल जहाज %कोलांडिया% की यात्रा का उल्लेख है। चोलों की समुद्री शक्ति 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर पहुंच गई, जिसके दौरान चोलों ने ब्लू वाटर क्षमताओं के साथ एक मजबूत नौसेना विकसित की और चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत व्यापार संबंध स्थापित किए। चोल साम्राज्य के नाविकों के पास असाधारण नौवहन कौशल और समुद्र, मानसून, हवाओं और धाराओं की समझ थी। वे नेविगेशन के लिए 32-बिंदु अरब-तमिल पवन कम्पास और उत्तरी गोलार्ध में 56 सितारों के उपयोग से परिचित थे। पतवार और चुंबकीय कम्पास की कमी के बावजूद, चोल नाविक भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच की दूरी बारह से पंद्रह दिनों में तय कर सकते थे, जो उनकी ब्लू वाटर क्षमता का संकेत है। चोलों के समुद्री प्रयास समकालीन भारतीय समुद्री रणनीति के हितधारकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारतीय समुद्री दृष्टिकोण जो 'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) में विकसित हुआ है, भारत की समुद्री विरासत से प्रेरणा ले सकता है। अदन की खाड़ी में एंटी-पायरेसी मिशन, एचएडीआर मिशन, सागरमाला और पोर्ट लेड डेवलपमेंट, सागर, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया आदि जैसी पहलों में चोल की समुद्री प्रथाओं के साथ समानताएं हैं।

खेलों की मेजबानी का मिश्रित मॉडल

> **आईसीसी आयोजनों की मेजबानी के लिए भारत के प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को पीसीबी द्वारा स्वीकार किए जाने को मंजूरी दी गई है।**

केएस तोमर
(लेखक, राजनीतिक विश्लेषक हैं)

पाकिस्तान के सरकारी गलियारों से एक व्यावहारिक और अभूतपूर्व निर्णय सामने आया है, जिसमें आईसीसी आयोजनों की मेजबानी के लिए भारत के प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को उसके क्रिकेट बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने को मंजूरी दी गई है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण, जिसमें यूएई जैसे तटस्थ स्थानों पर मैच शामिल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक जीवन रेखा है। यह 19 फरवरी से 9 मार्च, 2025 तक निर्धारित प्रतिष्ठित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के मेजबानी अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। अंततः, क्रिकेट ही अंतिम विजेता के रूप में उभरता है।

भारत और पाकिस्तान के लाखों क्रिकेट प्रेमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की सफल मध्यस्थता का जश्न मना रहे हैं। यह संकल्प विभाजन को पाटने के लिए खेलों की शक्ति को रेखांकित करता है। आईसीसी ने पहले पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार करने पर उसके मेजबानी अधिकारों को रद्द करने की चेतावनी दी थी। क्रिकेट के प्रति अपने प्रेम से एकजुट प्रशंसकों का चिरस्थायी जुनून क्षेत्रीय सीमाओं से अप्रभावित रहता है। प्रतिद्वंद्विता और भावनाओं से सराबोर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेल से परे होते हैं और देशभक्ति और जोश का तमाशा बन जाते हैं। समानांतर घटनाक्रम में, जय शाह को आईसीसी का नया प्रमुख चुना गया है, जो वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में एक महत्वपूर्ण क्षण है। शाह के नेतृत्व में आईसीसी के लिए परिवर्तनकारी अवसर हैं, जो दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट निकाय, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष के रूप में उनके विशाल अनुभव का लाभ उठाते हैं। उनका चुनाव महत्वपूर्ण मील के पत्थर के लिए मंच तैयार करता है, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट के आयोजन में।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, यह निर्णय संभावित अलगाव को रोकने के लिए एक सुनियोजित कदम था। भारत की शर्तों को अस्वीकार करने से पाकिस्तान को अपनी मेजबानी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिल पाता, खासकर भारत की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए। हाइब्रिड मॉडल, जो पाकिस्तान और यूएई के बीच मैचों को विभाजित करता है, एक संतुलित समाधान प्रदान करता है। पाकिस्तान भारत की आशंकाओं को दूर करते हुए अपने मेजबानी अधिकार बरकरार रखता है, इस प्रकार प्रतिष्ठा और वित्तीय नुकसान से बचता है। हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करना क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक विश्वसनीय मेजबान बना रहे और अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने का अवसर बनाए रखे। इसके अतिरिक्त, इस समझौते में पीसीबी से वित्तीय आश्वासन शामिल होने की संभावना है, जो किसी भी कथित समझौते की भरपाई करेगा। सफल कार्यान्वयन से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरे के बाद एक विश्वसनीय क्रिकेट हब के रूप में पाकिस्तान की छवि बेहतर हो सकती है।

हाइब्रिड मॉडल सुरक्षा चिंताओं को मेजबानी महत्वाकांक्षाओं के साथ संतुलित करते हुए जीत-जीत का परिणाम प्रदान करता है। जबकि भारत के मैच तटस्थ स्थानों पर होंगे, पाकिस्तान के पास अपनी धरती पर अन्य खेलों की मेजबानी करने का अवसर बना रहेगा। यह व्यवस्था स्थानीय प्रशंसकों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का प्रत्यक्ष अनुभव करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, 2031 तक भारत में होने वाले आयोजनों के लिए पारस्परिकता पर पीसीबी का जोर रणनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है, जो भविष्य के न्यायसंगत समझौतों का मार्ग प्रशस्त करता है।

चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार करना पाकिस्तान के लिए एक भयावह गलती होती। वैश्विक क्रिकेट में भारत के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए, इस तरह के निर्णय से पीसीबी आईसीसी और प्रमुख हितधारकों से अलग हो सकता था। वित्तीय और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान के साथ-साथ प्रशंसकों के मनोबल में कमी और प्रायोजकों के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने स्थायी निशान छोड़े होंगे। दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देकर, पीसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मंच पर अपनी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित की है।

शाह का लक्ष्य क्रिकेट को यूएसए, चीन और अफ्रीका जैसे नए बाजारों में पेश करना, दर्शकों में विविधता लाना और खेल को वास्तव में वैश्विक बनाना है। राजस्व सृजन में उनकी विशेषज्ञता रिकॉर्ड-तोड़ मीडिया सौदों की ओर ले जा सकती है, जिससे समान राजस्व साझाकरण के माध्यम से छोटे बोर्डों को लाभ मिल सकता है। उन्नत तकनीकों और डेटा-संचालित रणनीतियों को एकीकृत करके, शाह आईसीसी टूर्नामेंटों का आधुनिकीकरण कर सकते हैं, युवा दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं और खेल की वैश्विक अपील को बढ़ा सकते हैं।

एक भारतीय के रूप में, शाह पर बीसीसीआई के हितों का पक्ष लेने के आरोप लग सकते हैं। समावेशिता सुनिश्चित करना और सदस्यों की चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण होगा। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट दिग्गजों के प्रभुत्व को छोटे देशों के विकास के साथ संतुलित करना शाह के नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।

जय शाह के नेतृत्व में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्रतिस्पर्धा, नवाचार और प्रशंसक जुड़ाव में मानक स्थापित करने की क्षमता के साथ अपार संभावनाएं हैं। हाइब्रिड मॉडल को अपनाने का पाकिस्तान का व्यावहारिक निर्णय इस यात्रा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए इसकी क्रिकेट महत्वाकांक्षाओं को संरक्षित किया जा सके। साथ में, ये विकास खेल के लिए एक नए युग का संकेत देते हैं, जो क्रिकेट के बैनर तले प्रशंसकों और देशों को एकजुट करते हैं।

आप की बात

संसदीय कार्यवाही

इस शीतकालीन सत्र की शुरुआत काफी हंगामें बाजी से होने के कारण दो-तीन दिन का समय बर्बाद हो गया था। अब चूंकि संसद की कार्यवाही प्रतिदिन निर्बाध रूप से शुरू हो चुकी हैं अत: विश्वास है अब संसद में कई विधेयकों पर विस्तार से चर्चा हो सकेगी। फिर अब तो संसद की कार्यवाही आने वाले छुट्टी के दिनों मे भी जारी रहेगी अत: यह एक अच्छा निर्णय कहा जा सकता है कारण अक्सर देखा गया है कि हुल्हड़ बाज सांसदों द्वारा जब-जब संसद की करवाही बाधित करने का प्रयास किया जाता है तब लगभग पूरा दिन भी कार्यवाही नहीं हो पाती थी एवं इसी कारण काफी नुकसान होता था अत: संसद की कार्यवाही को अब छुट्टी के दिनों मे जारी रखने का निर्णय काफी प्रशंसनीय कहा जा सकता है। विश्वास है कि अब इन छुट्टीके दिनों मे कई विधेयकों पर चर्चा हो सकेगी। अत: यहां पर हम तो यही कहेंगे कि अगर मोदी सरकार के पूर्व के दो कार्य कालों के समय में भी हंगामे के कारण बर्बाद दिनों की भी छुट्टी के दिनों में कार्यवाही जारी रखने का निर्णय उस वक्त हि अगर ले लिया जाता तब उस समय भी बेकार हुए समय का उपयोग कर लिया जाता। खैर देर आयद दुरुस्त आयद। आगे से संसद की कार्यवाही किसी वजह से बाधित हो तो उसकी पूर्ति छुट्टीके दिनों मे कार्यवाही कर पूरी की जाना चाहिए। इसे हम एक सही निर्णय कह सकते हैं।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

छात्र संघ चुनाव बहाली

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ के चुनाव करवाए जाने का निर्णय उचित है। इससे छात्रों को राजनीति का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। मगर यह भी विचारणीय है कि प्रतिभाशाली छात्र चुनावी राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं। और बाहुबल, धनबल, दादागिरी करने वाले छात्र ही चुनावों में अपना गुट बनाकर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। हालांकि बीजेपी की विद्यार्थी छात्र परिषद और कांग्रेस की एन एस एस छात्र चुनावी इकाइयां अपने बेनर तले छात्रों को उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाते हैं। इस प्रकार छात्रों को राजनीति के दांव पेंच और तोर तरीके ज्ञात होंगे। चुनाव के लिए टिकट पाने का भी तरीका इन संगठनों के माध्यम से छात्र सीख जाएंगे। और हमने यह भी देखा है कि जो छात्र राजनीति में सक्रिय और सफल रहते हैं वे छात्र भविष्य में बड़े नेता बने हैं। चुनाव के दरमियान बाहरी अराजक तत्व शिक्षा परिसर में प्रवेश नहीं करने पाएं तथा छात्राओं केलिए भी सीटे रिजर्व रखी जाए। चुनाव ईवीएम से करवायें जाए तथा खर्च की सीमा भी निर्धारित की जाए। और चुनाव लड़ने ,जीतने वाले छात्रों को चुनाव के बाद चुनावी कटुता भुलाकर मिलजुल कर पढ़ाई करना चाहिए। साथ ही विधान सभा में लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में राजनीति शास्त्र में स्नातक होना अनिवार्य किया जाए तो हमारी प्रजातांत्रिक जड़ें मजबूत होंगी।

– **विभुक्ति बुपक्या**, खाचरोद, मप्र

युद्ध समस्या का हल नहीं

वर्तमान दौर में दुनियां के कुछ देशों में युद्ध , चल रहे हैं। और लंबे समय से इन चलने वाले युद्धों में बर्बादी और पतन की अलावा कुछ नजर नहीं आता। बड़ी मुश्किल से विकास के द्वार खुलते हैं। और युद्धनीति से वर्षों तक का विकास अवरूद्ध हो जाता है। विगत समय से देशों के युद्ध में अरबों खरबों से ऊपर धन बर्बादी और चारों और अंधकार ही हासिल हुआ। कहीं जिंदगी शुरू होने से पहले ही काल के गाल में समा गई। हजारों लाखों लोगों की असमय मृत्यु हो गई। क्या यह सब मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली घटनाएं नहीं ? युद्धों से कोई समस्या का हल नहीं। देश के बुद्धिजीवी वर्ग इस नीति को अपनाएंगे चारो और बर्बादी, पतन खोफ भय का मंजर रहेगा। दुनियां के अन्य देशों ने अपना प्रतिनिधित्व निभाकर युद्ध से संबंधित देशों का युद्ध रोकथाम के लिए कारगर रणनीति तैयार करनी चाहिए। बल्कि ठोस कार्रवाई और पटल पर बात रखनी चाहिए। घर में लड़ाई झगडे होते हैं तो छूड़ाया जाता है। क्या अन्य देशों को यह रणनीति नहीं आती ? इतिहास गवाह हैं की प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान परिदृश्य तक युद्ध से बर्बादी, पतन के अलावा क्या हासिल हुआ। ? कुछ भी हो कोई भी समस्या का हल बातचीत , संवाद से होना चाहिए, देशों में समन्वय होना चाहिए ताकि युद्ध नीति को तरूरत ही न महसूस हों।

– **योगेश जोशी**, बड़वाह, मप्र

अत्याचारी का अंत निश्चित

हर अत्याचारी हर नरसंहारी का अंत तो एक न एक दिन होता ही है। मगर उससे पहले अपने अत्याचारों एवं जुल्मों से, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार चुके होते हैं। ऐसा ही एक तानाशाह अब तक जिन्दा है। जिसका नाम है बशर अल असद। जिसने पिछले 24 वर्षों से सीरिया पर जुल्म किया हैं। असद राजवंश एक सीरियाई राजनीतिक परिवार है जिसने 1971 में बाथ पार्टी के तहत हाफ़िज़ अल-असद के सीरिया के राष्ट्रपति बनने के बाद से सीरिया पर शासन किया है। जून 2000 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके बेटे बशर अल-असद ने उनका स्थान लिया। असद और उनके परिवार ने 50 से अधिक वर्षों तक सीरिया पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जब से असद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 2000 में राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से असद की सेना ने 350,000 से अधिक विरोधियों को मार डाला है, अनगिनत लोगों को जेल में डाला है और यातनाएं दी हैं और उनके शासन को चुनौती देने वालों को रोकने के लिए विपक्षी शहरों पर प्रतिबंधित नर्व गैस का इस्तेमाल किया है। अब लग रहा है की इस राजवंश का अंत निकट है।

– **जंग बहादुर सिंह**, जमशेदपुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।